दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

समक्ष

माननीय न्यायमूर्ति श्री पुरूषेंद्र कुमार कौरव

<u>रि.या.(सि.) 3796/2022</u>

इनके बीचः-

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड,
अपने अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा
श्री राहुल सिंह द्वारा से
शाल टावर, तीसरी मंजिल
प्लॉट सं.23 न्यू रोहतक रोड,
नई दिल्ली-110005 .....याचिकाकर्ता

(द्वाराः श्री संजीव सेन, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री सुमित गोयल, सुश्री श्रीपर्णा बसक, सुश्री अंजलि सिंह, सुश्री प्रत्युषा प्रियदर्शिनी और श्री जयंत बजाज, अधिवक्तागण)

और

उप सामान्य प्रबंधक,
उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय
श्री एम.ए. शिनोद
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
एन.बी.सी.सी. कॉम्प्लेक्स, कार्यालय टावर-1,
आठवीं मंजिल, प्लेट बी, ईस्ट किदवई नगर,
नई दिल्ली-110023 .....प्रत्यर्थी सं. 1

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड

अपने अध्यक्ष द्वारा
सेबी भवन, प्लॉट सं. सी-4ए,
"जी" ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा (ई), मुंबई 400051 .....प्रत्यर्थी सं. 2

श्री दीपक गोयल
सुपुत्र मदन लाल गोयल
द पाल्म स्प्रिंग्स, विला सं.-7,
गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर-54
गुड़गांव हरियाणा-122001

इसके अलावा, विला सं.-टी.पी.वी.-जी.-जी.वी.-जी.वी. 07,
द पाल्म स्प्रिंग्स, सेक्टर-54,
वजीराबाद गांव की राजस्व संपदा में स्थित
तहसील एवं जिला गुड़गांव, हरियाणा-122002

इसके अलावा, गोयल इन्वेस्टमेंट्स एंड सिक्योरिटीज,
इकाई सं.-554 और 555 पांचवी मंजिल
टावर-बी-2, स्पेज़ टेक पार्क सोहना रोड, सेक्टर-49
गुड़गांव, हरियाणा-122001 ..... प्रत्यर्थी सं. 3

श्रीमती रुचिका गोयल
पत्नी श्री दीपक गोयल
जीवी 07, द पाल्म स्प्रिंग्स
गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर 54
हरियाणा गुड़गांव-122001

इसके अलावा, विला सं.-टी.पी.वी.-जी.-जी.वी.-जी.वी. 07,
द पाल्म स्प्रिंग्स, सेक्टर-54,
वजीराबाद गांव की राजस्व संपदा में स्थित

तहसील और जिला गुड़गांव, हरियाणा-122002 ..... प्रत्यर्थी सं. 4

(*द्वारा: श्री अरुणाभ चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री आशीष अग्रवाल, सुश्री आस्था कौशल और श्री अनिरुद्ध महादेवन सेठी, सेबी के लिए अधिवक्तागण। श्री गजिंदर कुमार, अधिवक्ता*)

उद्घोषित: 21.07.2023

<u>निर्णय</u>

1. तत्काल याचिका में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इसके पश्चात **'सेबी'**) के पूर्णकालिक सदस्यों द्वारा दिनांक 29.05.2018 और 14.12.2018 को पारित आदेशों की घोषणा की मांग की गई है, जो याचिकाकर्ता बैंक पर लागू नहीं होते हैं और कहा गया है कि वे आदेश याचिकाकर्ता बैंक को वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके पश्चात **'सरफेसी अधिनियम, 2002'**) के प्रावधानों के तहत गिरवी रखी गई संपत्ति को बेचने के लिए आगे बढ़ने से नहीं रोकते हैं, जो कि टीपीवी-जी-जीवी-07, द पाम स्प्रिंग्स, वजीराबाद गाँव, सेक्टर 54, गुड़गांव 122002 (इसके पश्चात **'बंधकित संपत्ति'**) है।

2. याचिकाकर्ता बैंक ने प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 को दिनांक 29.01.2021 और 18.03.2021 के आक्षेपित ई-मेल के अनुसार कोई आगे की कार्रवाई न करने और बंधकित संपत्ति की बिक्री के संबंध में याचिकाकर्ता बैंक को किसी भी तरह से विफल न करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया है। वैकल्पिक रूप से, यह घोषणा करने के

लिए भी निर्देश मांगे गए हैं कि याचिकाकर्ता बैंक का बंधकित संपत्ति पर पहला प्रभार है साथ ही उसे सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार बंधकित संपत्ति की नीलामी करने की अनुमति देने का भी निर्देश दिया गया है।

3. मामले के तथ्यों से पता चलता है कि याचिकाकर्ता बैंक कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक निजी कंपनी है और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के तहत परिभाषित एक बैंकिंग कंपनी है।

4. प्रत्यर्थी सं. 1 प्रत्यर्थी सं. 2-सेबी के उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय का उप महाप्रबंधक है जो भारत में प्रतिभूति और वस्तु बाजार का नियामक निकाय है, जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (इसके पश्चात **'सेबी अधिनियम, 1992'**) के अनुसार स्थापित किया गया है।

5. प्रत्यर्थी सं.3 और 4 यानी, श्री दीपक गोयल और श्रीमती रुचिका गोयल, याचिकाकर्ता बैंक के उधारकर्ता हैं और उन्होंने याचिकाकर्ता बैंक से दिनांक 22.09.2017 को सुविधा समझौते के माध्यम से 6,03,99,231/- रुपए की गृह ऋण सुविधा प्राप्त की थी, जिसमें विचाराधीन संपत्ति को बंधकित रखा गया था। विचाराधीन गृह ऋण याचिकाकर्ता बैंक द्वारा अपनी ग्रीन पार्क शाखा, नई दिल्ली से प्रत्यर्थी सं. 3 और 4 को वितरित किया गया था।

6. 22.09.2017 को प्रत्यर्थी सं. 3 और 4 द्वारा गारंटी विलेख निष्पादित किया गया था और उन्होंने याचिकाकर्ता बैंक के पास बिक्री विलेख दिनांक 22.04.2013 सहित उक्त

बंधकित संपत्ति का मूल शीर्षक दस्तावेज़ जमा करते हुए, याचिकाकर्ता बैंक के पक्ष में संपत्ति के संबंध में सुरक्षा हित बनाया था। याचिकाकर्ता बैंक ने उक्त बंधकित संपत्ति को 17.10.2017 को भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केंद्रीय रजिस्ट्री (इसके पश्चात "सरसाई") के साथ विधिवत पंजीकृत किया था।

7. ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ष 2017 में, सेबी ने एफ.6 कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ जांच शुरू की, जिसमें प्रत्यर्थी सं. 3 और 4 निदेशक थे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से 27.07.2017 और 03.08.2017 दिनांकित ई-मेल प्राप्त करने के बाद जांच शुरू की गई थी।

8. 29.05.2018 को सेबी के पूर्णकालिक सदस्य द्वारा सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 11 (1), 11 (4), 11 ख और 11 घ सह पठित धारा 19 के तहत शक्ति के प्रयोग में एकपक्षीय अंतरिम आदेश पारित किया गया था, जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यस्थ) विनियम, 2008 (इसके पश्चात "विनियम, 2008") के विनियमन 35 के साथ पढ़ा गया था, जिससे निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए थे:

"27. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मैं, सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 11 (1), 11 (4), 11 ख और 11 घ, प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के विनियमन 35 सह पठित धारा 19 के आधार पर मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार (मध्यस्थ) विनियम, 2008, इस एकपक्षीय-विज्ञापन-अंतरिम आदेश के माध्यम से, निम्नलिखित निर्देश जारी करती हूँ:

> *क. एफ.6 फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड, एफ.6 कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, श्री पंकज गोयल, श्री परवीन शर्मा, श्री मीनू गोयल, श्री संजय आनंद, सुश्री कविता आनंद, सुश्री आशा शर्मा, श्री दीपक गोयल और*

सुश्री रुचिका गोयल को प्रतिभूति बाजार में प्रवेश करने से रोक दिया गया है और उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभूतियों की खरीद, बिक्री या अन्यथा लेनदेन करने या किसी भी तरह से प्रतिभूति बाजार से जुड़े रहने पर अगले निर्देश तक प्रतिबंध लगा दिया गया है:

ख. उपरोक्त इकाईयाँ और व्यक्ति अगले निर्देशों तक प्रतिभूति बाजार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह की कोई भी गतिविधि करना प्रविरत कर देंगे।

ग. उपरोक्त इकाईयों और व्यक्तियों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपनी सभी संपत्तियों, चाहे वह चल हो या अचल, या ऐसी किसी भी संपत्ति में किसी भी ब्याज या निवेश या शुल्क की पूरी सूची प्रदान करें, जिसमें उनके सभी बैंक खातों, डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड निवेशों का विवरण शामिल हो, लेकिन इन निर्देशों की प्राप्ति की तिथि से 5 कार्य दिवसों के बाद नहीं।

घ. उपरोक्त इकाईयों और व्यक्तियों को निर्देश दिया जाता है कि वे सेबी की पूर्व अनुमति के अलावा किसी भी संपत्ति, चाहे वह चल हो या अचल, या बैंक खातों में पड़े धन को छोड़कर ऐसी किसी भी संपत्ति में कोई ब्याज या निवेश या शुल्क का निपटान या अंतरण न करें।

ङ. इस संबंध में अगले निर्देशों तक, इन हकदारों की परिसंपत्तियों का उपयोग केवल संबंधित स्टॉक एक्सचेंज(ओं) की देखरेख में ग्राहकों/निवेशकों को धन के भुगतान और/या प्रतिभूतियों के वितरण के उद्देश्य से किया जाएगा।

च. निक्षेपधारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि संबंधित स्टॉक एक्सचेंज से पुष्टि के बाद उप-पैरा (ङ) में उल्लिखित उद्देश्य को छोड़कर उपरोक्त हकदारों और व्यक्तियों के संयुक्त रूप से या अलग-अलग रखे गए डीमैट खातों में कोई डेबिट नहीं किया जाता है।

छ. पंजीयक और अंतरण अभिकर्ताओं को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि भौतिक रूप में प्रतिभूतियां (म्यूचुअल फंड इकाइयों सहित), जो संयुक्त रूप से या अलग-अलग रूप से उपरोक्त हकदारों और व्यक्तियों द्वारा आयोजित की जाती हैं, इस संबंध में संबंधित स्टॉक एक्सचेंज से पुष्टि के बाद उप-पैरा (ङ) में उल्लिखित उद्देश्य के अलावा हस्तांतरित/छुड़ाए नहीं जाते हैं।

ज. बैंकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि एफ6 फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड, एफ6 कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, श्री पंकज गोयल और श्री मीनू गोयल द्वारा संयुक्त रूप से या अलग-अलग रखे गए बैंक खातों में कोई डेबिट नहीं किया जाए, सिवाय इसके कि संबंधित स्टॉक एक्सचेंज(ओं) की लिखित पुष्टि के तहत ग्राहकों/निवेशकों को धन का भुगतान किया जाए।

झ. उपरोक्त निर्देश उपरोक्त इकाईयों/व्यक्तियों के संबंध में शुरू की जा सकने वाली कोई अन्य कार्रवाई करने के लिए सेबी के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना हैं।"

9. अनिवार्य रूप से, दिनांकित 29.05.2018 के आदेश में दिए गए निर्देशों का प्रभाव प्रत्यर्थी सं. 3 और 4 सहित नोटिसी को प्रतिभूति बाजार तक पहुंचने से प्रतिबंधित करना था और उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभूतियों में खरीदने/बेचने या अन्यथा लेनदेन करने या प्रतिभूति बाजार से जुड़े होने से प्रतिबंधित करना था।

10. यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि नोटिसी को सेबी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी चल या अचल संपत्ति, या किसी भी ब्याज या निवेश या बैंक खातों में पड़े धन को छोड़कर ऐसी किसी भी संपत्ति में परिवर्तन नहीं करने का निर्देश दिया गया था।

11. यह देखा गया है कि आगे के निरीक्षण आदि के आधार पर, सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 11 (4), 11 ख और 11 घ के तहत प्रत्यर्थी सं. 2 के एक पूर्णकालिक सदस्य द्वारा 14.12.2018 को एक पुष्टिकरण आदेश पारित किया गया था, जिसे विनियम, 2008 सह पठित विनियमन 35, जिसमें अगले आदेश तक प्रत्यर्थी सं. 3 और 4 सहित 10 व्यक्तियों के खिलाफ 29.05.2018 के एकपक्षीय अंतरिम आदेश की पुष्टि की गई थी।

12. इस बीच, याचिकाकर्ता बैंक ने ध्यान दिया कि प्रत्यर्थी सं. 3 और 4 ने याचिकाकर्ता बैंक से लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान में चूक की और तदनुसार, विचाराधीन खाते को याचिकाकर्ता बैंक द्वारा 30.09.2019 को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

13. इसके बाद याचिकाकर्ता बैंक ने सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत दिनांक 22.11.2019 को एक मांग नोटिस जारी किया जिसमें प्रत्यर्थी सं.3 और 4 और प्रत्याभूति-दाता को बकाया राशि चुकाने के लिए कहा गया। प्रत्यर्थी सं. 3 और 4 बकाया राशि चुकाने में विफल रहे जो 22.11.2019 तक 6,08,72,618/- रुपए थी।

14. इसलिए, याचिकाकर्ता बैंक ने सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) के तहत 16.03.2020 को बंधकित रखी गई संपत्ति का प्रतीकात्मक कब्जा अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद याचिकाकर्ता बैंक ने सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 14 के तहत संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष भौतिक कब्जे को लेने के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसकी अनुमति 15.09.2020 को दी गई थी। तदनुसार, बंधकित संपत्ति का

भौतिक कब्जा ले लिया गया और 14.10.2020 दिनांकित एक कब्जे का नोटिस जारी किया गया, जिसमें प्रत्यर्थी सं.3 और 4 और आम जनता कोप सूचित किया गया कि याचिकाकर्ता बैंक ने सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बंधकित संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया था।

15. याचिकाकर्ता बैंक द्वारा दिनांकित 14.10.2020 का एक पूर्व-बिक्री नोटिस भी जारी किया गया था, जिसमें प्रत्यर्थी सं. 3 और 4 से बकाया राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया गया था, जिसमें विफल रहने पर याचिकाकर्ता बैंक को बकाया राशि का एहसास करने के लिए बंधकित संपत्ति को बेचने के लिए बाध्य किया जाएगा। इसके बाद याचिकाकर्ता बैंक ने 16.10.2020 को दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित एक नोटिस जारी कर जनता को आगाह किया कि वे संबंधित संपत्ति के साथ सौदा न करें और उसी के साथ काम करना याचिकाकर्ता बैंक के प्रभार के अधीन होगा। 19.12.2020 को याचिकाकर्ता बैंक ने 8,67,20,000/- रुपए की आरक्षित कीमत पर बंधकित संपत्ति की नीलामी बिक्री के लिए नोटिस प्रकाशित किया। उसी दिन यानी 19.12.2020 को याचिकाकर्ता बैंक ने प्रत्यर्थी सं. 3 और 4 और प्रत्याभूति-दाता को 15 दिनों के भीतर संपत्ति में चल वस्तुओं को खाली करने के लिए एक अवकाश नोटिस के साथ एक बिक्री नोटिस भेजा।

16. इसके बाद, 29.01.2021 को याचिकाकर्ता बैंक को प्रत्यर्थी सं. 1 से एक आक्षेपित ई-मेल प्राप्त हुआ, याचिकाकर्ता बैंक को सूचित करते हुए कि सेबी के पूर्णकालिक सदस्य द्वारा पारित आदेश (इसके पश्चात "कथित आदेश" कहा गया है) दिनांकित 29.05.2018

और 14.12.2018 के तहत, प्रत्यर्थी सं. 3 और 4 को प्रत्यर्थी सं. 2 की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी संपत्ति का निपटान या अन्यसंक्रांत करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। याचिकाकर्ता बैंक को तदनुसार सेबी की ओर से सेबी के पूर्णकालिक सदस्य द्वारा 10 इकाईयों के खिलाफ पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें प्रत्यर्थी सं. 3 और 4 शामिल थे।

17. 04.02.2021 को, याचिकाकर्ता बैंक ने 29.01.2021 के ई-मेल का जवाब दिया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया था कि याचिकाकर्ता बैंक, एक सुरक्षित लेनदार होने के नाते, 19.12.2020 को सार्वजनिक नीलामी के लिए एक नोटिस जारी किया था और चूंकि उधारकर्ताओं ने याचिकाकर्ता बैंक के पक्ष में उक्त संपत्ति के संबंध में बंधकित किया था, इसलिए, दिनांक 29.01.2021 का संचार याचिकाकर्ता बैंक को आगे बढ़ने से प्रतिबंधित नहीं करेगा।

18. दिनांक 04.02.2021 के उत्तर में पैराग्राफ सं. 6 से 8 को निम्नानुसार पढ़ा जाए:

> *"6. सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसरण में बैंक ने एक सुरक्षित लेनदार होने के नाते 19 दिसंबर 2020 को सार्वजनिक नीलामी बिक्री के लिए एक नोटिस जारी किया था और उक्त संपत्ति की नीलामी बिक्री विला सं. टीपीवी-जी-जीवी-ओ?, द पाम स्प्रिंग्स, वजीराबाद गांव, सेक्टर 54, गुड़गांव 122002, 02 फरवरी 2021 को 86720000/- रुपए के आरक्षित मूल्य पर आयोजित होने वाली है।*
>
> *7. बैंक का कहना है कि उधारकर्ताओं ने गृह ऋण सुविधा के तहत देय बकाया के उचित पुनर्भुगतान को सुरक्षित करने के लिए बैंक के पक्ष में उक्त संपत्ति के संबंध में एक बंधक बनाया था। इसलिए बैंक कहता है कि*

उक्त संपत्ति के संबंध में उसका पहला और अनन्य प्रभार विला सं. टीपीवी-जी-जीवी-07, द पाम स्प्रिंग्स, गांव वजीराबाद, सेक्टर 54, गुड़गांव 122002 है और इसलिए बैंक एक वैध चार्जधारक/बंधकदार होने के नाते सर्वोपरि प्रभार रखता है और अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए उक्त संपत्ति में बनाए गए सुरक्षा हित के प्रवर्तन के अपने वैधानिक अधिकार का प्रयोग करने का हकदार है।

8. उपरोक्त परिस्थितियों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड 29 मई 2018 के आदेश में नामित 10 संस्थाओं में शामिल नहीं है, बैंक डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित अपने प्रतिभूति ब्याज को लागू करने का हकदार है और विला सं. टी.पी.वी.जी-जी.वी-7 पाम स्प्रिंग्स, गाँव वजीराबाद, सेक्टर 54, गुड़गांव 122002 की नीलामी के साथ आगे बढ़ सकता है। हालांकि, बकाया राशि के समायोजन के बाद बैंक नीलामी बिक्री से प्राप्त अधिशेष (यदि कोई हो) के बारे में आगे के निर्देश के लिए आपके कार्यालय को सूचित करेगा। हमारा मानना है और हमारी समझ के अनुसार, बैंक सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ सकता है और पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। कृपया हमारी समझ की पुष्टि करें।"

19. 18.03.2021 को, प्रत्यर्थी सं.1 ने याचिकाकर्ता बैंक के दिनांक 04.02.2021 के ई-मेल का जवाब दिया और अन्य बातों के साथ-साथ कहा कि दिनांकित 29.05.2018 और 14.12.2018 के आदेश सर्वबंधी आदेशों के चरित्र को शामिल करते हैं और जांच/फोरेंसिक ऑडिट के पूरा होने तक दलाल या उसकी आस्ति/देनदारियों से निपटने वाले सभी घटकों को बाध्य करते हैं और उसके पश्चात, याचिकाकर्ता बैंक ने तत्काल रिट याचिका दायर की है। हालाँकि, तत्काल रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 11(4), 11ख और 11घ के तहत सेबी द्वारा दिनांक 09.06.2022 का अंतिम आदेश पारित किया गया है।

20. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजीव सेन ने श्री सुमित गोयल, सुश्री श्रीपर्णा बसाक, सुश्री अंजलि सिंह और श्री जयंत बजाज की सहायता से प्रस्तुत किया कि **सुरक्षित ऋण की वसूली के लिए एक सुरक्षित ऋणदाता के अधिकार को अन्य सभी ऋणों पर प्राथमिकता दी जाती है।** ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 (इसके पश्चात **"आरडीबी अधिनियम, 1993"**) की धारा 31ख सह पठित सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 26ङ के गैर-अस्थाई खंड पर विशिष्ट निर्भरता रखने के बाद, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया था कि धारा 26 ङ सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 28क पर प्रबल होगी।

21. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 35 और 37 के आधार पर सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधान सेबी अधिनियम, 1992 में निहित असंगत प्रावधानों को निरस्त करेंगे।

22. इस न्यायालय को सरफेसी अधिनियम, 2002 के अध्याय IV-ए के माध्यम से, जिसे 24.01.2020 से अंतःस्थापित किया गया है, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 26ङ के संदर्भ में सरकारी बकाया सहित अन्य सभी बकाया राशि पर सुरक्षित लेनदार को प्राथमिकता दी गई है और इस प्राथमिकता के लिए, प्रतिभूति ब्याज का अनिवार्य पंजीकरण आवश्यक है।

23. आगे यह तर्क दिया जाता है कि आर.डी.बी. अधिनियम, 1993 में धारा 31ख को शामिल करने के आलोक में, सुरक्षित लेनदारों की प्राथमिकता को भी 01.09.2016 से प्रभावी रूप से जोड़ा गया है, और इसका मतलब यह होगा कि विधायिका का इरादा सेबी

अधिनियम,1992 के तहत प्रावधान होने के बावजूद, सुरक्षित लेनदार को प्राथमिकता देना था।

24. यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 11(1), 11(4), 11ख और 11घ के तहत पारित आदेश सर्वबंधी नहीं हैं और सेबी के आक्षेपित निर्देश सरफेसी अधिनियम, 2002 के मूल इरादे के विपरीत हैं।

25. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने सरफेसी अधिनियम, 2002, सेबी अधिनियम, 1992 और आरडीबी अधिनियम, 1993 के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से इस न्यायालय का रुख किया। उसने ***बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम गुजरात राज्य और अन्य, कालुपुर वाणिज्यिक सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम गुजरात राज्य और अन्य, सहायक आयुक्त (सी.टी.), अन्ना सलाई-III मूल्यांकन सर्कल बनाम इंडियन ओवरसीज बैंक और अन्य, बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम बिक्री कर आयुक्त, इंदौर और अन्य, भानु राम और अन्य बनाम एच.बी.एन. डैरीज एंड एलाइड लिमिटेड, प्राचार्य आयकर आयुक्त बनाम मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड, मध्य प्र. राज्य और अन्य बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंदौर और अन्य, सॉलिडेयर इंडिया लिमिटेड बनाम फेयरग्रोथ फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, फ्रैंकलिन टेम्पलटन ट्रस्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम अमुता गर्ग और अन्य, शेवपूंजनराई इंद्रसनराई लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क कलक्टर और अन्य, पंजाब नेशनल बैंक बनाम भारत संघ और अन्य, बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम उप निदेशक, महाराजा प्रताप उदय नाथ***

शाही देओ बनाम सारा लाल दुर्गा प्रसाद नाथ शाही देओ और अन्य, पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड बनाम मेसर्स हरियाणा कॉन्कास्ट लिमिटेड और अन्य, अधिकृत अधिकारी, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर और अन्य बनाम मैथ्यू के.सी., भारत संघ बनाम एस.आई.सी.ओ.एम. लिमिटेड और अन्य, जलगांव जनता सहकारी बैंक लिमिटेड और अन्य बनाम संयुक्त आयुक्त, उप निदेशक प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली बनाम एक्सिस बैंक और अन्य, अधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक बनाम डी. विशालाक्षी और अन्य और कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड बनाम गिरनार कॉरूगेटर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के मामलों में विभिन्न निर्णयों पर भी भरोसा किया है।

26. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरुणाभ चौधरी ने श्री आशीष अग्रवाल, सुश्री आस्था कौशल और श्री अनिरुद्ध महादेवन की सहायता से प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 की ओर से अपने प्रति शपथपत्र पर भरोसा करते हुए कहा कि तीन आदेश अर्थात अंतरिम आदेश, पुष्टिकरण आदेश और अंतिम आदेश ने अंतिम रूप प्राप्त कर लिया है। इन आदेशों को चुनौती नहीं दी गई है। उसने कहा कि अंतरिम आदेश और पुष्टिकरण आदेश, याचिकाकर्ता द्वारा अभिलेख पर रखे गए हैं, हालांकि, याचिकाकर्ता द्वारा 09.06.2022 दिनांकित अंतिम आदेश को अभिलेख पर नहीं रखा गया है। प्रत्यर्थी सं.1 और 2 ने उपाबंध-आर1 के रूप में दिनांकित अंतिम आदेश की एक प्रति अभिलेख पर रखी है।

27. इसलिए, उसने तर्क दिया कि तीन आदेश न केवल नोटिसी के खिलाफ काम कर रहे हैं, बल्कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ काम कर रहे हैं जो नोटिसी के माध्यम से और विशेष रूप से तत्काल मामले में, प्रत्यर्थी सं. 3 और 4 के माध्यम से दावा कर रहा है।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, तीन आदेशों का प्रभाव नोटिसी के स्वामित्व वाली संपत्तियों के संचालन के लिए एक निषेधाज्ञा है।

28. उसके अनुसार, सेबी अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त विशेष क्षेत्राधिकार के तहत प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए निर्देश जारी किए गए हैं, न कि सेबी के किसी भी व्यक्तिगत दावे के लिए।

29. उसने यह भी प्रस्तुत किया कि सेबी अधिनियम, 1992 के प्रावधान सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों और आरडीबी अधिनियम, 1993 के प्रावधानों पर प्रबल होंगे। उसके अनुसार, यह केवल किसी अन्य अधिनियम के प्रावधान हैं, जो सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं, जिनका कोई अनुप्रयोग नहीं होगा। हालांकि, वर्तमान मामले में, उसके अनुसार, सरफेसी अधिनियम, 2002 और सेबी अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के बीच कोई असंगतता नहीं है और दोनों अधिनियम अपने संबंधित क्षेत्र में काम कर सकते हैं ताकि उस विशेष उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके जिसके लिए उन्हें अधिनियमित किया गया है।

30. अपने निवेदन को विस्तार से बताते हुए, उसने सेबी अधिनियम, 1992 के विधायी इरादे का संकेत दिया है, जो मुख्य रूप से एक सामाजिक कल्याण विधि है जो छोटे निवेशकों वाले आम आदमी के हितों की सुरक्षा की मांग करता है।

31. उसने प्रस्तुत किया कि सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 37 के तहत प्रावधान स्पष्ट रूप से सेबी अधिनियम, 1992 के प्रावधानों को संचालित करने के लिए स्थान

प्रदान करते हैं क्योंकि यह विशेष रूप से प्रदान करता है कि सरफेसी अधिनियम, 2002 या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधान कंपनी अधिनियम, 1956 (1/1956), प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (42/1956), सेबी अधिनियम, 1992 (15/1992), आर.डी.बी. अधिनियम, 1993 (51/1993) या उस समय लागू किसी अन्य विधि के अतिरिक्त हैं और उनके अपमान में नहीं हैं।

32. इसलिए, उसने कहा कि सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 37 में उल्लिखित चार अधिनियमों के प्रावधान विशेष रूप से सहेजे गए हैं और इसलिए, याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क स्वीकार्य नहीं है।

33. प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि सेबी अधिनियम, 1992 निरर्थक हो जाएगा यदि, क़ानून द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह नहीं माना जा सकता कि सेबी के पास बैंकों को संपत्ति के हस्तांतरण को रोकने का निर्देश देने की शक्ति है। यदि ऐसी शक्तियां सेबी को अध्यारोपित नहीं की जाती हैं तो कोई विनियमन और जांच नहीं हो सकती है। बैंक खातों से धन के अंतरण को रोकने के लिए या दूसरे शब्दों में, बैंक खातों से नामे को रोकने के लिए बैंकों को निर्देश देने की शक्ति, नियामक ढांचे के लिए आकस्मिक और आवश्यक है कि वह उस तरीके से काम करे जिसमें विधायिका ने इसकी कल्पना की थी। इसलिए, यह स्पष्ट है कि सेबी के पास सामान्य रूप से बैंकों और विशेष रूप से याचिकाकर्ता बैंक को निर्देश जारी करने की शक्ति है।

34. यथार्थता, विद्वान अधिवक्ता ने यह स्थापित करने की कोशिश की कि संसद का इरादा सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 37 के तहत स्पष्ट है जिसका अर्थ है कि सेबी अधिनियम, 1992 के प्रावधान धारा 35 में निहित गैर-अस्थाई खंड या सरफेसी अधिनियम, 2002 के अध्याय IV-A यानी धारा 26घ और उसके 26 ङ के अंतर्गत नहीं होंगे।

35. उसने इस संबंध में ***मैथ्यू वर्गीज बनाम एम. अमृथा कुमार और अन्य, केएसएल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम अरिहंत थ्रेड्स लिमिटेड, मद्रास पेट्रोकेम लिमिटेड बनाम औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड और अन्य, पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम भारतीय संघ, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बनाम अजय अग्रवाल, विद्या द्रोलिया बनाम दुर्गा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, जय इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड बनाम उद्योग सुविधा परिषद, पी. सी. जोशी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, रामदेव फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम अरविंदभाई रामभाई पटेल और अन्य, ए.जी. वरदराजुलु बनाम तमिलनाडु राज्य, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम केरल राज्य, इम्पीरिया स्ट्रक्चर्स लिमिटेड बनाम अनिल पटनी, पंजाब राज्य बनाम गुरदेव सिंह, केएसएल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम अरिहंत थ्रेड्स लिमिटेड, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाम एलाइड इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड और अन्य और डेविस और अन्य बनाम पॉवेल डफरिन एसोसिएटेड कॉलरीज लिमिटेड*** के मामलों में विभिन्न निर्णयों पर भी भरोसा किया है।

36. प्रत्यर्थी सं.1 और 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने मामले के गुण-दोष के आधार पर उनकी प्रस्तुतियों के अलावा, सेबी अधिनियम 1992 की धारा 15न के तहत प्रभावी वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के आधार पर तत्काल रिट याचिका की पोषणीयता के संबंध में एक प्रारंभिक आपत्ति भी उठाई। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्त आदेश जिन्हें याचिकाकर्ता बैंक पर लागू नहीं होने के रूप में घोषित करने की माँग की गई है, सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 15न के तहत प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (इसके पश्चात "एस.ए.टी.") के समक्ष अपील योग्य हैं और उनके अनुसार, एस.ए.टी. द्वारा पारित कोई भी आदेश सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 15य के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील योग्य है।

37. अपनी दलीलों का समर्थन करने के लिए, उन्होंने ***थानसिंह नाथमल और अन्य बनाम कर अधीक्षक, धुबरी और अन्य, राज कुमार शिवहरे बनाम सहायक निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय और अन्य, निवेदिता शर्मा बनाम सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम ग्रेटशिप (इंडिया) लिमिटेड, पंजाब राज्य और अन्य बनाम गुरदेव सिंह, कुबेर फ्लोरीटेक लिमिटेड बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और बलवीर सिंह बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड*** के मामलों में विभिन्न निर्णयों पर भरोसा किया है।

38. तत्काल रिट याचिका की रखरखाव के संबंध में प्रस्तुतियों के जवाब में याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता बैंक उक्त आदेशों से व्यथित नहीं है क्योंकि वे याचिकाकर्ता बैंक पर लागू

नहीं होते हैं। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता 29.01.2021 (पृ.-43) और 18.03.2021 (पृ.-44) के आक्षेपित ई-मेल/संचार से व्यथित है, जिसके द्वारा सेबी ने याचिकाकर्ता बैंक को दिनांक 29.05.2018 और 14.12.2018 के आदेशों का पालन करने और सेबी की पूर्व अनुमति के बिना सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 के तहत बंधकित संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया।

39. उनके अनुसार, आक्षेपित ई-मेल अधिकारिता के बिना हैं और याचिकाकर्ता का निवेशकों से कोई सरोकार नहीं है और वह इसमें पक्षकार नहीं है। याचिकाकर्ता केवल बंधकित संपत्ति का परिसमापन करते समय अपने ऋण की वसूली से संबंधित है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब बंधकित रखी गई संपत्ति को बैंक के पास गिरवी रखा गया था तो उस पर कोई विल्लंगम नहीं था और सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 15न के तहत अपील एक वास्तविक और प्रभावकारी उपाय नहीं होगी।

40. उन्होंने ***राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी लिमिटेड बनाम सेबी, एच.बी. स्टॉकहोल्डिंग्स लिमिटेड बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, राधा कृष्ण इंडस्ट्रीज, हि.प्र. राज्य, जशभाई मोतीभाई बनाम रोशन कुमार, हाजी बशीर अहमद और अन्य, रामप्रसाद सोमानी बनाम अध्यक्ष, सेबी, कुंतेश गुप्ता बनाम हिंदू कन्या महाविद्यालय, व्हर्लपूल कार्पोरेशन बनाम रजिस्ट्रार ऑफ़ ट्रेड मार्क्स, राम एंड श्याम कंपनी बनाम हरियाणा राज्य, हि.प्र. राज्य बनाम गुजरात अंबुजा सीमेंट लिमिटेड और सी.आई.टी. बनाम छबिल दास अग्रवाल*** के मामलों में विभिन्न निर्णयों पर भरोसा किया है।

41. चूंकि प्रत्यर्थी सं.1 और 2 ने तत्काल रिट याचिका की स्थिरता के संबंध में आपत्ति जताई है, इसलिए, इसे एक प्रारंभिक मुद्दे के रूप में माना जाना आवश्यक है।

42. वर्तमान मामले में, वर्तमान याचिका की पोषणीयता के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए, कुछ आनुषंगिक और प्रासंगिक मुद्दे हैं जिन पर निर्णेय लेने की आवश्यकता है। ये सेबी अधिनियम, 1992 के तहत सेबी के पास निहित शक्तियों, उक्त आदेशों के क्षेत्र और दायरे और आक्षेपित ई-मेल की प्रकृति से संबंधित हैं।

43. पहला मुद्दा जो न्यायालय को तय करना होगा वह यह है कि क्या सेबी के पास याचिकाकर्ता बैंक को निर्देश देने के लिए अपेक्षित विधिक शक्ति निहित है।

44. इस मामले में निर्विवाद रूप से, उक्त आदेश सेबी द्वारा पारित किए गए हैं, हालांकि, याचिकाकर्ता बैंक ने उन आदेशों का विरोध नहीं करने का विकल्प चुना है, बल्कि इसके बजाय आक्षेपित संचार को चुनौती दी है। प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 की प्रारंभिक आपत्ति का याचिकाकर्ता बैंक ने यह तर्क देकर जवाब दिया कि सेबी के पास याचिकाकर्ता बैंक, यानी सेबी के पास अपंजीकृत बैंक को निर्देश देने की अधिकारिता नहीं है। यह मानते हुए कि सेबी के पास अधिकारिता है, याचिकाकर्ता बैंक का तर्क है कि उक्त आदेश उसे बंधकित रखी गई संपत्ति की नीलामी करने से नहीं रोकते हैं, इसलिए, आक्षेपित ई-मेल उनके अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, न कि उक्त आदेशों का।

45. ***सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड*** *(पूर्वोक्त)* में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने सेबी को प्रदत्त शक्तियों की प्रकृति की व्याख्या की। इसने निम्नलिखित

टिप्पणियां कीं, जिन्हें बाद में शीर्ष न्यायालय के निर्णयों में दोहराया गया। पैराग्राफ सं.108, इसे निम्नानुसार देखा गया है:

> *"118. मैंने पहले ही संकेत दिया है कि अधिनियम की धारा 11क के तहत सेबी का कर्तव्य है कि वह सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करे, जो या तो सूचीबद्ध हैं या जिन्हें कानून के तहत सूचीबद्ध किया जाना आवश्यक है या जिन्हें सूचीबद्ध किया जाना है। धारा 11ख के तहत, सेबी के पास* ***प्रतिभूति बाजार से जुड़े किसी भी व्यक्ति को*** *प्रतिभूति और प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों में उचित निर्देश जारी करने की शक्ति है।"*
>
> *[जोर दिया गया]*

46. भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर ने अपनी सम्मत सहमति में वर्तमान मामले पर प्रभाव डालने वाली महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं। उन्हें उदारतापूर्वक निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

> *"221.*
>
> *...*
>
> *"2002 में सेबी अधिनियम में संशोधन अत्यंत प्रासंगिक है। 2002 में सेबी अधिनियम के संशोधन के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के प्रासंगिक भाग को नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:*
>
> *XXX*
>
> *2. हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के विधिक प्रावधानों में कई कमियां देखी गई हैं, विशेष रूप से निरीक्षण, जांच और प्रवर्तन के संबंध में। वर्तमान में, सेबी जानकारी की माँग कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है, स्टॉक एक्सचेंजों, म्यूचुअल फंडों, मध्यस्थों की पूछताछ और ऑडिट कर सकता है, निर्देश जारी कर*

सकता है, अभियोजन शुरू कर सकता है, निलंबन या पंजीकरण को रद्द करने का आदेश दे सकता है। अधिनियम के प्रावधानों या नियमों या विनियमों के उल्लंघन के मामले में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हालाँकि, सेबी के पास प्रतिभूतियों को जारी करने या किसी भी कंपनी द्वारा धन या परिसंपत्तियों की हेराफेरी को रोकने की कोई अधिकारता नहीं है। जबकि सेबी मध्यस्थों से जानकारी मांग सकता है, लेकिन यह किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित या गठित किसी भी बैंक और अन्य प्राधिकरण या बोर्ड या निगम से जानकारी नहीं मांग सकता है। सेबी लेखा पुस्तकों, दस्तावेजों आदि को अपनी हिरासत में नहीं रख सकता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 में निहित मौजूदा प्रावधानों के तहत, सेबी गवाहों या दस्तावेजों की जांच के लिए कमीशन जारी नहीं कर सकता है। इसके अलावा, सेबी ने बताया है कि मौजूदा दंड बहुत कम हैं और प्रभावी भयोपराधी के रूप में काम नहीं करते हैं। वर्तमान में, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के तहत, सेबी केवल उस अधिनियम की धारा 55क में निर्दिष्ट धाराओं में निहित प्रावधानों के उल्लंघन के लिए सूचीबद्ध कंपनियों का निरीक्षण कर सकता है, लेकिन वह सेबी अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों के उल्लंघन के लिए किसी भी सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी का निरीक्षण नहीं कर सकता है।

3. इसके अतिरिक्त, अर्थव्यवस्था में प्रतिभूति बाजारों के बढ़ते महत्व ने संगठन संरचना और संस्थागत क्षमता के संदर्भ में सेबी पर नई मांगें रखी हैं। इसलिए जांच और प्रवर्तन के लिए सेबी के पास उपलब्ध तंत्र को मजबूत करके इन कमियों को दूर करने की आवश्यकता महसूस की गई ताकि यह बाजार के अनाचारों की जांच और उन्हें लागू करने के लिए बेहतर तरीके से सुसज्जित हो सके।

4. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (6/2002) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय

बोर्ड अधिनियम, 1992 में संशोधन करने के लिए 29 अक्टूबर, 2002 को प्रख्यापित किया गया था।

5. अब अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विशेषताओं के साथ अध्यादेश को एक विधेयक द्वारा प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है

(क) सेबी के सदस्यों की संख्या छह (अध्यक्ष सहित) से बढ़ाकर नौ (अध्यक्ष सहित) करना।

(ख) बोर्ड को शक्ति प्रदान करना, क्योंकि,

(i) किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित या गठित किसी भी बैंक या अन्य प्राधिकरण या बोर्ड या निगम से प्रतिभूतियों में किसी भी संव्यवहार के संबंध में जानकारी और रिकॉर्ड मांगना जो बोर्ड द्वारा जांच या पूछताछ के अधीन है;

(ii) निवेशकों या प्रतिभूति बाजार के हित में, या तो लंबित जांच या पूछताछ के लिए या ऐसी जांच या पूछताछ के पूरा होने पर, निम्नलिखित में से कोई भी उपाय करने के लिए कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने का आदेश पारित करना, अर्थात्-

(क) किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी प्रतिभूति के व्यापार को निलंबित करना;

(ख) व्यक्तियों को प्रतिभूति बाजार तक पहुंचने से अवरोध और प्रतिभूति बाजार से जुड़े किसी भी व्यक्ति को प्रतिभूतियों को खरीदने, बेचने या सौदा करने से अवरोध;

(ग) किसी भी स्टॉक एक्सचेंज या स्वयं विनियमकारी संगठन के किसी भी पदाधिकारी को इस तरह के पद पर रहने से निलंबित करना;

(घ) जाँच के अधीन किसी भी संव्यवहार के संबंध में आय या प्रतिभूतियों को परिबद्ध और प्रतिधारित रखना;

(ङ) इस अधिनियम, या उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने वाले किसी भी तरीके से किसी भी मध्यस्थ या प्रतिभूति बाजार से जुड़े किसी भी व्यक्ति के एक या अधिक बैंक खाते या खातों को एक महीने से अधिक की अवधि के लिए अधिकार क्षेत्र वाले प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमोदन के लिए किए गए आवेदन पर आदेश पारित करने के बाद संलग्न करें;

(च) किसी भी मध्यस्थ या प्रतिभूति बाजार से जुड़े किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह से जांच के तहत किसी भी संव्यवहार का हिस्सा बनने वाली संपत्ति का निपटान या अन्यत्र न करने का निर्देश देना;

(iii) निवेशकों की सुरक्षा के लिए प्रॉस्पेक्टस जारी करने, प्रतिभूतियों को जारी करने के लिए पैसे मांगने वाले दस्तावेज़ या विज्ञापन की पेशकश को विनियमित या प्रतिबंधित करना;

(iv) किसी भी व्यक्ति को प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के पूर्व अनुमोदन के साथ, मध्यस्थ या प्रतिभूति बाजार से जुड़े व्यक्ति के मामलों की जांच करने और जांच के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझी जाने वाली पुस्तकों, रजिस्टरों, अन्य दस्तावेजों और अभिलेखों की खोज करने और जब्त करने का निर्देश देना;

(v) सेबी अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम या विनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करने वाले या उल्लंघन करने की संभावना वाले किसी व्यक्ति को ऐसा कोई उल्लंघन करने से रोकने और प्रवरित करने के लिए आदेश पारित करना;

(ग) षड्यंत्रात्मक और प्रवंचक उपकरणों, अंतरंगी व्यापार, कपटपूर्ण और षड्यंत्रात्मक व्यापार प्रवृत्तियाँ, बाजार हेरफेर और प्रतिभूतियों के पर्याप्त अधिग्रहण और नियंत्रण को प्रतिबंधित करना;

(घ) जुर्माने के रूप में प्राप्त राशि को भारत की संचित निधि में जमा करना;

... ''

[जोर दिया गया]

47. ***सुनील कृष्णन खेतान*** *(पूर्वोक्त)* में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ सं.81 में निम्नलिखित टिप्पणी की:

> *"... धारा 11(1) में बोर्ड के कार्यों को व्यापक रूप से परिभाषित करते हुए कहा गया है कि प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देना और विनियमित करना बोर्ड का कर्तव्य है। धारा 11-ख, जो निर्देश देने के लिए बोर्ड की शक्ति से संबंधित है, में कहा गया है कि बोर्ड, जांच करने या कराने के बाद, निर्देश जारी कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि यह आवश्यक है **निवेशकों का हित, या प्रतिभूति बाजार का व्यवस्थित विकास; धारा 12 में निर्दिष्ट किसी भी मध्यस्थ या अन्य व्यक्तियों के मामलों को निवेशकों के हित के लिए हानिकारक तरीके से कार्य करने से रोकने के लिए या ऐसे मध्यस्थ या व्यक्तियों का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए।** धारा 11(2)(ज) यह प्रावधान करता है कि बोर्ड शेयरों के पर्याप्त अधिग्रहण और कंपनियों के अधिग्रहण को विनियमित करने के लिए उपाय करने का हकदार है। विनियम 44 में कहा गया है कि निदेशक मंडल को निर्देश जारी करते समय प्रतिभूति बाजार के हित और निवेशकों के हित के संरक्षक के रूप में इसकी भूमिका को ध्यान में रखना होगा। हम "प्रतिभूति बाजार के हित में या निवेशकों की सुरक्षा के लिए" अभिव्यक्ति के बीच "या" शब्द को "और" के रूप में पढ़ेंगे। इसलिए, जब बोर्ड विनियमन 44 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने का निर्णय लेता है और उक्त विनियमन के तहत निर्देश जारी करता है, तो उसे दो पहलुओं को ध्यान में रखना होगा, अर्थात्, (i) प्रतिभूति बाजार का हित; और (ii) निवेशकों के हित का संरक्षण।*
>
> *[जोर दिया गया]*

48. ***सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड*** *(पूर्वोक्त)* में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद सेबी अधिनियम, 1992 को प्रतिभूति नियम (संशोधन) अधिनियम, 2014 के माध्यम से फिर से संशोधित किया गया था। संशोधन अधिनियम के महत्वपूर्ण अनुभाग निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किए गए हैं:

> *"...*
>
> *2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11 में (इसके पश्चात इस अध्याय में इसे मूल अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है), -*
>
> *(i) उप-धारा (2) में--*
>
> *(क) खंड (iक.) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—*
>
> *"(iक.) किसी भी केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित या गठित किसी बैंक या किसी अन्य प्राधिकरण या बोर्ड या निगम सहित किसी भी व्यक्ति से जानकारी और अभिलेख मंगाना, जो बोर्ड की राय में प्रतिभूतियों में किसी भी संव्यवहार के संबंध में बोर्ड द्वारा किसी भी जांच या पूछताछ के लिए प्रासंगिक होगा;*
>
> *(ख) खंड (iक.) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा और 6 मार्च, 1998 से प्रभावी रूप से अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—*
>
> *"(iख.) प्रतिभूति विनियमों के संबंध में उल्लंघनों की रोकथाम या पता लगाने से संबंधित मामलों में, इस संबंध में अभी लागू अन्य कानूनों के प्रावधानों के अधीन, बोर्ड के समान कार्य करने वाले अन्य प्राधिकरणों से, चाहे वे भारत में हों या भारत के बाहर, जानकारी प्राप्त करना या उन्हें जानकारी प्रदान करना:*

बशर्ते कि बोर्ड, भारत के बाहर किसी भी प्राधिकरण को कोई जानकारी देने के उद्देश्य से, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ ऐसे प्राधिकरण के साथ एक व्यवस्था या करार या समझौता कर सकता है;";

(ii) उप-धारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(5) इस अधिनियम की धारा 11ख या प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 12क या निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 19, जैसा भी मामला हो, के तहत जारी किए गए निर्देश के अनुसार अलग की गई राशि को बोर्ड द्वारा स्थापित निवेशक संरक्षण और शिक्षा निधि में जमा किया जाएगा और ऐसी राशि का उपयोग बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों के अनुसार किया जाएगा।

...

4. मूल अधिनियम की धारा 11ख में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण— सन्देहों को दूर करने के लिए, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस धारा के तहत निर्देश जारी करने की शक्ति में किसी भी व्यक्ति को, जिसने इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किसी भी लेनदेन या गतिविधि में लिप्त होकर लाभ या हानि को टाला है, ऐसे उल्लंघन से हुए गलत लाभ या हानि के बराबर राशि को हटाने का निर्देश देने की शक्ति शामिल होगी और हमेशा शामिल मानी जाएगी।"

49. आज की तिथि में, सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 11, जो सेबी के कार्यों के लिए प्रावधान करती है, इस प्रकार है:

11. बोर्ड के कार्य।—(1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, यह बोर्ड का कर्तव्य होगा कि वह प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करे

और प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा दे और उसे ऐसे उपायों द्वारा विनियमित करे जो वह उचित समझे।

(2) पूर्वगामी प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसमें निर्दिष्ट उपायों में निम्नलिखित प्रावधान किए जा सकते हैं-

(क) स्टॉक एक्सचेंज और किसी अन्य प्रतिभूति बाजार में व्यवसाय को विनियमित करना;

(ख) शेयर दलालों, उप-दलालों, शेयर हस्तांतरण अभिकर्ताओं, किसी निर्गम के लिए बैंकरों, न्यास विलेखों के न्यासियों, किसी निर्गम के कुलसचिवों, व्यापारी बैंकरों, हामीदारों, पोर्टफोलियो प्रबंधकों, निवेश सलाहकारों और ऐसे अन्य मध्यस्थों के कामकाज को पंजीकृत और विनियमित करना जो किसी भी तरह से प्रतिभूति बाजारों से जुड़े हो सकते हैं।

(खक) निक्षेपागारों, प्रतिभागियों, प्रतिभूतियों के संरक्षकों, विदेशी संस्थागत निवेशकों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों और ऐसे अन्य मध्यस्थों के कामकाज को पंजीकृत और विनियमित करना जिन्हें बोर्ड, अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है;

(ग) म्यूचुअल फंड सहित उद्यम पूंजी निधि और सामूहिक निवेश योजनाओं के कामकाज को पंजीकृत और विनियमित करना।

(घ) स्वयं विनियमकारी संगठनों को बढ़ावा देना और उनका विनियमन करना।

(ङ) प्रतिभूति बाजारों से संबंधित कपटपूर्ण और अनुचित व्यापार प्रवृत्तियों को प्रतिबंधित करना;

(च) निवेशकों की शिक्षा और प्रतिभूति बाजारों के मध्यस्थों के प्रशिक्षण को बढ़ावा देना;

(छ) प्रतिभूतियों में अंतरंगी व्यापार को प्रतिबंधित करना;

(ज) शेयरों के पर्यास अधिग्रहण और कंपनियों के अधिग्रहण को विनियमित करना;

(झ) स्टॉक एक्सचेंजों, म्यूचुअल फंडों, प्रतिभूति बाजार के मध्यस्थों और प्रतिभूति बाजार में स्वयं विनियमकारी संगठनों से जुड़े अन्य व्यक्तियों से जानकारी मांगना, निरीक्षण करना, पूछताछ करना और ऑडिट करना;

(झक) किसी भी केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित या गठित किसी बैंक या किसी अन्य प्राधिकरण या बोर्ड या निगम सहित किसी भी व्यक्ति से जानकारी और रिकॉर्ड प्राप्त करना, जो बोर्ड की राय में प्रतिभूतियों में किसी भी संव्यवहार के संबंध में बोर्ड द्वारा किसी भी जांच या पूछताछ के लिए प्रासंगिक होगा।

(झख) प्रतिभूति विनियमों के संबंध में उल्लंघनों की रोकथाम या पता लगाने से संबंधित मामलों में, इस संबंध में अभी लागू अन्य विनियमों के प्रावधानों के अधीन, बोर्ड के समान कार्य करने वाले अन्य प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करना या उन्हें जानकारी प्रदान करना, चाहे वे भारत में हों या भारत के बाहर हों:

बशर्ते कि बोर्ड, भारत के बाहर किसी भी प्राधिकरण को कोई जानकारी देने के उद्देश्य से, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ ऐसे प्राधिकरण के साथ एक व्यवस्था या करार या समझौता कर सकता है;

(ञ) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) के प्रावधानों के तहत ऐसे कार्यों का पालन करना और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा उसे सौंपा जा सकता है;

(ट) इस धारा के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उदग्रहण करना या अन्य शुल्क लगाना;

(ठ) उपरोक्त उद्देश्यों के लिए अनुसंधान करना;

(ठक) बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किसी भी ऐसी अभिकरण से ऐसी जानकारी प्राप्त करना या प्रस्तुत करना, जो उसके द्वारा अपने कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए आवश्यक मानी जाए;]

(ड) ऐसे अन्य कार्य करना जो निर्धारित किए जा सकते हैं;

(2क) उप-धारा (2) में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड किसी भी पुस्तक, या रजिस्टर, या किसी सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी या सार्वजनिक कंपनी (जो धारा 12 में संदर्भित मध्यस्थ नहीं है) के अन्य दस्तावेज या अभिलेख का निरीक्षण करने के लिए उपाय कर सकता है, जो अपनी प्रतिभूतियों को किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराने का इरादा रखता है, जहां बोर्ड के पास यह विश्वास करने के लिए उचित आधार है कि ऐसी कंपनी अंतरंगी व्यापार या प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अनुचित व्यापार प्रवृत्तियों में लिप्त रही है।

(3) 9 [उप-धारा (2) या उप-धारा (2ए)] के खंड (i) या खंड (iए) या उप-धारा (2ए)] के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय किसी भी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, बोर्ड के पास वही शक्तियां होंगी जो किसी मुकदमे का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के तहत सिविल कोर्ट में निहित हैं, निम्नलिखित विषयों के संबंध में, अर्थात्-

(i) लेखा पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों की खोज और उत्पादन, ऐसे स्थान पर और ऐसे समय पर जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है;

(ii) व्यक्तियों को बुलाना और उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित करना और शपथ पर उनकी जांच करना;

(iii) धारा 12 में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति की किसी भी पुस्तक, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों का किसी भी स्थान पर निरीक्षण;

(iv) उप-धारा (2ए) में निर्दिष्ट कंपनी की किसी पुस्तक, या रजिस्टर, या अन्य दस्तावेज या अभिलेख का निरीक्षण;

(v) साक्षियों या दस्तावेजों की जांच के लिए कमीशन जारी करना।] 1

[(4) उप-खंड (1), (2), (2ए) और (3) और खंड 11बी में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड, एक आदेश द्वारा, निवेशकों या प्रतिभूति बाजार के हित में लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, निम्नलिखित उपायों में से कोई भी उपाय कर सकता है, या तो लंबित जांच या जांच या ऐसी जांच पूरी होने पर, अर्थात्:—

(क) किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी प्रतिभूति के व्यापार को निलंबित करना;

(ख) व्यक्तियों को प्रतिभूति बाजार तक पहुंचने से प्रतिबंधित करना और प्रतिभूति बाजार से जुड़े किसी भी व्यक्ति को प्रतिभूतियों को खरीदने, बेचने या सौदा करने से प्रतिबंधित करना;

(ग) किसी भी स्टॉक एक्सचेंज या स्व-नियामक संगठन के किसी भी पदाधिकारी को इस तरह के पद पर रहने से निलंबित कर देगा।

(घ) जांच के अधीन किसी भी संव्यवहार के संबंध में आय या प्रतिभूतियों को जब्त और बनाए रखना; किसी भी मध्यस्थ या प्रतिभूति बाजार से जुड़े किसी भी व्यक्ति के बैंक खाते या अन्य संपत्ति को नब्बे दिनों से अधिक की अवधि के लिए इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान या उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों के उल्लंघन में शामिल किसी भी तरीके से कुर्क करना:

बशर्ते कि बोर्ड, उक्त कुर्की के नब्बे दिनों के भीतर, धारा 26क के तहत स्थापित विशेष न्यायालय से उक्त कुर्की की पुष्टि प्राप्त करेगा, जिसकी अधिकारिता है और इस तरह की पुष्टि पर, ऐसी कुर्की उपरोक्त कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान जारी रहेगी और उक्त कार्यवाहियों के समापन पर, धारा 28क के प्रावधान लागू होंगे:

बशर्ते कि केवल संपत्ति, बैंक खाता या खाते या उसमें दर्ज किया गया कोई भी संव्यवहार, जहां तक कि इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान या उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों के उल्लंघन में वास्तव में शामिल आय से संबंधित है, को कुर्क करने की अनुमति दी जाएगी।

(च) किसी भी मध्यस्थ या प्रतिभूति बाजार से जुड़े किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह से किसी भी संव्यवहार का हिस्सा बनने वाली संपत्ति का निपटान या अलगाव नहीं करने का निर्देश देता है जिसकी जांच की जा रही है:

बशर्ते कि बोर्ड, उप-धारा (2) या उप-धारा (2क) में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी भी सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी या सार्वजनिक कंपनी (जो धारा (2) में संदर्भित मध्यस्थ नहीं है) के संबंध में धारा (घ) या धारा (ङ) या धारा (च) में निर्दिष्ट उपायों में से कोई भी उपाय कर सकता है, जो अपनी प्रतिभूतियों को किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराने का इरादा रखता है, जहां बोर्ड के पास यह विश्वास करने के लिए उचित आधार है कि ऐसी कंपनी आंतरिक व्यापार या प्रतिभूति बाजार से संबंधित धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं में लिप्त रही है:

उप-धारा (1), (2), (2क), (3) और (4), धारा 11ख और धारा 15-I में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड, एक आदेश द्वारा, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, धारा 15क, 15ख, 15ग, 15घ, 15 ङ, 15 ङ क, 15 ङ ख, 15च, 15छ, 15ज, 15जक और 15जख के तहत निर्धारित तरीके से जांच करने के बाद जुर्माना लगा सकता है।

(5) इस अधिनियम की धारा 11ख या प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (42/1956) की धारा 12 क या निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (22/1996) की धारा 19 के तहत या प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (42/1956) की धारा 15ञख या धारा

23अक या निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (22/1996) की धारा 19अक के तहत किए गए समझौते के तहत जारी किए गए निर्देश के अनुसार, बोर्ड द्वारा स्थापित निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष में जमा की जाएगी और ऐसी राशि का उपयोग बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों के अनुसार किया जाएगा।"

50. सेबी अधिनियम, 1992 धारा 11ख (1) (3) (क) के माध्यम से सेबी को सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 12 में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग या प्रतिभूति बाजार से जुड़े व्यक्तियों को निर्देश देने की शक्ति प्रदान करता है। इस धारा को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"11ख. निर्देश जारी करने और जुर्माना लगाने की शक्ति।— (1) धारा 11 में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, यदि बोर्ड जांच करने या कराने के बाद संतुष्ट है कि यह आवश्यक है -

(i) निवेशकों के हित में, या प्रतिभूति बाजार के व्यवस्थित विकास में; या

(ii) धारा 12 में निर्दिष्ट किसी मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति के कार्यों को निवेशकों या प्रतिभूति बाजार के हितों के लिए हानिकारक तरीके से संचालित होने से रोकने के लिए; या

(iii) ऐसे किसी मध्यस्थ या व्यक्ति के उचित प्रबंधन को सुरक्षित करने के लिए, वह ऐसे निर्देश जारी कर सकता है -

(क) धारा 12 में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग, या प्रतिभूति बाजार से जुड़े व्यक्तियों के लिए; या

(ख) धारा 11क में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में किसी भी कंपनी के लिए, जो प्रतिभूतियों और प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हित में उचित हो सकता है।"

[जोर दिया गया]

51. इसी प्रकार, विनियम 2008 के विनियम 35 में सेबी को निवेशकों के हितों की सुरक्षा के उद्देश्य से निदेश जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। यह इस प्रकार है:

> *"35. प्रतिभूति कानूनों के तहत किसी भी आदेश और इन विनियमों के अध्याय 5 के तहत एक आदेश सहित उसके तहत जारी किए जाने वाले निर्देशों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बोर्ड प्रतिभूति बाजार के हित में, निवेशकों के हित में या किसी भी मध्यस्थ, निर्गम का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, आवश्यक निर्देश जिसमें निम्नलिखित में से किसी भी एक या सभी तक सीमित नहीं है -*
>
> ***(क) प्रतिभूति बाजार से जुड़े मध्यस्थ या अन्य व्यक्तियों को किसी भी योजना के तहत या अन्यथा, ब्याज के साथ या उसके बिना निवेशकों से एकत्र किए गए किसी भी धनराशि या प्रतिभूतियों के प्रतिदाय का निर्देश देना;***
>
> ***(ख) मध्यस्थ या प्रतिभूति बाजार से जुड़े अन्य व्यक्तियों को पूंजी बाजार तक नहीं पहुंचने या किसी विशेष अवधि के लिए प्रतिभूतियों में सौदा नहीं करने या किसी मध्यस्थ या किसी पूंजी बाजार से संबंधित गतिविधि से संबद्ध नहीं होने का निर्देश देना;***
>
> *(ग) मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को म्यूचुअल फंड या सामूहिक निवेश योजना द्वारा जारी प्रतिभूतियों या इकाइयों में व्यापार की अनुमति नहीं देने का निर्देश देना;*
>
> *(घ) म्यूचुअल फंड या सामूहिक निवेश योजना द्वारा जारी प्रतिभूतियों या इकाइयों में व्यापार को निलंबित करने के लिए संबंधित मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को निर्देश देना;*
>
> ***(ङ) कोई अन्य निर्देश जिसे बोर्ड मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित समझे:***

बशर्ते कि कोई भी निर्देश जारी करने से पहले बोर्ड संबंधित व्यक्तियों को सुनने का उचित अवसर देगा:

बशर्ते कि यदि परिस्थितियों के अनुसार कोई अंतरिम निर्देश तुरंत पारित करने की आवश्यकता है, तो बोर्ड बिना किसी अनुचित देरी के निर्देश पारित करने के बाद संबंधित व्यक्तियों को सुनवाई का उचित अवसर देगा।

[जोर दिया गया]

52. इसके बाद एक मध्यस्थ को विनियम, 2008 के विनियम 2 (1)(छ) के तहत निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया जाता है:

"(छ) "मध्यस्थ" का अर्थ है अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (ख) और (खक) और धारा 12 की उप-धारा (1) और (1 क) में उल्लिखित व्यक्ति और इसमें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के संबंध में एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी शामिल है, जो एक समाशोधन निगम या समाशोधन गृह का समाशोधन सदस्य है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक और स्टॉक एक्सचेंज के व्युत्पन्न भाग या मुद्रा व्युत्पन्न भाग के एक व्यापारिक सदस्य लेकिन इसमें विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक, म्यूचुअल फंड, सामूहिक निवेश योजना और उद्यम पूंजी निधि शामिल नहीं हैं;

[जोर दिया गया]

53. सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 12 में स्टॉक दलालों, उप-दलालों, शेयर हस्तांतरण अभिकर्ताओं आदि के पंजीकरण का प्रावधान है।

<u>12. स्टॉक-दलालों, उप-दलालों, शेयर हस्तांतरण अभिकर्ताओं आदि का पंजीकरण।—(1) कोई भी स्टॉक दलाल, उप-दलाल, शेयर हस्तांतरण अभिकर्ता, किसी निर्गम के लिए बैंकर, न्यास विलेख का न्यासी, किसी निर्गम के लिए पंजीयक, मर्चेंट बैंकर, हामीदार, पोर्टफोलियो प्रबंधक, निवेश सलाहकार और ऐसा अन्य मध्यस्थ जो प्रतिभूति बाजार से जुड़ा</u>

<u>हो, इस अधिनियम के तहत बनाए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र की शर्तों के अलावा प्रतिभूतियों में खरीद, बिक्री या सौदा नहीं करेगा:</u>

बशर्ते कि प्रतिभूतियों को खरीदने या बेचने वाला व्यक्ति या अन्यथा प्रतिभूति बाजार के साथ स्टॉक दलाल, उप-दलाल, शेयर हस्तांतरण अभिकर्ता, किसी निर्गम के लिए बैंकर, न्यास विलेख के न्यासी, किसी निर्गम के पंजीयक, मर्चेंट बैंकर, हामीदार, पोर्टफोलियो प्रबंधक, निवेश सलाहकार और ऐसे अन्य मध्यस्थ जो बोर्ड की स्थापना से तुरंत पहले प्रतिभूति बाजार से जुड़े हों, जिसके लिए ऐसे प्रतिष्ठान से पहले कोई पंजीकरण प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं था, ऐसे प्रतिष्ठान से तीन महीने की अवधि के लिए ऐसा करना जारी रख सकता है या, यदि उसने तीन महीने की उक्त अवधि के भीतर ऐसे पंजीकरण के लिए आवेदन किया है, तो ऐसे आवेदन के निपटारे तक:

बशर्ते कि प्रतिभूति विधि (संशोधन) अधिनियम, 1995 के प्रारंभ से तुरंत पहले प्राप्त पंजीकरण का कोई भी प्रमाण पत्र, ऐसे पंजीकरण के लिए प्रावधान करने वाले विनियमों के अनुसार बोर्ड से प्राप्त किया गया माना जाएगा।

(1क) कोई भी निक्षेपागार, प्रतिभागी, प्रतिभूतियों का संरक्षक, विदेशी संस्थागत निवेशक, प्रत्ययमापी अभिकरण, या प्रतिभूति बाजार से जुड़ा कोई अन्य मध्यस्थ, जैसा कि बोर्ड इस ओर से अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, इस अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों के अनुसार बोर्ड से प्राप्त पंजीकरण प्रमाण पत्र की शर्तों के तहत और उसके अनुसार के अलावा प्रतिभूतियों में खरीद या बिक्री या सौदा नहीं करेगा:

...

[जोर दिया गया]

54. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम के लिए बैंकर) विनियम, 1994 विनियम 2 (कक) में "किसी निर्गम के लिए बैंकर" को परिभाषित किया गया है और विनियम 2 (ङ) में "अनुसूचित बैंक" को परिभाषित किया गया है, जो निम्नानुसार है:

> *"2(1)*
> *...*
> *(कक) "किसी निर्गम का बैंकर" से निम्नलिखित सभी या किसी भी गतिविधि को करने वाला अनुसूचित बैंक अभिप्रेत है, अर्थात्:—*
> *(i) आवेदन और आवेदन धनराशि की स्वीकृति;*
>
> *(ii) आवंटन या कॉल धनराशि की स्वीकृति;*
>
> *(iii) आवेदन के धनराशि का प्रतिदाय;*
>
> *(iv) लाभांश या ब्याज वारंट का भुगतान;*
>
> *...*
>
> *"(ङ) "अनुसूचित बैंक" से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की दूसरी अनुसूची में शामिल एक बैंक अभिप्रेत है।"*

55. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची तब आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड यानी याचिकाकर्ता बैंक के लिए प्रावधान करती है।

56. इसके पश्चात इस न्यायालय के समक्ष जो प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या धारा 12 में निर्दिष्ट व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग को पंजीकरण से पहले धारा 11ख के तहत शक्तियों के अधीन किया जा सकता है जैसा कि सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 12 के तहत प्रदान किया गया है। दूसरे शब्दों में, क्या धारा 12 में निर्दिष्ट व्यक्तियों या व्यक्तियों

के वर्गों को धारा 11ख के तहत अपनी शक्तियों के अधीन होने के लिए सेबी के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है।

57. धारा 11ख (1) (iii) (क) के तहत प्रावधान के सटीक शब्दों की जांच की जा सकती है। यह धारा 12 के तहत पंजीकृत किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के विपरीत धारा 12 में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को बताता है। "बोर्ड के साथ पंजीकृत" या "मध्यस्थ के रूप में पंजीकृत" अभिव्यक्तियों का उपयोग विधानमंडल द्वारा सेबी अधिनियम, 1992 के अध्याय VIA के तहत उदारतापूर्वक किया जाता है जैसा कि सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 11कक के तहत भी देखा जा सकता है।

58. दूसरी ओर, विनियम 2(1)(छ) के तहत विनियम, 2008 "मध्यस्थ" को परिभाषित करता है, और धारा 12 के तहत व्यक्तियों को उसी तरीके से संदर्भित करता है जैसे इसे धारा 11ख(1)(iii)(क) के तहत संदर्भित किया जाता है। यह इस प्रकार है:

> *"2(1)(छ) "मध्यस्थ" का अर्थ है अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (बी) और (बीए) और धारा 12 की उप-धारा (1) और (1 ए) में उल्लिखित व्यक्ति और इसमें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के संबंध में एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी शामिल है, एक समाशोधन निगम या समाशोधन गृह विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का एक समाशोधन सदस्य और एक स्टॉक के व्युत्पन्न खंड या मुद्रा व्युत्पन्न खंड का एक व्यापारिक सदस्य विनिमय लेकिन इसमें विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक, म्यूचुअल फंड, सामूहिक निवेश योजना और उद्यम पूंजी निधि शामिल नहीं है;*
>
> *[जोर दिया गया]*

59. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि सेबी अधिनियम, 1992 और इसके तहत बनाए गए विनियम, धारा 12 के तहत सूचीबद्ध संस्थाओं के संदर्भों को दो तरीकों से नियोजित करते हैं, पहला पंजीकरण के बाद उन्हें संदर्भित करना है, और दूसरा सरल शब्दों में व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग का संदर्भ है, यानी सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 12 के तहत पंजीकरण की योग्यता के बिना।

60. यह भी विचार करना महत्वपूर्ण है कि धारा 12 के तहत प्रदान की गई विस्तृत सूची को सेबी अधिनियम, 1992 के किसी भी हिस्से में दोहराया नहीं गया है। इस प्रकार यह इस बिंदु को विश्वसनीयता देता है कि यदि सेबी अधिनियम, 1992 के तहत एक प्रावधान, पंजीकरण की योग्यता के साथ धारा 12 के तहत प्रगणित व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग को संदर्भित करने का इरादा रखता है, तो धारा को संदर्भ देने वाले प्रावधान में इस प्रभाव के शब्दों का प्रावधान किया जाना चाहिए।

61. इस प्रकार धारा 11ख(1)(iii)(क) का केवल एक ही स्पष्ट अर्थ दिया जा सकता है, वह यह है कि धारा 12 में निर्दिष्ट व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग को धारा 12 के तहत पंजीकरण के बावजूद संदर्भित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, धारा 11ख(1)(iii)(क) को आकर्षित करने के लिए, किसी को केवल धारा 12 में निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग में आना होगा, भले ही उनका सेबी के साथ पंजीकरण कुछ भी हो।

62. यह सच हो सकता है कि यह निर्माण, सेबी को प्राप्त शक्तियों के जाल को अन्य संकीर्ण निर्माण की तुलना में काफी हद तक विस्तृत करता है। लेकिन केवल परिणामों के आधार पर, यह न्यायालय किसी पाठ के स्पष्ट अर्थ को सीमित नहीं कर सकता है।

63. इस संबंध में, जी.पी. सिंह के वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत. 15वाँ संस्करण, पृ. 38-39 निम्नानुसार टिप्पणी करते हैं:

> *"जब किसी अधिनियम के शब्द स्पष्ट, उचित या असंदिग्ध होते हैं, यानी वे केवल एक ही अर्थ के लिए यथोचित रूप से अतिसंवेदनशील होते हैं, तो न्यायालय परिणाम की परवाह किए बिना उस अर्थ को प्रभावी बनाने के लिए बाध्य होते हैं। ससेक्स पीरेज के मामले में टिंडल सी.जे. द्वारा कहा गया नियम निम्नलिखित रूप में है:*
>
> > *"यदि अधिनियम के शब्द अपने आप में सटीक और असंदिग्ध हैं, तो उन शब्दों को उनके स्वाभाविक और सामान्य अर्थों में व्याख्या करने के अलावा और कुछ आवश्यक नहीं हो सकती है। ऐसे मामलों में शब्द अकेले ही विधि निर्माता के इरादे की सबसे अच्छी घोषणा करते हैं।"*
>
> *नियम को एक अन्य रूप में भी कहा गया है:*
>
> > *"जब कोई भाषा सरल और असंदिग्ध होती है और केवल एक अर्थ को स्वीकार करती है तो अधिनियम के निर्माण का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अधिनियम अपने लिए बोलता है।"*
>
> *निर्माण के परिणाम तब न्यायालय के लिए कोई मामला नहीं हैं, भले ही वे अजीब या आश्चर्यजनक, अनुचित या अन्यायपूर्ण या दमनकारी हों। "बार-बार," विस्काउंट साइमंड्स विद्वान अधिवक्ता ने कहा, इस बोर्ड ने इस बात पर जोर दिया है कि अधिनियमित शब्दों का अर्थ लगाने में हम शामिल नीति या परिणामों से संबंधित नहीं हैं, जो हानिकारक या अन्यथा हैं, जो उपयोग की गई भाषा को प्रभावी बनाने के लिए हो सकते हैं। जैसा कि न्या. गजेंद्रगडकर ने कहा:*
>
> *यदि उपयोग किए गए शब्द केवल एक निर्माण करने में सक्षम हैं तो न्यायालयों के लिए इस आधार पर कोई अन्य काल्पनिक निर्माण*

अपनाने के लिए खुला नहीं होगा कि ऐसा काल्पनिक निर्माण अधिनियम के कथित उद्देश्य और नीति के साथ अधिक सुसंगत है"।

64. समान आधार पर, क्रेज़ ऑन लेजिस्लेशन, 9वां संस्करण, कार्डिनल नियम के रूप में सादे अर्थ के अनुसार निर्माण का वर्णन करता है। पृष्ठ 611 पर अनुच्छेद सं. 17.1.1 में नियम का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में किया गया है:

"पारंपरिक नियम

विधायन के निर्माण के लिए मुख्य नियम यह है कि इसका अर्थ उपयोग की गई भाषा में व्यक्त इरादे के अनुसार किया जाना चाहिए। इसलिए न्यायालय का कार्य विधि की व्याख्या करना है "उनके इरादे के अनुसार जिन्होंने इसे बनाया" और उस इरादे को उपयोग की गई भाषा से निकाला जाना है।

आदर्श रूप से, जैसा कि उपरोक्त कहा गया है, विधान के शब्द सटीक और स्पष्ट होंगे और वे जहां भी हों, वे विधानमंडल के इरादे को घोषित करने का सबसे अच्छा और एकमात्र सच्चा साधन हैं। जैसा कि टिंडल सी.जे. ने वारबर्टन बनाम लवलैंड में कहा था -

"जहां किसी अधिनियम की भाषा स्पष्ट और व्यक्त है, हमें उसे प्रभावी बनाना चाहिए, चाहे जो भी परिणाम हों, क्योंकि उस मामले में अधिनियम के शब्द विधायिका के इरादे को बताते हैं।""

[जोर दिया गया]

65. स्पष्ट भाषा के परिणामों पर, पृष्ठ 613, पैराग्राफ संख्या 17.1.4 क्रेज़ ऑन लेजिस्लेशन *(पूर्वोक्त)* में निम्नलिखित कहा गया है:

"मुख्य नियम का प्रमुख प्रभाव, निम्नानुसार बताए गए प्रतिबंधों और संशोधनों के अधीन, यह है कि एक न्यायालय स्पष्ट विधायी भाषा को

प्रभावी बनाने के लिए बाध्य है, भले ही तत्काल मामले में परिणाम ऐसे हों कि विधायिका ने विचार नहीं किया हो और न ही स्वीकार किया हो। जैसा कि मु.न्या. जर्विस ने एबले बनाम डेल में कहा था -

> *"यदि उपयोग किए गए सटीक शब्द स्पष्ट और असंदिग्ध हैं, तो हम उन्हें उनके सामान्य अर्थों में समझने के लिए बाध्य हैं, भले ही यह एक बेतुकेपन या स्पष्ट अन्याय की ओर ले जाता है। जहां शब्दों का महत्व संदिग्ध या अस्पष्ट है, वहां शब्दों को संशोधित या भिन्न किया जा सकता है, लेकिन जब हम उपयोग किए गए सटीक शब्दों के सामान्य अर्थ से हट जाते हैं तो हम विधायकों के कार्यों को मान लेते हैं, केवल इसलिए कि हम देखते हैं, या कल्पना करते हैं, उनके शाब्दिक अर्थ के पालन से अर्थहीनता या प्रकट अन्याय।"*

66. वास्तव में यह मामला है कि यह पारंपरिक नियम अब इस योग्यता के अधीन हो गया है कि हास्यास्पद तर्क परिणामों से बचा जाना चाहिए, लेकिन वर्तमान मामला उक्त नियम के अपवादों के अंतर्गत नहीं आता है। इस प्रकार हम प्रावधान के स्पष्ट अर्थ के साथ रह गए हैं।

67. इसलिए इस न्यायालय की राय है कि सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 11ख(1)(iii)(क) सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 12 में निर्दिष्ट व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग को निर्देश देने की अनुमति देती है, भले ही सेबी में पंजीकृत व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग कुछ भी हो।

68. सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 11 ख और विनियम, 2008 के विनियम 35(ङ) के तहत सेबी को व्यापक शक्तियां दी गई हैं। जबकि विनियमन 35(ङ) विस्तृत रूप से

यह प्रदान नहीं करता है कि इस विनियमन के तहत किसके खिलाफ निर्देश पारित किए जा सकते हैं। यह निर्विवाद रूप से विनियमन 35 के तहत उल्लिखित संस्थाओं के खिलाफ पारित किया जा सकता है, जिसमें मध्यस्थ और प्रतिभूति बाजार से जुड़े व्यक्ति शामिल हैं।

69. सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 11ख में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि धारा 12 में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्गों या प्रतिभूति बाजार से जुड़े व्यक्तियों को निर्देश जारी किए जा सकते हैं।

70. वास्तव में सेबी के उचित संचालन के लिए बैंक को निर्देशित करने की शक्ति आवश्यक है। इस तरह की शक्तियां यह सुनिश्चित करने के लिए आकस्मिक हैं कि सेबी द्वारा की गई जांच या जांच का उद्देश्य वास्तव में सफल हो। लेकिन इस शक्ति के लिए, एक व्यक्ति, बिना इससे अधिक, अपनी संपत्ति का अपव्यय कर सकता है।

71. व्यक्ति या संस्था जो संदिग्ध साधनों द्वारा परिसंपत्तियों का अधिग्रहण या संग्रह करती है, जैसे ही उन्हें उनके खिलाफ शुरू की जा रही जांच या पूछताछ के बारे में सूचित किया जाता है, वे अपनी परिसंपत्तियों को ऐसे प्रपत्र और स्थान पर परिसमापन और हस्तांतरण कर सकते हैं जहां वे सेबी की पहुंच से बाहर हों। सेबी अधिनियम, 1992 और उसके तहत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों का इस तरह से निर्माण करना मूर्खतापूर्ण होगा कि उपरोक्त प्रभाव प्राप्त हो जाए।

72. हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि सेबी अधिनियम, 1992 के तहत सेबी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग इस तरह से किया जाना चाहिए कि वे अन्य कानूनों के साथ टकराव में न आएं या उनके प्रभाव को कम न करें। इसका अर्थ यह है कि सेबी द्वारा शक्ति का प्रयोग, जो सेबी अधिनियम, 1992 द्वारा उसे प्रदान किया गया है, केवल शक्ति का एक विधिक और वैध प्रयोग बना हुआ है, और जहां तक यह अन्य विधियों के जनादेश को भंग नहीं करता है।

73. तत्काल मामले के तथ्यों में, सेबी के पास याचिकाकर्ता बैंक को निर्देश देने की शक्ति है, हालांकि, उस शक्ति का उपयोग उचित सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। इसका प्रयोग अन्य विधियों के प्रभाव को कम करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

74. उपरोक्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सेबी के पास सेबी अधिनियम, 1992 के तहत विशेष रूप से याचिकाकर्ता बैंक और सामान्य रूप से बैंकों को निर्देश देने की शक्तियां हैं, चाहे वे सेबी के साथ पंजीकृत हों या नहीं।

75. सक्षमता पर निर्णय लेने के बाद, अब यह जांच की जानी चाहिए कि क्या उक्त आदेश याचिकाकर्ता बैंक को प्रत्यर्थी सं. 3 और 4 की बंधकित संपत्ति को हस्तांतरित करने से रोकते हैं।

76. उक्त आदेशों की प्रकृति को बेहतर ढंग से समझने के लिए, उनके महत्वपूर्ण भागों को निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.05.2018 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

"...

27. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यस्थ) विनियम, 2008 की धारा 11 (1), 11 (4), 11ख और 11घ सह पठित धारा 19 के आधार पर मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस एकतरफा अंतरिम आदेश के माध्यम एकपक्षीय निम्नलिखित निर्देश जारी करता हूं:

क. एफ.6 फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड, एफ.6 कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, श्री पंकज गोयल, श्री परवीन शर्मा, श्री मीनू गोयल, श्री संजय आनंद, सुश्री कविता आनंद, सुश्री आशा शर्मा, श्री दीपक गोयल और सुश्री रुचिका गोयल को प्रतिभूति बाजार में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है और उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभूतियों की खरीद, बिक्री या अन्यथा लेनदेन करने या किसी भी तरह से प्रतिभूति बाजार से जुड़े रहने पर अगले निर्देश तक प्रतिबंध लगा दिया गया है:

ख. उपरोक्त संस्थाएं और व्यक्ति अगले निर्देशों तक प्रतिभूति बाजार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह की कोई भी गतिविधि करना बंद कर देंगे।

ग. उपरोक्त संस्थाओं और व्यक्तियों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपनी सभी संपत्तियों, चाहे वह चल हो या अचल, या ऐसी किसी भी संपत्ति में किसी भी ब्याज या निवेश या शुल्क की पूरी सूची प्रदान करें, जिसमें उनके सभी बैंक खातों, डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड निवेशों का विवरण शामिल हो, लेकिन इन निर्देशों की प्राप्ति की तिथि से 5 कार्य दिवसों के बाद नहीं।

घ. उपरोक्त संस्थाओं और व्यक्तियों को निर्देश दिया जाता है कि वे सेबी की पूर्व अनुमति के अलावा किसी भी संपत्ति, चाहे वह चल हो या अचल, या बैंक खातों में पड़े धनराशि को छोड़कर ऐसी किसी

भी संपत्ति में कोई ब्याज या निवेश या शुल्क का निपटान या हस्तांतरण न करें।

ङ. इस संबंध में अगले निर्देशों तक, इन संस्थाओं की परिसंपत्तियों का उपयोग केवल संबंधित स्टॉक एक्सचेंज (ओं) की देखरेख में ग्राहकों/निवेशकों को धन के भुगतान और/या प्रतिभूतियों के वितरण के उद्देश्य से किया जाएगा।

च. निक्षेपागार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि संबंधित स्टॉक एक्सचेंज से पुष्टि के बाद उप-पैरा (ङ) में उल्लिखित उद्देश्य को छोड़कर उपरोक्त अधिकारों और व्यक्तियों के संयुक्त रूप से या अलग-अलग रखे गए डीमैट खातों में कोई डेबिट नहीं किया जाता है।

छ. पंजीयक और अंतरण अभिकर्ताओं को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि भौतिक रूप में प्रतिभूतियां (म्यूचुअल फंड इकाइयों सहित), जो संयुक्त रूप से या अलग-अलग रूप से उपरोक्त अधिकारों और व्यक्तियों द्वारा आयोजित की जाती हैं, इस संबंध में संबंधित स्टॉक एक्सचेंज से पुष्टि के बाद उप-पैरा (ङ) में उल्लिखित उद्देश्य के अलावा हस्तांतरित/छुड़ाए नहीं जाते हैं।

ज. बैंकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि एफ6 फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड, एफ6 कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, श्री पंकज गोयल और श्री मीनू गोयल द्वारा संयुक्त रूप से या अलग-अलग रखे गए बैंक खातों में कोई डेबिट नहीं किया जाए, सिवाय इसके कि संबंधित स्टॉक एक्सचेंज (ओं) की लिखित पुष्टि के तहत ग्राहकों/निवेशकों को धनराशि का भुगतान किया जाए।

झ. उपरोक्त निर्देश उपरोक्त संस्थाओं/व्यक्तियों के संबंध में शुरू की जा सकने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई के सेबी के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना हैं।

28. जैसा कि उपरोक्त उल्लेख किया गया है, निरीक्षण के दौरान यह देखा गया है कि एफ6 ने कुछ विशिष्ट ग्राहकों के लाभ के लिए अपने ग्राहकों की प्रतिभूतियों और धन का दुरुपयोग किया था। मेरे विचार में यह आवश्यक है कि ऐसे ग्राहकों की भूमिका की जांच सेबी द्वारा चल रही जांच परीक्षा में विस्तार से की जाए।

29. आदेश में दर्ज निष्कर्ष प्रथम दृष्टया तथ्यों की जांच और प्रथम दृष्टया कानून के उल्लंघन पर आधारित हैं।

30. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश की एक प्रति सभी स्टॉक एक्सचेंजों, संबंधित बैंकों, पंजीयक और हस्तांतरण अभिकर्ताओं और निक्षेपगारों को भेजी जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपरोक्त दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है।

...”

77. सेबी के पूर्णकालिक सदस्य द्वारा पारित दिनांक 14.12.2018 के पुष्टिकरण आदेश का सामग्री भाग निम्नानुसार है:

“...

आदेश:

26. उपरोक्त पर विचार करते हुए, मैं, धारा 11(1), 11(4) और आई.आई.डी. के साथ पठित, सेबी अधिनियम की धारा 19 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा पुष्टि करता हूं कि उपरोक्त उल्लिखित नोटिसियों के खिलाफ 29 मई, 2018 के अंतरिम एकतरफा आदेश के माध्यम एकपक्षीय जारी किए गए निर्देश अगले आदेश तक जारी रहेंगे।

27. आम्रपाली आग्रा ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड मामले में 31 अक्टूबर, 2018 को निर्णय लिया गया था कि ग्राहकों/निवेशकों के

हितों की रक्षा के लिए एक अलग डीमैट गणना और अलग ब्याज वाले बैंक खाते खोले जाएंगे जिसमें सूचना प्राप्तकर्ता से संबंधित प्रतिभूतियों और निधियों को स्थानांतरित किया जाएगा। मौजूदा मामले में, 29 मई, 2018 के अंतरिम आदेश ने निक्षेपगार, पंजीयक और हस्तांतरण अभिकर्ताय और बैंकों को निर्देश दिया कि नोटिसियों के खातों से कोई डेबिट/हस्तांतरण नहीं किया जाता है। इसलिए, मैं निम्नलिखित निर्देश देता हूँ:

क. चूँकि एन.एस.ई. में दावा मूल्य अधिक है, एन.एस.ई. व्यतिक्रमी समिति, जितनी जल्दी हो सके, एक समर्पित डीमैट खाता खोलेगी और संचालित करेगी जहाँ एफ. 6 फिनसर्व के डीमैट खाते में पड़ी सभी प्रतिभूतियों को स्थानांतरित किया जाएगा।

ख. एन.एस.ई. व्यतिक्रमी समिति एक राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ एक समर्पित ब्याज वाले बैंक खाते को खोलेगी और संचालित करेगी, जिसमें एफ. 6 फिनसर्व, श्री पंकज गोयल और सुश्री मीनू गोयल के नाम पर विभिन्न बैंक खातों में रखी गई सभी निधियों को हस्तांतरित किया जाएगा।

ग. एम.एक्स.वाई. की व्यतिक्रमी समिति एक राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ एक समर्पित ब्याज वाले बैंक खाते को खोलेगी और संचालित करेगी, जहां एफ.6 कमोडिटीज के नाम पर विभिन्न बैंक खातों में रखी गई सभी निधियों को हस्तांतरित किया जाएगा।

28. यह आदेश किसी भी प्रवर्तन कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है जिसे सेबी मामले की जांच के अनुसार नोटिस प्राप्तकर्ताओं के खिलाफ आवश्यक समझ सकता है। यह आदेश अगले निर्देश तक लागू रहेगा।

..."

78. यह देखा जा सकता है कि निर्देश की तीन प्रजातियाँ हैं जो सेबी द्वारा अपने दिनांकित 29.05.2018 आदेश में जारी की गई हैं, जिनकी पुष्टि बाद में दिनांकित

14.12.2018 आदेश द्वारा की गई थी। पहला निर्देश है जो विशिष्ट व्यक्तियों और संस्थाओं को जारी किए जाते हैं। इसमें पैराग्राफ सं. 27(क)-(घ) में दिए गए निर्देश शामिल हैं। दूसरी प्रजाति प्रतिभूति बाजार से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं को जारी किए गए निर्देशों से संबंधित है, जिनमें निक्षेपागार, रजिस्ट्रार और स्थानान्तरण अभिकर्ता शामिल हैं। इसमें पैराग्राफ सं. 27(च) और (छ) में दिए गए निर्देश शामिल हैं। तीसरी श्रेणी उन व्यक्तियों और संस्थाओं को जारी किए गए निर्देशों से संबंधित है जो न तो आवश्यक रूप से जांच का हिस्सा हैं और न ही अनिवार्य रूप से प्रतिभूति बाजार से जुड़े हैं। इसमें पैराग्राफ सं. 27(ङ) और (ज) और 30 में निर्देश शामिल हैं। ।

79. प्रत्यक्षतः यह देखा जा सकता है कि याचिकाकर्ता बैंक किसी निर्गम का पंजीयक या शेयर अंतरण अभिकर्ता नहीं है, हालांकि इसकी संक्षिप्त जांच की जा सकती है कि क्या याचिकाकर्ता बैंक एक 'निक्षेपागार' है, और इसलिए यह निर्देशों की दूसरी प्रजाति के अंतर्गत आता है। ' निक्षेपागार' शब्द को सेबी अधिनियम, 1992 के तहत परिभाषित नहीं किया गया है, हालांकि, सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 2 (2) में प्रावधान है कि जो शब्द और अभिव्यक्तियाँ सेबी अधिनियम, 1992 के तहत परिभाषित नहीं हैं, वे अपने अर्थ प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 या निक्षेपागार अधिनियम, 1996 से उधार लेंगे। सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 2 (2) को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

> *"(2) इस अधिनियम में उपयोग किए गए और परिभाषित नहीं किए गए लेकिन प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (42/1956) या निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) में*

परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ क्रमशः उस अधिनियम में दिए गए होंगे।"

80. 'निक्षेपागार' की परिभाषा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 में नहीं पाई जाती है, हालांकि, धारा 2 (ङ) में अधिनियम, 1996 उसी को परिभाषित करता है। यह इस प्रकार है:

"2...
(ङ) "निक्षेपागार" से कंपनी अधिनियम, 1956 (1/1956) के तहत गठित और पंजीकृत कंपनी अभिप्रेत है और जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (15/1992) की धारा 12 की उप-धारा (1क) के तहत पंजीकरण का प्रमाण पत्र दिया गया है"।

81. याचिकाकर्ता बैंक का मामला यह है कि वह सेबी के साथ पंजीकृत नहीं है, इसलिए, वह निर्देशों की दूसरी श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। अब यह जांच की जानी चाहिए कि क्या याचिकाकर्ता बैंक को तीसरी श्रेणी में शामिल किया जा सकता है।

82. 29.05.2018 दिनांकित आदेश के पैराग्राफ सं. 27 (ङ) के अवलोकन से पता चलता है कि एक सामान्य निर्देश दिया गया है कि संस्थाओं की संपत्ति का उपयोग केवल संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों की देखरेख में ग्राहकों/निवेशकों को प्रतिभूतियों के भुगतान और/या वितरण के उद्देश्य से किया जाना है।

83. इसी तरह, दिनांक 29.05.2018 के आदेश के पैराग्राफ सं. 27 (ज) में बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वे प्रत्यर्थी सं. 3 और 4 के बैंक खातों से कोई डेबिट न करें, स्टॉक एक्सचेंज की लिखित पुष्टि के साथ ग्राहकों/निवेशकों को धन के भुगतान के मामलों को छोड़कर।

84. यह निश्चित रूप से मामला है कि याचिकाकर्ता बैंक "बैंक" की श्रेणी में आता है, इसलिए पैराग्राफ सं.30 सह पठित पैराग्राफ सं.27 (ङ) में निहित निर्देश; और पैराग्राफ सं. 27 (ज) में याचिकाकर्ता बैंक पर लागू होता है।

85. हालाँकि, निर्देशों के वास्तविक महत्व पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। पैराग्राफ सं. 27(ङ) और (ज), और पैराग्राफ सं. 30 में निहित निर्देशों की सावधानीपूर्वक जांच से पता चलता है कि वे याचिकाकर्ता बैंक को बंधकित रखी गई संपत्ति सहित प्रत्यर्थी सं. 3 और 4 की संपत्ति को अन्यसंक्रांत करने से प्रतिबंधित नहीं करते हैं।

86. पैराग्राफ सं. 27 (ङ) में निहित निर्देश "ईकाईयों" की परिसंपत्ति को अन्यसंक्रांत होने से प्रतिबंधित करता है। ये "ईकाईयां" "व्यक्तियों" से भिन्न हैं, एक ऐसा शब्द जिसका उल्लेख पैराग्राफ सं. 27(ख)-(घ) और (च)-(छ) में निहित निर्देशों में मिलता है।

87. विशेष रूप से, "व्यक्तियों" और "ईकाइयों" के बीच यह वर्गीकरण पैराग्राफ सं. 27(क) में निहित निर्देशों से उपजा है। पैराग्राफ में एफ6 फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड और एफ6 कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड जैसी कुछ कंपनियों के साथ-साथ कुछ व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है, जिसमें प्रत्यर्थी सं. 3 और 4 भी शामिल है। बाद के पैराग्राफ में कंपनियों को "ईकाईयों" के रूप में संदर्भित किया गया है जबकि लोगों को "व्यक्तियों" के रूप में संदर्भित किया गया है।

88. बंधकित संपत्ति निस्संदेह प्रत्यर्थी सं. 3 और 4 की है, जो "ईकाईयो" के विपरीत लोग या "व्यक्ति" हैं। इसलिए यह मामला है कि पैराग्राफ सं. 27 (ङ) में निहित निर्देश

प्रत्यर्थी सं. 3 और 4 की परिसंपत्ति को अन्यसंक्रांत होने से प्रतिबंधित नहीं करते हैं, जिसमें बंधकित रखी गई संपत्ति भी शामिल है।

89. **पैराग्राफ सं.27 (ङ) में दिए गए निर्देशों को पैराग्राफ सं.30 के साथ पढ़ने में प्रत्यर्थियों को कोई भी सहायता प्रदान नहीं होती है।** पैराग्राफ सं. 30 में निहित निर्देश केवल यह निर्धारित करता है कि 29.05.2018 के आदेश को कुछ ईकाईयों और व्यक्तियों को सूचित किया जाना है ताकि पिछले पैराग्राफ में दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। **इस प्रकार, पैराग्राफ सं. 30, ऐसा कुछ भी आदेश नहीं देता है जो पहले से न दिया गया हो, न ही यह किसी ऐसी चीज़ को निर्देशित करता है जो पिछले निर्देशों में पहले से निर्देशित न हो।**

90. यहां तक कि अगर पैराग्राफ सं. 30 याचिकाकर्ता बैंक पर लागू होता है, तो यह केवल अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक निर्देश होगा। **जहां तक इसके अनुपालन का सवाल है, याचिकाकर्ता बैंक को केवल वही करने या ऐसा करने से रोकने के लिए कहा गया है जो लागू पूर्ववर्ती पैराग्राफ में कहा गया है।** पिछले पैराग्राफ में निहित निर्देशों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो याचिकाकर्ता बैंक को प्रत्यर्थी सं. 3 और 4 की परिसंपत्तियों को अन्यसंक्रांत करने से रोकता है, जिसमें बंधकित रखी गई संपत्ति भी शामिल है।

91. इसके अलावा, पैराग्राफ सं. 27 (ज) में निहित निर्देशों के संदर्भ में, यह देखा जा सकता है कि यह संबंधित बैंकों को पैराग्राफ में उल्लिखित व्यक्तियों और ईकाईयों के खातों में डेबिट किए जाने से रोकने का आदेश देता है। इसलिए प्रत्यर्थी सं. 3 और 4 की बंधकित रखी गई संपत्ति के लिए इसकी कोई प्रासंगिकता या अनुप्रयोग नहीं है।

92. दिनांक 14.12.2018 के पुष्टिकरण आदेश, पैराग्राफ सं. 27 में दिनांक 29.05.2018 के एकपक्षीय अंतरिम आदेश की पुष्टि करने के अलावा, एन.एस.ई. व्यतिक्रमी समिति को एक समर्पित डीमैट खाता खोलने और संचालित करने का निर्देश देता है जहां एफ 6 फिनसर्व के डीमैट खाते में पड़ी सभी प्रतिभूतियों को स्थानांतरित किया जाएगा।

93. यह आगे एन.एस.ई व्यतिक्रमी समिति को एक राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ एक समर्पित ब्याज वाले बैंक खाते को खोलने और संचालित करने का निर्देश देता है, जहां एफ 6 फिनसर्व, श्री पंकज गोयल और सुश्री मीनू गोयल के नाम पर रखे गए विभिन्न बैंक खातों में रखी सभी धनराशि को स्थानांतरित किया जाएगा।

94. इसी तरह, एमसीएक्स की व्यतिक्रमी समिति को एक समर्पित डीमैट खाता खोलने और संचालित करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें एफ6 कमोडिटीज के डीमैट खातों में पड़ी सभी प्रतिभूतियों को स्थानांतरित किया जाएगा, और एक राष्ट्रीयकृत बैंक में एक समर्पित ब्याज वाला बैंक खाता भी खोला जाएगा, जिसमें एफ6 कमोडिटीज के नाम पर रखे गए विभिन्न बैंक खातों में पड़ी सभी निधियों को स्थानांतरित किया जाएगा।

95. इसलिए, यह स्पष्ट है कि 29.05.2018 दिनांकित पुष्टिकरण आदेश में ऐसा कोई निर्देश भी नहीं है जो याचिकाकर्ता बैंक को गिरवी रखी गई संपत्ति की नीलामी करने से रोकता है।

96. अंत में, संख्या 1 और 2 द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए दिनांक 09.06.2022 के अंतिम आदेश में भी एक विशिष्ट निर्देश शामिल नहीं है जो याचिकाकर्ता बैंक को गिरवी रखी गई संपत्ति की नीलामी करने से रोकता है।

97. इसलिए यह देखा गया है कि इस आशय का कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है कि प्रत्यर्थी सं. 3 और 4 द्वारा व्यक्तिगत रूप से बंधकित रखी गई परिसंपत्ति का निपटान याचिकाकर्ता बैंक द्वारा प्रत्यर्थी सं. 3 और 4 द्वारा बकाया ऋण की वसूली के लिए नहीं किया जा सकता है।

98. उपरोक्त विश्लेषण से, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हालांकि उक्त आदेश याचिकाकर्ता बैंक पर लागू होते हैं, और सेबी के पास याचिकाकर्ता बैंक को निर्देशित करने की अपेक्षित विधिक शक्ति है, निर्देशों का सटीक और विशिष्ट शब्द ऐसी प्रकृति का नहीं है कि याचिकाकर्ता बैंक को प्रत्यर्थी सं. 3 और 4 की परिसंपत्ति को अन्यसंक्रांत करने से रोका जाए, जिसमें बंधकित रखी गई संपत्ति भी शामिल है।

99. इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद, इस बात पर विचार करना अनावश्यक है कि उक्त आदेश *सर्वबन्धी* में काम करते हैं या *व्यक्तिबंधी* में । उक्त आदेशों की प्रकृति पर एक निष्कर्ष निर्देश की सामग्री को उपांतरित या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। उक्त आदेशों में वे निर्देश शामिल हैं जो याचिकाकर्ता बैंक पर लागू होते हैं, और सेबी के पास विधि द्वारा निहित शक्तियां हैं, हालाँकि, उनमें निहित निर्देशों की सटीक शब्दावली में ऐसा कोई आदेश नहीं है जो याचिकाकर्ता बैंक को प्रत्यर्थी सं. 3 और 4 की संपत्ति से

निपटने से रोकता है, जो उसके पास बंधकित है, और उसे विधि के अनुसार साकार करने से रोकता है।

100. इस मामले को देखते हुए, यह न्यायालय विद्या सम्बन्धी मुद्दे पर निर्णय लेना अनुचित मानती हैं कि क्या सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 11 (4), 11 बी और 11 घ और विनियम, 2008 के विनियम 35 के तहत पारित आदेश एक *सर्वबन्धी* में काम करते हैं या *व्यक्तिबंधी*।

101. इस न्यायालय को अब आक्षेपित ई-मेल से संबंधित मुद्दे पर विचार करना चाहिए, जिसमें आक्षेपित ई-मेल की प्रकृति भी शामिल है।

102. ***राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी लिमिटेड*** *(पूर्वोक्त)* में संव्यवहार करते समय अर्ध-न्यायिक आदेशों की प्रकृति से संबंधित पहलू से निपटने के दौरान, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुमोदन के साथ ***शिवाजी नाथूभाई बनाम भारत संघ और अन्य*** का हवाला दिया, जिसमें ***बॉम्बे प्रांत बनाम खुशालदास एस. आडवाणी*** में लार्ड जस्टिस एटकिन के पैराग्राफ के उल्लेख के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित तीन को आवश्यकता के रूप में अभिआदेश किया था, जिन्हें पूरा करने की आवश्यकता है, ताकि एक प्रशासनिक अधिनियम को अर्ध-न्यायिक के रूप में चिह्नित किया जा सके-(i) कानूनी प्राधिकरण होना चाहिए; (ii) यह प्राधिकरण विषयों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रश्नों को निर्धारित करने के लिए होना चाहिए; और (iii) न्यायिक रूप से कार्य करने का कर्तव्य होना चाहिए।

103. इसके अलावा, ***एच.बी. स्टॉकहोल्डिंग्स लिमिटेड*** *(पूर्वोक्त)* में, एक "आदेश" के अर्थ और प्रकृति की व्याख्या की गई थी। यह निर्णय दिया गया था कि एक आदेश मुख्य रूप से एक निर्णय है जिसमें एक आदेश का प्रभाव होता है, चाहे इस तरह के नाम से बुलाया जाए या नहीं, और एक सलाह या अनुरोध से अलग है, परिणाम की प्रकृति से जो उसी के गैर-कार्यान्वयन से प्रवाहित हो सकता है। इसके अलावा, यह माना गया कि यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई संचार या निर्णय किसी आदेश के बराबर है, इसके सार को देखना होगा न कि इसके रूप को। यदि कोई विशेष निर्देश, अनुरोध या अवलोकन बाध्यकारी है और इसके उल्लंघन के लिए दंडात्मक परिणाम हैं, तो इसे एक आदेश के रूप में माना जाएगा।

104. 29.01.2021 दिनांकित ई-मेल का महत्वपूर्ण भाग इस प्रकार है:

> *"3. यह सेबी के संज्ञान में लाया गया है कि आई.सी.आई.सी.आई. बैंक ने 19 दिसंबर, 2020 को आई.सी.आई.सी.आई. बैंक (अपने शाखा कार्यालय प्लॉट नं. 23, तीसरी मंजिल, शाही टावर, नया रोहतक रोड, करोलबाग, नई दिल्ली-110005) इस संपत्ति की ऑनलाइन नीलामी कर रहा है जो श्री दीपक गोयल और श्रीमती रुचिका गोयल के नाम पर विला नं. टीवी-जी-जीवी-07, द पाम स्प्रिंग्स, विलेज वजीराबाद, सेक्टर 54, गुड़गांव-1220002 (हरियाणा) 7136.93 वर्ग कि. मी. फीट (संलग्न) है।*
>
> *4. यह सूचित किया जाता है कि पैरा सं. 29 मई, 2018 के आदेश के 27 (घ) के अनुसार, सेबी ने उपरोक्त उल्लिखित व्यक्तियों/ईकाईयों के खिलाफ निम्नलिखित में से एक निर्देश पारित किया:*
>
> *"...उपरोक्त ईकाईयों और व्यक्तियों को निर्देश दिया जाता है कि वे किसी भी संपत्ति, चाहे वह चल हो या अचल, या किसी भी संपत्ति का निपटान*

या अन्यसंक्रांत न करें। सेबी की पूर्व अनुमति के अलावा बैंक खातों में पड़े धन को छोड़कर ऐसी किसी भी संपत्ति में ब्याज या निवेश या शुल्क।

*5. 29.05.2018 और 14.12.2018 दिनांकित ईमेल के माध्यम से आदेश की प्रति आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को भी भेजी गई थी। संदर्भ के लिए आदेशों की प्रति इसके साथ संलग्न की जा रही है। उपरोक्त बातों पर विचार करें। **निर्देश दिए गए हैं कि आपको सेबी के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है।"***

[जोर दिया गया]

105. 18.03.2021 दिनांकित ई-मेल का महत्वपूर्ण भाग इस प्रकार है:

*"ट्रेलिंग मेल के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि सेबी द्वारा जारी अंतरिम आदेश सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 11(1), 11(4), 11ख और 11घ में प्रदान शक्तियों को लागू करते हैं और दलाल अथवा उसकी परिसंपत्तियों/देयताओं से संबंधित सभी घटकों को जांच/फॉरेंसिक ऑडिट के अनुपालन तक बाध्य करते हैं। **इस तरह के अंतरिम हिमीकरण आदेशों को केवल उस व्यक्ति/ईकाई पर बाध्यकारी नहीं कहा जा सकता है जिसने प्रतिभूति विधियों के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, बल्कि बाजार में अन्य घटकों जैसे कि बैंकों, कंपनियों, मध्यस्थों आदि को भी बाध्य करता है, जिनका स्टॉक दलाल की विषय परिसंपत्तियों के साथ संव्यवहार है या जिन्होंने उक्त दलाल या उसके ग्राहकों के साथ लेनदेन किया है।***

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, सेबी की पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना सेबी द्वारा उचित निषेधात्मक आदेश लागू होने पर संपत्ति की बिक्री के लिए आई.सी.आई.सी.आई. बैंक द्वारा उठाए गए कदम उचित नहीं समझे जाते हैं।

<u>इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप 29 मई, 2018 और 14 दिसंबर, 2018 के सेबी के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें और ऐसी कोई कार्रवाई शुरू न करें जो उक्त आदेशों का उल्लंघन हो।"</u>

[जोर दिया गया]

106. ***स्टॉकहोल्डिंग्स लिमिटेड*** *(पूर्वोक्त)* के निर्णय को लागू करते हुए, वर्तमान आक्षेपित ई-मेल को आदेशों से अलग किया जाना है। ***शिवाजी नाथूभाई*** *(पूर्वोक्त)* में बताई गई तीन शर्तें, जिन्हें पूरा किया जाना है, ताकि आक्षेपित ई-मेल को अर्ध-न्यायिक आदेश माना जा सके, उन्हें भी पूरा नहीं किया जाता है। आक्षेपित ई-मेल न तो किसी प्राधिकारी द्वारा हैं जो विषयों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रश्नों का निर्धारण करने के लिए है और न ही प्रत्यर्थी सं. 1 न्यायिक रूप से कार्य करने के कर्तव्य के तहत था जब उसने आक्षेपित ई-मेल भेजे थे।

107. आक्षेपित ई-मेल इस प्रकार संवादात्मक प्रकृति के होते हैं।

108. 29.01.2021 दिनांकित ई-मेल याचिकाकर्ता बैंक को उक्त आदेशों के अस्तित्व के बारे में सूचित करता है, जिसमें पैराग्राफ सं.27(घ) दिनांकित 29.05.2018 आदेश का और याचिकाकर्ता बैंक को इसका पालन करने की सलाह देता है। 18.03.2021 दिनांकित ई-मेल में घोषणा की गई है कि उक्त आदेश सर्वबन्धी में काम करते हैं, वे याचिकाकर्ता बैंक पर लागू होते हैं, याचिकाकर्ता बैंक का बंधकित संपत्ति की नीलामी करने का कार्य "अनुचित" है, और याचिकाकर्ता बैंक को उक्त आदेशों के निर्देशों का पालन करना है।

109. हालांकि ठीक से तैयार नहीं किया गया है, ईमेल, वास्तव में, सूचित करते हैं कि उक्त आदेशों में निर्देश हैं, जिसमें पैराग्राफ सं.27(घ) दिनांकित 29.05.2018 आदेश का,

जो याचिकाकर्ता बैंक पर लागू होता है क्योंकि उक्त आदेश सर्वबन्धी में काम करते हैं, और इसलिए याचिकाकर्ता बैंक को बंधकित रखी गई संपत्ति की नीलामी करने से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। यह न्यायालय इसे त्रुटिपूर्ण तर्क मानता है।

110. जैसा कि पिछले पैराग्राफ में समझाया गया था, पैराग्राफ सं. 27(ङ) में दिए गए निर्देश को छोड़कर, 29.05.2018 के आदेश में विशिष्ट ईकाईयों और व्यक्तियों के लिए विशिष्ट निर्देश शामिल हैं। पैराग्राफ सं. 27 (ङ) में निर्देश भी परिसंपत्तियों से संबंधित है, न कि व्यक्तियों से। इसलिए प्रत्यर्थी सं. 3 और 4 की परिसंपत्ति पैराग्राफ सं. 27 (ङ) में निहित निर्देश के दायरे से बाहर है।

111. एक निष्कर्ष कि उक्त आदेश सर्वबन्धी में काम करते हैं, निर्देश की महत्वपूर्ण शर्तों को नहीं बदल सकता है। वे उन व्यक्तियों पर निर्देश लागू नहीं कर सकते हैं जिन पर यह लागू नहीं होता है। उदाहरण के लिए, यह मामला नहीं हो सकता है, कि एक दिशा जिसमें किसी व्यक्ति को "x" करने या किसी विशेष कार्य को करने से छोड़ने की आवश्यकता होती है, जब सर्वबन्धी में पाया जाता है, तो बाकी दुनिया की आवश्यकता होती है, जिसमें व्यक्तियों और ईकाईयों को विशेष रूप से निर्देशित नहीं किया जाता है और कार्यवाही से पूरी तरह से असंबद्ध भी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि "x" वास्तव में उस विशेष कार्य को करने से करता है या पूर्वाभास करता है। इस प्रकार आक्षेपित ई-मेल में निहित तर्क गलत है।

112. इसलिए, उक्त ई-मेल, उक्त आदेशों के दायरे का विस्तार करते हैं, और इसके साथ असंगत हैं।

113. उपर्युक्त विश्लेषण से, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आक्षेपित ईमेल गलत थे और पूरी तरह से अधिकारिता के बिना थे।

114. इस न्यायालय को अब सहायक और आकस्मिक मुद्दों पर उपरोक्त निष्कर्षों के प्रकाश में पोषणीयता के मुद्दे की समग्र रूप से जांच करनी चाहिए।

115. ***थानसिंह नथमल*** *(पूर्वोक्त)* में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के शब्द व्यापक होने के बावजूद, इस विवेकाधीन राहत पर कुछ स्व-लागू सीमाएँ होनी चाहिए, और वे ऐसी प्रकृति की होनी चाहिए, जो अनुच्छेद 226 को एक वैकल्पिक उपाय के रूप में माने जाने की अनुमति नहीं देगी। इसके विपरीत, किसी विवाद के समाधान के लिए या अनुच्छेद 226 याचिका में इस तरह से अनुरोध की गई राहत देने के लिए मौजूदा विधिक तंत्र की उपस्थिति में, उच्च न्यायालय के रिट अधिकारिता का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

116. ***निवेदिता शर्मा*** *(पूर्वोक्त)* में, सर्वोच्च न्यायालय ने ***थानसिंह*** *(पूर्वोक्त)* को मंजूरी देते हुए कहा कि यदि पीड़ित व्यक्ति के लिए एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है या जिस अधिनियम के तहत शिकायत की गई कार्रवाई की गई है, उसमें स्वयं शिकायत के निवारण के लिए एक तंत्र है, तो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत राहत नहीं होगी।

117. ***ग्रेटशिप (इंडिया) लिमिटेड*** (पूर्वोक्त) में, फिर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उच्च न्यायालय ने

वैधानिक उपायों को दरकिनार करते हुए महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2002 और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के तहत निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित एक मूल्यांकन आदेश के खिलाफ भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका पर विचार करने में गलती की थी।

118. ***गुरूदेव सिंह*** *(पूर्वोक्त)* मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रो. वेड के प्रशासनिक व्यवस्था, 6 वीं संस्करण, पृष्ठ संख्या 352, निम्नानुसार वर्णित है:

> *"9. सिद्धांत के अनुरूप प्रो. वेड कहते हैं: "सिद्धांत समान रूप से सही होना चाहिए जहां अयोग्यता का "ब्रांड" स्पष्ट रूप से दिखाई देता है; क्योंकि वहां भी न्यायालय का निर्णय प्राप्त करके ही विधि में आदेश का प्रभावी ढंग से विरोध किया जा सकता है। प्रोफ़ेसर वेड इन सिद्धांतों का सारांश देते हैं:*
>
> *"मामले की सच्चाई यह है कि न्यायालय किसी आदेश को तभी अमान्य करेगी जब सही व्यक्ति द्वारा सही कार्यवाही और परिस्थितियों में सही उपाय मांगा जाए। आदेश काल्पनिक रूप से अमान्य हो सकता है, लेकिन न्यायालय वादी की स्थिति की कमी के कारण इसे रद्द करने से इनकार कर सकती है, क्योंकि वह विवेकाधीन उपचार का हकदार नहीं है, क्योंकि उसने अपने अधिकारों को अधित्यक्त कर दिया है, या किसी अन्य विधिक कारण से। ऐसे किसी भी मामले में "शून्य" आदेश प्रभावी रहता है और वास्तव में वैध होता है। यह इस प्रकार है कि एक आदेश एक उद्देश्य के लिए अमान्य और दूसरे के लिए वैध हो सकता है और यह कि यह एक व्यक्ति के खिलाफ अमान्य हो सकता है लेकिन दूसरे के खिलाफ वैध हो सकता है।"*

119. ***कुबेर फ्लोराइटेक लिमिटेड*** *(पूर्वोक्त)* और ***बलवीर सिंह*** *(पूर्वोक्त)* में, इस न्यायालय ने इस आधार पर कि अधिनियम के भीतर एक वैकल्पिक प्रभावी उपाय उपलब्ध है, रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें सेबी द्वारा पारित आदेशों को चुनौती दी गई थी।

120. ***राज कुमार शिवहरे*** *(पूर्वोक्त)* मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि माननीय उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक रिट याचिका को अनुमति देने में स्पष्ट रूप से गलती की, भले ही याचिकाकर्ता यह प्रदर्शित करने में विफल रहा हो कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 35 के तहत अपील के रूप में वैकल्पिक वैधानिक उपाय प्रभावी क्यों नहीं है।

121. इसके अलावा, ***कुंतेश गुप्ता*** *(पूर्वोक्त)* और ***व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन*** *(पूर्वोक्त)* पर भरोसा किया गया है; उक्त मामले प्रोत्साहित करते हैं कि ऐसे मामलों में जहां आक्षेपित आदेश/कार्रवाई पूरी तरह से अधिकारिता के बिना है और ऐसे मामलों में जहां प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया है, एक वैकल्पिक उपचार का अस्तित्व अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियों के लागू होने के लिए एक बाधा के रूप में कार्य नहीं करेगा। ***व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन*** *(पूर्वोक्त)* के महत्वपूर्ण भाग को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

> *"**14.** संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विशेषाधिकार रिट जारी करने की शक्ति पूर्ण प्रकृति की है और यह संविधान के किसी अन्य प्रावधान द्वारा सीमित नहीं है। इस शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा न केवल संविधान के भाग III में निहित किसी भी मूल अधिकार को लागू करने*

के हेवियस कार्पस परमादेश, निषेध वारंट और उत्प्रेषण की प्रकृति में रिट जारी करने के लिए किया जा सकता है, बल्कि "किसी अन्य उद्देश्य" के लिए भी किया जा सकता है।

15.** संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत, उच्च न्यायालय को मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका पर विचार करने या न करने का विवेकाधिकार है। लेकिन उच्च न्यायालय ने अपने उपरोक्त कुछ प्रतिबंध लगाए हैं जिनमें से एक यह है कि यदि कोई प्रभावी और प्रभावी उपाय उपलब्ध है, तो उच्च न्यायालय सामान्य रूप से ऐसा नहीं करेगा। **अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करें। लेकिन इस न्यायालय द्वारा वैकल्पिक उपचार को लगातार कम से कम तीन आकस्मिकताओं में एक बाधा के रूप में काम नहीं करने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है, अर्थात्, जहां किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए रिट याचिका दायर की गई है या जहां प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है या जहां आदेश या कार्यवाही पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना है या किसी अधिनियम के अधिकारों को चुनौती दी गई है।

...

20.** तब से पुल के नीचे बहुत पानी बह गया है, लेकिन इन निर्णयों पर कोई संक्षारक प्रभाव नहीं पड़ा है, जो पुराने होने के बावजूद, इस क्षेत्र में बने हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक रिट याचिका पर विचार करने में उच्च न्यायालय के अधिकारिता के बारे में विधि है। संविधान का अनुच्छेद 226, **वैकल्पिक वैधानिक उपचारों के बावजूद, प्रभावित नहीं होता है, विशेष रूप से ऐसे मामले में जहां प्राधिकरण जिसके खिलाफ रिट दायर किया गया है, उसके पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था या बिना किसी कानूनी आधार के अधिकार क्षेत्र को हड़पने का इरादा था।"

[जोर दिया गया]

122. ***गोदरेज सारा ली लिमिटेड बनाम आबकारी और कराधान अधिकारी*** मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय के हाल के एक निर्णय में , किसी याचिका की पोषणीयता और मनोरंजन के बीच के अंतर को विस्तार से बताते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय

ने स्पष्ट किया कि वैकल्पिक उपचार का सिद्धांत मनोरंजन के क्षेत्र से संबंधित है। इस प्रकार, उच्च न्यायालय की शक्तियों पर कोई आत्यन्तिक प्रतिबंध नहीं है।

123. माननीय उच्चतम न्यायालय ने आगे यह निष्कर्ष निकाला कि जिन मामलों में विवाद विशुद्ध रूप से विधिक है, और इसमें तथ्य के आक्षेपित प्रश्न नहीं हैं, बल्कि केवल विधि के प्रश्न शामिल हैं, तो वैकल्पिक उपचार के आधार पर रिट याचिका को खारिज करने के बजाय उच्च न्यायालय द्वारा इसका निर्णय लिया जाना चाहिए। ***गोदरेज सारा ली लिमिटेड*** *(पूर्वोक्त)* में निर्णय के महत्वपूर्ण भाग को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

> *"प्रश्नों का उत्तर देने से पहले, हम संविधान के अनुच्छेद 226 द्वारा प्रदत्त रिट शक्तियों के प्रयोग पर कुछ शब्द कहने का आग्रह महसूस करते हैं क्योंकि उच्च न्यायालयों द्वारा पारित कुछ आदेशों में रिट याचिकाओं को केवल "बनाए रखने योग्य नहीं" माना गया है। **क्योंकि संबंधित विधियों द्वारा प्रदान किए गए वैकल्पिक उपचार को रिट अधिकारिता को लागू करने के इच्छुक पक्षों द्वारा आगे नहीं बढाया गया है। अनुच्छेद 226 के तहत विशेषाधिकार रिट जारी करने की शक्ति पूर्ण प्रकृति की है। इस तरह की शक्ति के प्रयोग पर किसी भी परिसीमन का पता संविधान में ही लगाया जाना चाहिए ।** इस संबंध में अनुच्छेद 329 और संविधान में इसी तरह के अन्य अनुच्छेदों के आदेशों का संदर्भ दिया जा सकता है। अनुच्छेद 226, संदर्भ में, रिट जारी करने की शक्ति के प्रयोग पर कोई परिसीमन या प्रतिबंध नहीं लगता है। हालांकि यह सच है कि उसी विधि के तहत एक उपाय की उपलब्धता के बावजूद रिट शक्तियों का प्रयोग अधिनियमित तरीके से नहीं किया जाना चाहिए, जो रिट याचिका में आक्षेपित कार्रवाई को जन्म दिया है, फिर भी, **केवल यह तथ्य कि उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता ने, किसी दिए गए मामले में, उसके***

लिए उपलब्ध वैकल्पिक उपाय का अनुसरण नहीं किया है/इसे यांत्रिक रूप से इसकी बर्खास्तगी के लिए एक आधार के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह स्वयंसिद्ध है कि उच्च न्यायालयों (प्रत्येक विशेष मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए) को यह विवेकाधिकार है कि वे किसी रिट पर विचार करें या नहीं। याचिका दायर करें या नहीं। अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति के प्रयोग पर स्व-लगाए गए प्रतिबंधों में से एक जो न्यायिक पूर्व निर्णय द्वारा से विकसित हुआ है, वह यह है कि उच्च न्यायालयों को आम तौर पर एक रिट याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए, जहां एक प्रभावी और प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है। *साथ ही, यह याद रखना चाहिए कि अपील या संशोधन के एक वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता, जिसे अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू करने वाले पक्ष ने आगे नहीं बढ़ाया है, उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाहर नहीं करेगी और एक रिट याचिका को "बनाए रखने योग्य नहीं" बनाएगी। निर्णयों की एक लंबी पंक्ति में, इस न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एक वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता एक रिट याचिका की "पोषणीयता" के लिए एक आत्यन्तिक बाधा के रूप में काम नहीं करती है और यह कि नियम, जिसमें एक पक्ष को एक अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए वैकल्पिक उपचार को आगे बढ़ाने की आवश्यकता होती है, विधि के नियम के बजाय नीति, सुविधा और विवेक का नियम है। हालांकि प्रारंभिक, यह दोहराया जाना चाहिए कि एक रिट याचिका की "मनोरंजन" और "पोषणीयता" अलग-अलग अवधारणाएं हैं। दोनों के बीच के अच्छे लेकिन वास्तविक अंतर को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। "विचारणीयता" के बारे में आपत्ति मामले की जड़ तक जाती है और यदि ऐसी आपत्ति सारवान पाई जाती है, तो अदालतें निर्णय के लिए प्रास करने में भी असमर्थ हो जाएंगी। दूसरी ओर, "मनोरंजन" का प्रश्न पूरी तरह से उच्च न्यायालयों के विवेकाधिकार के दायरे में है, रिट उपचार विवेकाधीन है। पोषणीयता योग्य होने के बावजूद एक रिट याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा कई कारणों से विचार नहीं किया जा सकता है या*

एक ठोस विधिक बिंदु स्थापित करने के बावजूद याचिकाकर्ता को राहत देने से भी इनकार किया जा सकता है, यदि दावा की गई राहत देने से सार्वजनिक हित आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा एक रिट याचिका को इस आधार पर खारिज करना कि याचिकाकर्ता ने वैकल्पिक उपाय का लाभ नहीं उठाया है, हालांकि, यह जांच किए बिना कि क्या इस तरह के मनोरंजन के लिए एक असाधारण मामला बनाया गया है, उचित नहीं होगा।

*8. इसके अलावा, हम उपयोगी रूप से (1977) 2 एस.सी.सी. 724 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम इंडियन ब्लूम पाइप कंपनी लिमिटेड) और (2000) 10 एस.सी.सी. 482 (भारत संघ बनाम हरियाणा राज्य) में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के निर्णयों का भी उल्लेख कर सकते हैं। पूर्व निर्णय के एक सादे पठन पर जो दिखाई देता है वह यह है कि क्या कोई वस्तु बिक्री कर अधिनियम में प्रविष्टि के भीतर आती है, विधि का एक शुद्ध सवाल उठाती है और यदि तथ्यों की जांच अनावश्यक है, तो उच्च न्यायालय अपने विवेक से एक रिट याचिका पर विचार कर सकता है, भले ही वैकल्पिक उपाय का लाभ नहीं उठाया गया था; और, जब तक विवेक का प्रयोग अनुचित या विकृत नहीं दिखाया जाता है, तब तक यह न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। बाद के निर्णय में, इस न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दे को मूल रूप से विधिक पाया, जिसके लिए उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय की आवश्यकता होती है, अपीलकर्ता को पदानुक्रम में वैधानिक अपीलों द्वारा से रखे बिना। **उक्त से यह निर्णय निकलता है कि जहां विवाद विशुद्ध रूप से विधिक है और इसमें तथ्य के आक्षेपित प्रश्न शामिल नहीं हैं, बल्कि केवल विधि के प्रश्न शामिल हैं, तो इसका निर्णय एक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने के आधार पर रिट याचिका को खारिज करने के बजाय उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।"***

[जोर दिया गया]

124. उपरोक्त दिए गए अधिकारियों के परिप्रेक्ष्य से, विधिक स्थिति जो उभरती है वह यह है कि आम तौर पर एक उच्च न्यायालय एक रिट याचिका पर विचार नहीं कर सकता है जिसमें अनुरोध की गई राहतों का एक वैकल्पिक मंच से दावा किया जा सकता है; हालाँकि, यह स्व-लागू नियम सुविधा का है और एक उच्च न्यायालय, एक उचित परिस्थिति में, याचिकाकर्ता के लिए एक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने के बावजूद एक रिट याचिका पर विचार करने का विकल्प चुन सकता है।

125. इस न्यायालय को अब सेबी अधिनियम, 1992 के तहत अपील की प्रकृति से संबंधित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दिए गए निर्णयों पर विचार करना चाहिए।

126. ***राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड*** *(पूर्वोक्त)* में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर निर्णय लिया-क्या सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 11 (1) के तहत सेबी द्वारा जारी एक प्रशासनिक परिपत्र धारा 15न के तहत अपील का विषय हो सकता है। अपील की प्रकृति पर निर्णय देते समय, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि धारा 15न में न केवल सेबी अधिनियम, 1992, नियमों या विनियमों के तहत किए गए सेबी के आदेश द्वारा, बल्कि अधिनियम के तहत एक न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों द्वारा पीड़ित व्यक्तियों द्वारा अपील की परिकल्पना की गई है। धारा 15झ के तहत, सेबी जांच करने, संबंधित व्यक्ति को सुनवाई देने और उसके बाद जुर्माना लगाने के लिए एक न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में एक प्रभाग प्रमुख के पद से नीचे के अधिकारी को नियुक्त कर सकता है, जो सभी ऐसे अधिकारियों द्वारा किए जा रहे केवल अर्ध-न्यायिक कार्यों की ओर इशारा करते हैं।

127. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कई घोषणाओं पर विचार करने के बाद, यह अभिनिर्धारित किया गया कि सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 11(1) के लिए संदर्भित परिपत्र जैसे प्रशासनिक आदेश न्यायाधिकरण के अपीलीय अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। पैराग्राफ सं.25 में निर्णय को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

> *"यह कहा जा सकता है कि धारा 29 के तहत बनाए गए दोनों नियमों के साथ-साथ धारा 30 के तहत बनाए गए विनियमों को अधिनियम की धारा 31 के तहत संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए। अधिकारियों के दिग्दर्शन से यह स्पष्ट है कि यह अधिनियम की धारा 11 (4), 11 (ख), 11 (घ), 12 (3) और 15-I के लिए संदर्भित आदेश हैं, जो अर्ध-न्यायिक आदेश हैं, और नियमों और विनियमों के तहत बनाए गए अर्ध-न्यायिक आदेश हैं जो धारा 15न के तहत अपील का विषय हैं। अधिनियम की धारा 11 (1) के लिए संदर्भित वर्तमान मामले के तहत जारी किए गए परिपत्र जैसे प्रशासनिक आदेश स्पष्ट रूप से हमारे द्वारा उपरोक्त दिए गए कारणों से न्यायाधिकरण के अपीलीय अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। इसलिए, 2007 की दीवानी याचिका सं 186 को अनुमति दी गई है और प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष ली गई प्रारंभिक आपत्ति कायम है। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय को तदनुसार अपास्त कर दिया जाता है।"*

128. इसके अलावा, ***एच.बी. स्टॉकहोल्डिंग्स लिमिटेड*** *(पूर्वोक्त)* के मुद्दे पर अपील की पोषणीयता पर, यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई संचार या निर्णय धारा 15न के अर्थ के भीतर एक आदेश के बराबर है, इसके सार को देखना होगा न कि इसके रूप को। यदि कोई विशेष निर्देश, अनुरोध या अवलोकन बाध्यकारी है और इसके उल्लंघन के लिए दंडात्मक परिणाम हैं, तो इसे एक आदेश के रूप में माना जाएगा।

129. इसके बाद, ***राधा कृष्ण इंडस्ट्रीज, हि.प्र. राज्य*** *(पूर्वोक्त)*, ***जशभाई मोतीभाई*** *(पूर्वोक्त)*, ***रामप्रसाद सोमानी*** *(पूर्वोक्त)*, वैकल्पिक उपचार के नियम के अपवादों और विधिक उल्लंघन के अधिस्थिति को विस्तार से बताएँ।

130. ***रामप्रसाद सोमानी*** *(पूर्वोक्त)* में एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष का उल्लेख करना उचित है, क्योंकि "व्यथित व्यक्ति" शब्दों का अर्थ जैसा कि वे सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 15न में दिखाई देते हैं, कहीं भी परिभाषित नहीं हैं और उनका अर्थ उस संदर्भ में लगाया जाना चाहिए जिसमें वे दिखाई देते हैं, और उन्हें इस बात पर विचार करते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए कि क्या किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, जो चिंता को बढ़ा रहा है।

131. पूर्ववर्ती पैराग्राफ में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्षों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय की राय है कि उक्त आदेश सही हैं याचिकाकर्ता बैंक द्वारा चुनौती नहीं दी गई। याचिकाकर्ता बैंक को उक्त आदेशों से व्यथित नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वे याचिकाकर्ता बैंक को प्रत्यर्थी सं. 3 और 4 की बंधकित रखी गई संपत्ति की नीलामी करने से नहीं रोकते हैं।

132. प्रत्यर्थी सं.1 और 2 के लिए विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वैकल्पिक उपचार का सिद्धांत वर्तमान मामले में लागू होता है, इसलिए, गलत पाया जाता है। याचिकाकर्ता बैंक उस आदेश को चुनौती नहीं दे सकता है जिससे वह व्यथित नहीं है। याचिकाकर्ता बैंक के मामले की पूरी इमारत उक्त आदेशों पर टिकी हुई है जो उन्हें बंधकित रखी गई संपत्ति की नीलामी करके अपने ऋण का भुगतान करने से नहीं रोकते हैं। इसलिए

याचिकाकर्ता बैंक ने उक्त आदेशों के बजाय 29.01.2021 और 18.03.2921 दिनांकित ई-मेलों पर आपत्ति जताई।

133. ***निवेदिता शर्मा*** *(पूर्वोक्त),* ***थानसिंह नाथमल*** *(पूर्वोक्त)* और ***महाराष्ट्र राज्य*** *(पूर्वोक्त)*, के मामले इसलिए, प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 के लिए कोई मदद नहीं करते हैं, क्योंकि उक्त मामलों में केवल उन मामलों में आवेदन होता है जहां वास्तव में, एक वैकल्पिक उपाय है जो एक याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध है। गुरदेव सिंह (पूर्वोक्त) में प्रो. वेड के शब्दों के अनुमोदन पर प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 की निर्भरता सही है, उन्हें फिर से यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है:

> *"इस मामले की सच्चाई यह है कि न्यायायलय किसी आदेश को तभी अमान्य करेगी जब सही व्यक्ति द्वारा सही कार्यवाही और परिस्थितियों में सही उपाय मांगा जाए।"*

134. वर्तमान परिस्थितियों में, इस न्यायालय की राय है कि याचिकाकर्ता बैंक सही व्यक्ति है जो सही कार्यवाही में सही उपचार की मांग कर रहा है। ***कुबेर फ्लोरिटेक लिमिटेड*** *(पूर्वोक्त)* और ***बलवीर सिंह*** *(पूर्वोक्त)* में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय तत्काल मामले में लागू नहीं होते हैं क्योंकि उपरोक्त निर्णयों में जिन आदेशों पर हमला किया गया था, वे आदेश थे, इसके अलावा न्यायालय ने संबंधित आदेशों को सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 15न के तहत अपील योग्य पाया गया।

135. इसके अलावा, ***राज कुमार शिवहरे*** *(पूर्वोक्त)*, अनुपयुक्त है क्योंकि वर्तमान मामले में उद्धृत निर्णय की तुलना में एक अलग तथ्यात्मक मैट्रिक्स है। याचिकाकर्ता बैंक इस

न्यायालय को यह समझाने में सफल रहा है कि उनके लिए वैधानिक अपील क्यों उपलब्ध नहीं है।

136. उपरोक्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि याचिकाकर्ता बैंक ने उक्त आदेशों को लागू न करने का विकल्प चुनकर कोई त्रुटि नहीं की है। याचिकाकर्ता बैंक दिनांक 29.01.2021 और 18.03.2021 के ई-मेल/संचार पर आरोप लगाता है और उक्त आदेशों को लागू नहीं करता है, जबकि उक्त आदेश बने हुए हैं, इस अदालत को वर्तमान याचिका को पोषणीय रखने योग्य से नहीं रोकता है।

137. यह भी देखा जाना चाहिए कि 29.05.2018 को ई-मेल प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा बंधकित रखी गई संपत्ति की नीलामी के लिए याचिकाकर्ता बैंक के सार्वजनिक नोटिस से उत्तेजित होने के बाद भेजा गया था। संचार, हालांकि उक्त आदेशों की आड़ में खुद को झुकाते हुए, प्रभावी रूप से याचिकाकर्ता बैंक को बंधक संपत्ति की नीलामी के साथ आगे नहीं बढ़ने का निर्देश देते हैं। इस प्रकार सरफेसी अधिनियम, 2002 द्वारा गारंटीकृत याचिकाकर्ता बैंक के वैधानिक अधिकार को आक्षेपित ई-मेल द्वारा विफल कर दिया जाता है। याचिकाकर्ता बैंक को उनके वित्तीय हित से समझौता करने के कारण पर्याप्त बाधा उत्पन्न होती है। सेबी के उप महाप्रबंधक यानी प्रत्यर्थी सं. 1 का एक ई-मेल, जो याचिकाकर्ता बैंक को अपने विधिक अधिकारों का प्रयोग करने से अनुचित रूप से रोकता है, इस रिट न्यायालय से संपर्क करने के लिए पर्याप्त कारण है।

138. इसलिए, इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि चूंकि आक्षेपित ई-मेल/संचार गलत थे और पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना थे; और उक्त आदेश याचिकाकर्ता बैंक

को बंधकित रखी गई संपत्ति की नीलामी करने से नहीं रोकते हैं, वर्तमान रिट याचिका सुनवाई योग्य है।

139. इस न्यायालय को अब उस मुद्दे पर निर्णय करना चाहिए, जिस पर इस न्यायालय के समक्ष विस्तार से बहस की गई थी कि क्या सेबी अधिनियम, 1992 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके सेबी याचिकाकर्ता बैंक को सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत कार्यवाही करने से रोक सकता है।

140. ***मद्रास पेट्रोकेम लिमिटेड*** *(उपरोक्त)* में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने सरफेसी अधिनियम, 2002, आर.डी.बी. अधिनियम, 1993 और सिक औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 (इसके पश्चात **एस.आई.सी.ए. अधिनियम, 1985**) के बीच अंतर-भूमिका पर निर्णय लिया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा तय किया गया मूलभूत प्रश्न था-क्या सेबी अधिनियम, 1985, सरफेसी अधिनियम, 2002 पर लागू होता है। यह मुद्दा धारा 37 की व्याख्या पर उत्पन्न हुआ, विशेष रूप से धारा 35 के तहत *गैर-अस्थाई* खंड के आलोक में "कुछ समय के लिए कोई अन्य कानून" अभिव्यक्ति।

141. उक्त निर्णय के पैराग्राफ सं. 13 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विवाद में शामिल विभिन्न विधियों द्वारा निपटाए गए विभिन्न पहलुओं को मान्यता दी, जिन्हें निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> *"13. इस स्तर पर इन तीन विधानों की उत्पत्ति का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है। इनमें से प्रत्येक बैंक और वित्तीय ईकाईयों को देय ऋणों की वसूली के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है। उनमें से दो लेनदारों के*

हितों का उल्लेख करते हैं और एक ओर बकाया ऋणों और उनके द्वारा किए गए अग्रिमों की वसूली से कैसे निपटना है, जबकि दूसरी ओर सिक औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 कुछ ऐसे देनदारों से संबंधित है जो सिक औद्योगिक कंपनियां हैं (यानी उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की अनुसूची में नामित उद्योग चलाने वाली कंपनियां) और क्या ऐसे "देनदार" बीमार हो गए हैं, उनका पुनर्वास किया जाना है। इसलिए सवाल यह है कि क्या बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली में सार्वजनिक हित बीमार औद्योगिक कंपनियों के पुनर्वास में सार्वजनिक हित को रास्ता देना है, जैसा कि देश में वर्तमान आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए संसदीय विधान में परिलक्षित होता है।"

142. जिस उद्देश्य के लिए सरफेसी अधिनियम, 2002 लागू हुआ, उस पर जोर देने और सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 35 और धारा 37 की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या करने के बाद, शीर्ष न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची कि धारा 37 में "कुछ समय के लिए कोई अन्य कानून" अभिव्यक्ति का दायरा सीमित करने की आवश्यकता है ताकि एस.आई.सी.ए. अधिनियम, 1985 को बाहर किया जा सके।

143. ***केएसएल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम अरिहंत थ्रेड्स लिमिटेड*** का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा किए गए संदर्भ के माध्यम से उत्पन्न हुआ, जिसमें माननीय न्यायमूर्ति सी.के. ठक्कर और माननीय न्यायमूर्ति अटलामास कबीर के बीच आर.डी.बी. अधिनियम 1993 की धारा 35 की व्याख्या पर मतभेद था। माननीय न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे ने तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ के लिए लेखन करते हुए एस.आई.सी.ए. अधिनियम, 1985 और आर.डी.बी. अधिनियम, 1993 के बीच संघर्ष को एस.आई.सी.ए. अधिनियम, 1985 के पक्ष में एक

निष्कर्ष देकर हल किया। पैराग्राफ संख्या 37-41 में निर्णय को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

> ***<u>"37. उप-धारा (2) को 2000 के अधिनियम संख्या 1 द्वारा 17.01.2000 से आर.डी.डी.बी. अधिनियम की धारा 34 में जोड़ा गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब कोई अधिनियम, जैसा कि यहाँ, यह प्रावधान करता है कि उसके प्रावधान किसी अन्य विधि या विधियों के अतिरिक्त होंगे और उनका अल्पीकरण नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है कि विधानमंडल का इरादा है कि ऐसा अधिनियम अन्य अधिनियमों के साथ सह-अस्तित्व में होगा। स्पष्ट रूप से ऐसे मामले में विधानमंडल का इरादा अन्य विधियों के प्रावधानों को रद्द करने या उनसे अलग करने का नहीं है। "अल्पीकरण में" शब्द का अर्थ है "निराकरण या निरसन में"। ब्लैक लॉ डिक्शनरी "अल्पीकरण" के लिए निम्नलिखित अर्थ निर्धारित करती है:</u>***
>
> *पश्चातवर्ती कार्य द्वारा किसी विधि का आंशिक निराकारण या निरसन करना जो इसके दायरे को सीमित करता है या इसकी उपयोगिता और बल को कम करता है।*
>
> ***यह स्पष्ट है कि उप-धारा (1) में एक गैर-अस्थाई खंड है, जो आर.डी.डी.बी. अधिनियम को प्रमुख प्रभाव देता है। उप-धारा (2) ऐसे प्रबलकारी प्रभाव के लिए अपवाद की प्रकृति में कार्य करती है।** इसमें कहा गया है कि यह अधिभावी प्रभाव कुछ विधियों के संबंध में है और यह कि आर.डी.डी.बी. अधिनियम ऐसी विधियों के अतिरिक्त होगा और निरस्त नहीं होगा। **एस.आई.सी.ए. निस्संदेह ऐसी ही विधि है।***
>
> ***<u>38. उप-धारा (2) का प्रभाव अनिवार्य रूप से एस.आई.सी.ए. के तहत प्राधिकरणों की शक्तियों को संरक्षित करने और बाद के अधिनियम अर्थात आर.डी.डी.बी. अधिनियम द्वारा अधिभावी की जाने वाली कार्यवाही है।</u>***

39. इस प्रकार, हम एस.आई.सी.ए. के तहत कंपनी के पुनर्निर्माण की कार्यवाही के संबंध में एक सामंजस्यपूर्ण योजना पाते हैं, जिसमें ऋणों का पुनर्निर्माण और यहां तक कि इस उद्देश्य के लिए बीमार कंपनी की संपत्तियों की बिक्री या पट्टा भी शामिल है, जो एक ओर बैंक या वित्तीय संस्थान के पक्ष में बीमार कंपनी द्वारा निष्पादित प्रतिभूति का हिस्सा हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, और आर.डी.डी.बी. अधिनियम के प्रावधान, जो बैंक या वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली से संबंधित हैं, यदि आवश्यक हो, तो बैंक या वित्तीय संस्थान से प्रभारित प्रतिभूति को लागू करके।

40. इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोनों विशेष विधि हैं। एस.आई.सी.ए. एक विशेष विधि है, जो बीमार कंपनियों के पुनर्निर्माण और उससे संबंधित मामलों से संबंधित है, हालांकि यह ऋण की वसूली जैसे अन्य मामलों के संबंध में सामान्य है। आर.डी.डी.बी. अधिनियम भी एक विशेष विधि है, जो एक विशेष प्रक्रिया द्वारा से बैंकों या वित्तीय संस्थानों को देय धन की वसूली से संबंधित है, हालांकि यह बीमार कंपनियों के पुनर्निर्माण जैसे अन्य मामलों के संबंध में सामान्य हो सकता है, जिनसे वह विशेष रूप से निपटता भी नहीं है। इस प्रकार, दोनों विधियों का उद्देश्य अलग है।

41. यह माना जाना चाहिए कि संसद को आर.डी.डी.बी. अधिनियम, 1993 को लागू करते समय 1985 में अधिनियमित पूर्व विधि अर्थात एस.आई.सी.ए. की जानकारी थी। प्रक्रिया के टकराव को रोकने और उसी इकाई और उसकी संपत्तियों के संबंध में विरोधाभासी आदेशों की संभावना को रोकने के लिए, और विशेष रूप से, ऐसी बीमार कंपनी की संपत्तियों के संबंध में पुनर्निर्माण के लिए पहले से ही उठाए गए कदमों को संरक्षित करने के लिए, जिन पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों के साथ प्रतिभूति के रूप में प्रभार लगाया जा सकता है, कि संसद ने विशेष रूप से उप-धारा (2) को अधिनियमित किया है। एस.आई.सी.ए. को निर्दिष्ट और सीमित कंपनियों के संबंध में अधिनियमित किया गया था, अर्थात

वे जो आई.डी.आर. अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट औद्योगिक उपक्रमों के मालिक थे, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, जबकि आर.डी.डी.बी. अधिनियम उन सभी व्यक्तियों से संबंधित है, जिन्होंने बैंक या वित्तीय संस्थान से नकद या अन्यथा ऋण लिया हो सकता है, चाहे वह सुरक्षित हो या असुरक्षित आदि।"

[जोर दिया गया]

144. हालांकि, ***केएसएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड*** *(पूर्वोक्त)* का निर्णय अलग है। जैसा कि अनुच्छेद सं. में उल्लेख किया गया है। जैसा कि ***मद्रास पेट्रोकेम लिमिटेड*** (पूर्वोक्त) के पैराग्राफ सं. 35 में उल्लेख किया गया था, आर.डी.बी. अधिनियम, 1993 की धारा 34 (1) में निहित गैर-अस्थाई खंड स्पष्ट रूप से एक उत्कीर्ण के लिए प्रदान करता है, और खुद को धारा 34 (2) के अधीन बनाता है। सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 35 में निहित गैर-अस्थाई खंड के मामले में ऐसा नहीं है। यह आर.डी.बी. अधिनियम, 1993 और सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है क्योंकि यह गैर-अस्थाई खंड के दायरे को प्रभावित करता है, और इसका प्रभाव होगा। अंतर को बेहतर ढंग से समझने के लिए, प्रावधानों को पुन: प्रस्तुत किया जाता है।

145. आर.डी.बी. अधिनियम, 1993 की धारा 34 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

*"34. अधिनियम का अधिभावी प्रभाव होगा।— **(1) उप-धारा (2) के तहत दिए गए प्रावधानों को छोड़कर,** इस अधिनियम के प्रावधान इस अधिनियम के अलावा किसी भी विधि के आधार पर प्रभावी होने वाले किसी भी अन्य विधि में या किसी भी उपकरण में निहित कुछ असंगत के होते हुए भी प्रभावी होंगे।*

(2) इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधान औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (15/1948), राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (63/1951), भारतीय इकाई न्यास अधिनियम, 1963 (52/1963), भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक अधिनियम, 1984 (62 /1984) (बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 (1/1986) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (39/1989) के अतिरिक्त होंगे और उनका अल्पीकरण नहीं करेंगे।"

[जोर दिया गया]

146. सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 35 और 37 निम्नानुसार है:

"35. इस अधिनियम के प्रावधान अन्य विधियों को अधिभावी करते हैं। — इस अधिनियम के प्रावधानों का प्रभाव होगा, भले ही उस समय लागू किसी अन्य विधि या किसी ऐसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी दस्तावेज में कुछ भी असंगत हो।"

"37. अन्य विधियों का प्रयोग वर्जित नहीं है। *— इसके प्रावधान अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियम कंपनी अधिनियम, 1956 (1/1956), प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (42/1956), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (15/1992), बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993 (51/1993) या उस समय लागू किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे और उनका अल्पीकरण नहीं करेंगे।"*

[जोर दिया गया]

147. ***मद्रास पेट्रोकेम लिमिटेड*** (पूर्वोक्त) के पैराग्राफ सं. 35 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सरफेसी अधिनियम, 2002 और आर.डी.बी. अधिनियम, 1993 में

निहित गैर-अस्थाई खंडों के दायरे और दायरे से संबंधित महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नानुसार है:

> ***"35. इसी निष्कर्ष का एक और दिलचस्प संकेत यह तथ्य है कि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 35 को उक्त अधिनियम की धारा 37 के अधीन नहीं बनाया गया है। यह सांविधिक योजना बैंकों और वित्तीय संस्थानों के देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 34 में निहित सांविधिक योजना से पूरी तरह से भिन्न है, जिसमें धारा 34 की उप-धारा (1) को स्पष्ट रूप से उप-धारा (2) (जिसमें बीमार औद्योगिक कंपनियां (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 शामिल है) के अधीन "उप-धारा (2) के तहत प्रदान किए गए प्रावधान को छोड़कर" अभिव्यक्ति द्वारा बनाया गया है।"***
>
> *[जोर दिया गया]*

148. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि आर.डी.बी. अधिनियम, 1993 के गैर-अस्थाई प्रावधान का प्रभाव धारा में प्रदान किए गए उपरिका द्वारा स्पष्ट रूप से कम कर दिया गया है, यह उप-धारा (2) के लिए उत्कीर्ण है। उप-धारा (2) के लिए यह बचत इस तरह से की जाती है कि गैर-अस्थाई खंड के प्रभाव को कम किया जाए। इसके बाद उप-धारा (2) की व्याख्या कम किए गए गैर-अस्थाई खंड के आलोक में की जाती है। दूसरे शब्दों में, उपधारा (2) का विवेक्षण करते समय, अर्थात्, धारा 34 (1) में निहित गैर-अल्पीकरण प्रावधान, गैर-अस्थाई खंड का कोई अनुप्रयोग नहीं है। यह मामला सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत नहीं है। सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 35 में निहित गैर-अस्थाई खंड को धारा 37 के अधीन नहीं बनाया गया है। इसके बाद सरफेसी

अधिनियम, 2002 की धारा 37 का अर्थ धारा 35 के तहत निरंकुश गैर-अस्थाई खंड के आलोक में लगाया जाना चाहिए।

149. ***मैथ्यू वर्गीज*** *(पूर्वोक्त)* में, माननीय उच्चतम न्यायालय को सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 37 में "अल्पीकरण में नहीं" अभिव्यक्ति के अर्थ और इसके प्रभाव पर विचार करने का अवसर मिला था। पैराग्राफ सं.43 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार कहा:

> *"43. धारा 37 के अध्ययन से पता चलता है कि सरफेसी अधिनियम का अनुप्रयोग आर.डी.डी.बी. अधिनियम के प्रावधानों के अतिरिक्त होगा न कि अल्पीकरण में। दूसरे शब्दों में, यह किसी भी तरह से आर.डी.डी.बी. अधिनियम के प्रावधानों के प्रभाव को रद्द या क्षीण नहीं करेगा।* ***हम विधि के अपने उपरोक्त कथन से भी दृढ़ीकृत हैं*** *क्योंकि उक्त धारा का शीर्षक भी स्थिति को स्पष्ट करता है कि अन्य विधियों के आवेदन पर रोक नहीं है। इसलिए, धारा 37 का प्रभाव यह होगा कि सरफेसी अधिनियम के तहत निहित प्रावधानों के अलावा, उक्त अधिनियम के तहत शुरू की गई कार्यवाही के संबंध में, यह एक पक्ष के लिए धारा 37 में उल्लिखित अन्य अधिनियमों के प्रावधानों पर वापस आने के लिए होगा, अर्थात्, कंपनी अधिनियम, 1956, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम 1956, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992, बैंकों और वित्त संस्थानों के कारण ऋण की वसूली अधिनियम, 1993, या किसी अन्य विधि को लागू करने के लिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के तहत दायर किया गया है।*
>
> *[जोर दिया गया]*

150. हाल ही में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***अधिकृत अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक बनाम सी नटराजन और अन्य*** के मामले में, सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा

35 और धारा 37 के बीच परस्पर क्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिए। उक्त निर्णय के पैराग्राफ सं. 23 का महत्वपूर्ण भाग निम्नानुसार है:

> *"23. इसके अलावा, महत्वपूर्ण रूप से, सरफेसी अधिनियम की धारा 35 में कहा गया है कि उसके प्रावधान प्रभावी होंगे, इसके बावजूद कि किसी अन्य विधि में निहित कुछ भी असंगत है या ऐसे किसी भी विधि के आधार पर प्रभावी है।* ***साथ ही, सरफेसी अधिनियम की धारा 37 में कहा गया है कि इसके प्रावधान या इसके तहत बनाए गए नियम गणना किए गए अधिनियमों या उस समय लागू किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे और उनका अल्पीकरण नहीं करेंगे।*** ***<u>महत्वपूर्ण बात यह है कि सरफेसी अधिनियम की धारा 35 में गैर-अस्थाई खंड उसकी धारा 37 के अधीन नहीं है।</u>*** *हालांकि, बाद के प्रावधान के एक सादे अध्ययन से पता चलता है कि सरफेसी अधिनियम और नियमों द्वारा बनाए गए/लगाए गए/प्रदान किए गए अधिकार, देनदारियां, दायित्व, उपचार, आदि को संरक्षित किया जाता है, भले ही उक्त अधिनियमों या किसी अन्य विधि में क्या प्रदान किया गया हो।* सरफेसी अधिनियम के तहत व्यवस्था पूरी तरह से अलग है और धारा 35 और 37 का उद्देश्य सुरक्षित लेनदार को एक सुरक्षा प्रदान करना है यदि वह शासी विधि का पालन करता है, जो अनुबंध अधिनियम जैसे सामान्य विधि के किसी अन्य प्रावधान के अधीन नहीं हो सकता है। चूँकि धारा 35 उसी या संबंधित क्षेत्र में अन्य विधियों को अभिभावी करती है और सरफेसी अधिनियम की योजना और प्राप्त किए जाने वाले प्रमुख उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि उपरोक्त उल्लेख किया गया है, किसी को भी इसके तहत आयोजित नीलामी को हल्के में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। किसी भी न्यायालय को बोली लगाने वाले को अपनी मर्जी से प्रक्रिया में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए बिना किसी वास्तविक इरादे के स्वीकार नहीं करना चाहिए। नियम 9 के उप-नियम (5) को अर्थ देने के लिए दिए गए मामले के संदर्भ में सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ नियमों की सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की जानी*

चाहिए। इसके अतिरिक्त, हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि सामान्य विधि, यानी अनुबंध अधिनियम और विशेष विधि, यानी सरफेसी अधिनियम के बीच किसी भी प्रतीत होने वाले संघर्ष या विसंगति के मामले में, यह बाद वाला है जो प्रबल होगा।"

[जोर दिया गया]

151. ***डेविस*** (पूर्वोक्त) के मामले में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का निर्णय, जिस पर प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किया गया था, पर अब सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। उद्धृत मामले में मुद्दा वर्तमान मामले पर पूरी तरह से लागू नहीं है, हालांकि, तर्क पर अभी भी ध्यान दिया जा सकता है। लॉर्ड मैकमिलन द्वारा तैयार किया गया सामान्य प्रश्न यह था:

"... चाहे मृतक के किसी आश्रित को घातक दुर्घटना अधिनियम, 1846 से 1908 के तहत देय नुकसान का आकलन करने में, विधि सुधार (विविध प्रावधान) अधिनियम, 1934 के तहत नुकसान में भाग लेने से उस आश्रित को मिलने वाले किसी भी लाभ को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

152. विधि सुधार (विविध प्रावधान) अधिनियम, 1934 के तहत प्रावधान, जो कुछ हद तक सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 37 के समान है, निम्नानुसार है:

"मृतक व्यक्तियों के राज्यों के लाभ के लिए इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकार घातक दुर्घटना अधिनियम, 1846 से 1908 द्वारा मृतक व्यक्तियों के आश्रितों को प्रदान किए गए किसी भी अधिकार के अतिरिक्त होंगे और उनका अल्पीकरण नहीं करेंगे"।

153. उपर्युक्त प्रावधान की व्याख्या पर, लॉर्ड रसेल ने निम्नलिखित रूप में उल्लेख किया:

"यह दोहरे वाक्यांश से कुछ विशेष अर्थ निकालने की कोशिश की गई थी "इसके अलावा होगा और इसका अल्पीकरण नहीं होगा।" यह कहा गया था कि यह पुनरावृत्ति मात्र नहीं था, बल्कि जानबूझकर संचयी था; और "अल्पीकरण में नहीं" शब्दों में एक निर्देश शामिल था कि घातक दुर्घटना अधिनियमों के तहत प्राप्त नुकसान से कोई कटौती या कमी नहीं की जानी चाहिए। अपने लिए मैं इस सूक्ष्म छिपे हुए अर्थ को उपखंड में पढ़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं देख सकता। मैं अपीलीय न्यायालय से सहमत हूं कि "और अल्पीकरण में नहीं" शब्द केवल उस बात पर जोर देते हैं जो पहले ही कहा जा चुका है, कि एक अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकार अन्य अधिनियमों द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अतिरिक्त हैं, और उस हद तक स्वतः संज्ञानात्मक हैं।"

154. यदि उपरोक्त आदेश लागू किया जाता है, तो सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत प्रदान किए गए अधिकार सेबी अधिनियम, 1992 के तहत प्रदान किए गए अधिकारों के अलावा पाए जाते हैं। हालाँकि, ***डेविस*** *(पूर्वोक्त)* में, दो विधि जिनके साथ उनके प्रभुता का संबंध था, वे जटिल रूप से जुड़े हुए थे। वर्तमान विवाद में, यह पता लगाने में कठिनाई उत्पन्न होगी कि कैसे एक बैंक जो सरफेसी अधिनियम, 2002 की प्रक्रिया के तहत अपने ऋणों का भुगतान करना चाहता है, वह सेबी अधिनियम, 1992 की सहायता ले सकता है। यह कठिनाई तब उत्पन्न नहीं हो सकती है जब प्रश्न आर.डी.बी. अधिनियम, 1993 और सरफेसी अधिनियम, 1992 के बीच परस्पर क्रिया से संबंधित हो। वास्तव में ऐसे परिदृश्य में सरफेसी अधिनियम, 1992 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को आर.डी.बी. अधिनियम, 1993 के तहत अधिकारों के अतिरिक्त कहा जा सकता है।

155. हालांकि, लॉर्ड रसेल की राय में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस न्यायालय को सेबी अधिनियम, 1992 को अभिभावी के रूप में समझने की अनुमति देता है और सरफेसी

अधिनियम, 1992 के तहत बैंकों द्वारा कार्यवाही और कार्यों को रोकता या विफल करता है।

156. प्रावधान के निर्माण के मुद्दे पर लॉर्ड मैकमिलन की भी यही राय है। महत्वपूर्ण भाग निम्नानुसार है:

> *"उस प्रावधान की व्याख्या पर जो मैंने अभी उद्धृत की है, मैं खुद को अपीलीय न्यायालय में लॉर्ड्स के न्यायाधीशों और आपके सभी लॉर्डशिप के साथ सहमत पाता हूं। मृत व्यक्तियों की संपदाओं के लाभ के लिए विधि सुधार अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकार ऐसे मृत व्यक्तियों की मृत्यु के बाद बनाए रखने के अधिकार हैं जो कार्रवाई के सभी कारण उनमें निहित हैं। ये अधिकार घातक दुर्घटना अधिनियमों द्वारा मृतक व्यक्तियों के आश्रितों को प्रदान किए गए किसी भी अधिकार के अतिरिक्त होने चाहिए न कि अल्पीकरण में। इसका मतलब है, जैसा कि मैं शब्दों को पढ़ता हूं, कि किसी मृत व्यक्ति की मृत्यु पर यह विधि सुधार अधिनियम और घातक दुर्घटना अधिनियम दोनों के तहत कार्रवाई करने के लिए सक्षम होगा। दोनों मामलों में कार्रवाई के अधिकार काफी अलग और स्वतंत्र हैं। विधि सुधार अधिनियम के तहत कार्रवाई का अधिकार मृतक की संपत्ति के लाभ के लिए है। घातक दुर्घटना अधिनियमों के तहत कार्रवाई का अधिकार मृतक के आश्रितों के लाभ के लिए है। चूंकि कार्रवाई के दोनों कारणों का आधार समान हो सकता है, अर्थात् किसी तीसरे पक्ष की लापरवाही जिसके कारण मृतक की मृत्यु हुई है-यह प्रावधान करना स्वाभाविक था कि कार्रवाई का अधिकार एक दूसरे के प्रति पूर्वाग्रह के बिना होना चाहिए। प्रावधान को पढ़ने के लिए यह काफी अलग बात है कि, घातक दुर्घटना अधिनियमों के तहत आश्रितों को देय नुकसान का आकलन करने में, किसी भी लाभ का कोई हिसाब नहीं लिया जाना है जो आश्रित अप्रत्यक्ष रूप से मृतक*

की संपत्ति में भागीदारी के माध्यम से विधि सुधार अधिनियम के तहत एक पुरस्कार से प्राप्त कर सकते हैं।

157. सामान्य प्रस्ताव के रूप में यह कहना मुश्किल होगा कि सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत कार्यवाही का कारण बनने वाली और सेबी अधिनियम, 1992 के तहत कार्रवाई शुरू करने वाली वाद हेतुक कारण एक ही है। हालांकि, यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि कार्रवाई के अधिकार काफी अलग और स्वतंत्र हैं। वे आगे परिसंपत्तियों के एक ही समूह पर लागू हो सकते हैं। तब जो मुद्दा उठता है वह यह है कि ***डेविस*** (पूर्वोक्त) के तहत, कार्यों के दो अलग-अलग अधिकार, शायद ही कभी हो सकते हैं, अगर यह एक संभावना हो सकती है, तो एक दूसरे के साथ भिन्नता पर आते हैं; वर्तमान विवाद के तहत, इसके लिए एक गंभीर संभावना है। उदाहरण के लिए, यदि वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता बैंक के खिलाफ एक निर्देश था कि वे इस तरह से कार्य नहीं कर रहे हैं, कि प्रत्यर्थी सं. 3 और 4 की संपत्ति अन्यसंक्रांत हो जाए, तो स्थायी आदेश याचिकाकर्ता बैंक को बंधकित संपत्ति को समाप्त करके अपने ऋण की वसूली में बाधा के रूप में कार्य कर सकता है।

158. ऐसे परिदृश्य में यह मुद्दा बन जाता है कि क्या सेबी के सामान्य आदेश या सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत कार्यवाही को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 35 में निहित अनियंत्रित गैर-अस्थाई खंड के आलोक में; जिसे सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 37 के अधीन नहीं बनाया गया है, यह न्यायालय पाता है कि सेबी अधिनियम, 1992 को सरफेसी अधिनियम, 2002 को स्थान देना चाहिए।

159. ***बिक्रम चटर्जी*** (पूर्वोक्त) पर प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा रखी गई निर्भरता मुख्य रूप से गलत है क्योंकि - सबसे पहले, रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 से संबंधित मामला, और वर्तमान मामले में मुद्दा अलग है, इसी तरह ***बिक्रम चटर्जी*** (पूर्वोक्त) के तथ्य मौलिक रूप से अलग हैं। वर्तमान मामले में, यह न्यायालय एक संशोधन के माध्यम से डाले गए मोटे तौर पर गैर-अस्थाई खंड वाले एक खंड की व्याख्या से चिंतित है, और इसका असर सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 37 पर होगा जिसमें उल्लेख और आदेश दिए गए हैं, यह अधिनियम सेबी अधिनियम, 1992 का अल्पीकरण नहीं होगा। दूसरा, ***बिक्रम चटर्जी*** *(पूर्वोक्त)* में तथ्यात्मक मैट्रिक्स बैंकों की ओर से धोखाधड़ी के दावे को दर्शाता है, जो वर्तमान मामले में अनुपस्थित है।

160. ***उप निदेशक प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली*** *(पूर्वोक्त)*, ***बैंक ऑफ बड़ौदा*** *(पूर्वोक्त)*, ***सॉलिडेयर इंडिया लिमिटेड*** *(पूर्वोक्त)* के मामले फिर से अनुपयुक्त पाए जाते हैं क्योंकि वर्तमान मामले में गैर-अस्थाई खंड वाली दो विधियों के बीच एक सरल संघर्ष मौजूद नहीं है। यह न्यायालय सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 37 की व्याख्या से संबंधित है, जिसमें उल्लेख किया गया है और अधिनियम को सेबी अधिनियम, 1992 के अवमूल्यन में नहीं होना चाहिए, और बाद में सामंजस्यपूर्ण व्याख्या की आवश्यकता है। ***एस.आई.सी.ओ.एम. लिमिटेड*** *(पूर्वोक्त)* फिर से लागू नहीं है क्योंकि वर्तमान मामले में बंधकित संपत्ति पर सेबी के अधिकारों और हितों को सरल शब्दों में असुरक्षित लेनदार नहीं कहा जा सकता है।

161. इसके अतिरिक्त, उक्त निर्णयों को ***पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन पी लिमिटेड*** (पूर्वोक्त) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की घोषणा के आलोक में भी महत्व दिए जाने की आवश्यकता है, जो आगे ***मद्रास पेट्रोकेम लिमिटेड*** (पूर्वोक्त) में लागू होता है। ***मद्रास पेट्रोकेम लिमिटेड*** (पूर्वोक्त) के पैराग्राफ सं. 51 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन*** (पूर्वोक्त) के अनुपात को निम्नलिखित शब्दों में समझाया:

> *"51. पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड और अन्य (सिविल अपील सं. 3646/2011) में इस न्यायालय के एक हालिया निर्णय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक निर्णय से सहमति व्यक्त की है, और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक निर्णय को अस्वीकार करते हुए कहा है कि कंपनी अधिनियम के तहत अधिकारिता का प्रयोग करने वाली कंपनी न्यायालय, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत ऐसे लेनदार को उपलब्ध शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री के संबंध में कोई नियंत्रण नहीं है।* ***इस न्यायालय द्वारा की गई कुछ टिप्पणियां दिलचस्प हैं कि इस न्यायालय ने माना है कि प्रतिभूतिकरण अधिनियम अपने आप में एक पूर्ण संहिता है, और राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 या बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के संदर्भ में दिए गए पहले के निर्णयों को प्रतिभूतिकरण अधिनियम पर लागू नहीं माना जा सकता है।*** *इसके अलावा, प्रतिभूतिकरण अधिनियम में कंपनी अधिनियम के कुछ प्रावधानों को शामिल करना ही कंपनी अधिनियम की धारा 529क के तहत श्रमिकों के ऋणों के संबंध में कंपनी अधिनियम के साथ बाद वाले अधिनियम को सुसंगत बनाता है"।*
>
> *[जोर दिया गया]*

162. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा गुण-दोष पर विचार किए जाने वाले मामलों के अलावा, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में यह भी प्रावधान है कि सरफेसी अधिनियम, 2002 के अलावा अन्य विधियों से संबंधित निर्णयों का बहुत अधिक प्रेरक मूल्य नहीं है।

163. इसलिए, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 35 सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 37 के अधीन नहीं है। ऐसे मामले में गैर-अस्थाई खंड के प्रभाव को कम नहीं किया जा सकता है।

164. वर्तमान तथ्यात्मक परिदृश्य में, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि दोनों विधियां अपने-अपने क्षेत्रों में काम करते हैं।

165. सरफेसी अधिनियम, 2002 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण का महत्वपूर्ण भाग निम्नानुसार है:

"वित्तीय परिसंपत्तियों की सुरक्षा और पुनर्गठन और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 का प्रवर्तन

(अधिनियम सं. 54/2002)

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

अपनी अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास में सफलता प्राप्त करने के भारत के प्रयासों में वित्तीय क्षेत्र प्रमुख चालकों में से एक रहा है। जबकि भारत में बैंकिंग उद्योग उत्तरोत्तर अंतर्राष्ट्रीय विवेकपूर्ण मानदंडों और लेखा प्रथाओं का पालन कर रहा है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के पास दुनिया के वित्तीय बाजारों में अन्य प्रतिभागियों की तुलना में समान अवसर नहीं है। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय बैंकों के विपरीत,

*भारत में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास प्रतिभूतियों का कब्जा लेने और उन्हें बेचने की शक्ति नहीं है। **वाणिज्यिक लेन-देन से संबंधित हमारे मौजूदा विधिक ढांचे ने बदलती वाणिज्यिक प्रथाओं और वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के साथ तालमेल नहीं रखा है। इसके परिणामस्वरूप ऋणों की वसूली की गति धीमी हुई है और बैंकों और वित्तीय संस्थानों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों का स्तर बढ़ गया है।***

*...इन समितियों ने अन्य **बातों के साथ-साथ प्रतिभूतिकरण के लिए एक नई विधि बनाने और बैंकों और वित्तीय संस्थानों को प्रतिभूतियों का कब्जा लेने और न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना उन्हें बेचने के लिए सशक्त बनाने का सुझाव दिया है।"***

[जोर दिया गया]

166. सेबी अधिनियम, 1992 का उद्देश्य खंड इस प्रकार है:

"प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देने और उसे विनियमित करने और उससे जुड़े या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए एक बोर्ड की स्थापना का प्रावधान करने के लिए एक अधिनियम"।

167. इस प्रकार यह देखा जाता है कि दोनों अधिनियम अलग-अलग क्षेत्रों में कार्य करते हैं। जबकि सरफेसी अधिनियम, 2002 को अधिनियम के तहत बैंकों द्वारा पंजीकृत प्रतिभूतियों की तेजी से प्राप्ति की अनुमति देने के लिए अधिनियमित किया गया था; दूसरी ओर, सेबी अधिनियम, 1992, निवेशकों की सुरक्षा के लिए संसद के इरादे को प्रकट करता है, और प्रतिभूति बाजार को विनियमित करने के लिए सेबी को शक्तियां प्रदान करता है। विनियमन की प्रक्रिया में, सेबी अन्य बातों के साथ-साथ उन व्यक्तियों

को निर्देश जारी कर सकता है, जो बाजार के हित के विपरीत स्वयं या अपना व्यवसाय करते पाए जाते हैं।

168. जैसा कि वर्तमान मामले में है, याचिकाकर्ता बैंक की कार्रवाई पूरी तरह से उक्त आदेशों के विषय-वस्तु से असंबद्ध है। याचिकाकर्ता बैंक अपनी सुरक्षित परिसंपत्ति को वसूलने का प्रयास कर रहा है, जो कि प्रत्यर्थी सं. 3 और 4 द्वारा लिए गए ऋण के लिए याचिकाकर्ता बैंक के पक्ष में बंधक है। बंधक रखी गई संपत्ति, न तो प्रतिभूति बाजार के संदर्भ में एक प्रतिभूति है और न ही ऐसी प्रतिभूति से जुड़ी है, और न ही विशेष रूप से सेबी अधिनियम, 1992 द्वारा शासित नहीं है। इसलिए, वर्तमान मुद्दे में एक कार्यात्मक पहलू है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है। सेबी और उक्त आदेश उस क्षेत्र से अलग क्षेत्र में कार्य करते हैं जिसमें याचिकाकर्ता बैंक ने सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत अपनी कार्रवाई की है।

169. विधियों की योजना से पता चलेगा कि वर्तमान मामले के समान तथ्यों और परिस्थितियों में, बैंकों को अपनी सुरक्षा का एहसास करने की अनुमति देने के लिए एक उत्कीर्ण किया जा सकता है, जिसे उन्होंने वैधानिक रूप से निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से पंजीकृत किया था। वास्तव में ऐसे मामले में, सरफेसी अधिनियम, 2002 का संचालन विशिष्ट विधि है जो एक निर्दिष्ट सुरक्षित ऋण पर लागू होता है, जबकि सेबी अधिनियम, 1992 के तहत निर्देश, जो परिसंपत्तियों के अपव्यय या अलगाव को रोकते हैं, परिसंपत्तियों के एक व्यापक समूह पर लागू सामान्यीकृत विधि है।

170. इस तरह के सामंजस्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि दोनों प्रावधानों को एक-दूसरे के साथ सीधे टकराव में आने से रोका जा सके। उक्त सिद्धांत का उल्लेख जी.पी. सिंह के प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्यूटरी इंटरप्रिटेशन 15 वें संस्करण, पृष्ठ 111 में किया गया है:

> *"यह पहले ही देखा जा चुका है कि एक अधिनियम को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और अधिनियम के एक प्रावधान का अर्थ उसी अधिनियम के अन्य प्रावधानों के संदर्भ में लगाया जाना चाहिए ताकि पूरे अधिनियम को सुसंगत रूप से लागू किया जा सके। इस तरह के निर्माण में किसी धारा के भीतर या किसी धारा और अधिनियम के अन्य हिस्सों के बीच किसी भी विसंगति या प्रतिकूलता से बचने का गुण है। यह न्यायालयों का कर्तव्य है कि वे एक ही अधिनियम की दो धाराओं के बीच "आमने-सामने टकराव" से बचें और "जब भी ऐसा करना संभव हो, उन प्रावधानों का अर्थ निकालें जो परस्पर विरोधी प्रतीत हों ताकि उनमें सामंजस्य हो"।*
>
> ...
>
> *यह हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए कि "संसद ने एक हाथ से वह दिया था जो उसने दूसरे हाथ से छीन लिया था।" अधिनियम की एक धारा के प्रावधानों का उपयोग दूसरे के प्रावधानों को हराने के लिए तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उनके बीच सुलह करना असंभव न हो। यही नियम किसी धारा की उप-धाराओं के संबंध में लागू होता है। न्या. गजेंद्रगडकर के शब्दों में:*
>
> > ***"दोनों उप-धाराओं को एक अभिन्न समग्र के भागों के रूप में और एक दूसरे पर निर्भर होने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए; यदि ऐसा करना उचित रूप से संभव है, तो उन्हें सामंजस्य स्थापित करने और विरोध से बचने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए"।***

जैसा कि न्या. वेंकटरामा अय्यर ने कहा है,

> ***"निर्माण का नियम अच्छी तरह से तय किया गया है कि जब किसी अधिनियम में दो प्रावधान हैं जिनका एक-दूसरे के साथ मिलान नहीं किया जा सकता है, तो उनकी व्याख्या इस तरह की जानी चाहिए कि, यदि संभव हो, तो दोनों को प्रभाव दिया जाना चाहिए।इसे सामंजस्यपूर्ण निर्माण के नियम के रूप में जाना जाता है।***

दोनों को यह प्रभाव दिया जाना चाहिए, यही नियम का सार है। इस प्रकार, एक निर्माण जो प्रावधानों में से एक को "बेकार लकडी" या "मृत पत्र" तक कम कर देता है, सामंजस्यपूर्ण निर्माण नहीं है। सामंजस्य स्थापित करना नष्ट करना नहीं है। ***ऐसे सभी मामलों में एक परिचित दृष्टिकोण यह पता लगाना है कि दो स्पष्ट रूप से परस्पर विरोधी प्रावधानों में से कौन सा अधिक सामान्य है और कौन सा अधिक विशिष्ट है और अधिक विशिष्ट को बाहर करने के लिए अधिक सामान्य का अर्थ लगाना है। सामान्य या विशेष प्रावधानों की सापेक्ष प्रकृति के बारे में प्रश्न का निर्धारण आम तौर पर या विशेष रूप से विशेष स्थितियों में उनके अनुप्रयोग के क्षेत्र और सीमा के संदर्भ में किया जाना चाहिए।"***

[जोर दिया गया]

171. वास्तव में विधायिका की मंशा से समझौता हो जाएगा यदि बैंकों को अपनी प्रतिभूति का एहसास करने की अनुमति नहीं दी जाती है जो उन्होंने वैधानिक योजना का पालन करते हुए पंजीकृत की थी। इस संदर्भ में क्रेज़ ऑन लेजिस्लेशन, 9 वां संस्करण, पृष्ठ 670-671 पर निम्नानुसार दिया गया है:

> *"नियम के अनुसार जहां संभव हो, विधायिका के इरादे को व्यर्थ नहीं माना जाना चाहिए या हवा में काम करने के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए। परिणाम यह है कि यदि किसी प्रावधान के दो निर्माण संभव हैं,*

और एक स्पष्ट रूप से विधायी उद्देश्य को आगे बढ़ाएगा और दूसरा स्पष्ट रूप से बहुत कम या कुछ भी नहीं हासिल करेगा, तो पहले वाले को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।"

172. इसके बाद सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों को विधायी इरादे के अनुसार समझा जाना चाहिए।

173. इरादे को निर्धारित करने के लिए, रिष्टि नियम को लागू करना सहायक होगा। इस नियम की एक संक्षिप्त व्याख्या बेनिओन ऑन स्टैच्युटरी इंटरप्रिटेशन, 7वाँ संस्करण, पृष्ठ 329-331 में पाई जाती है।

सामान्य

धारा 10.1: यह अनुमान कि न्यायायलय "रिष्टि" के लिए प्रदान किए गए उपाय को लागू करेगा

10.1 *संसद एक विशेष रिष्टि को दूर करने के लिए एक अधिनियम बनाने का इरादा रखती है। इसलिए यह माना जाता है कि संसद का इरादा है कि न्यायालय, अधिनियम का अर्थ लगाते हुए, उसके द्वारा प्रदान किए गए उपाय को इस तरह से लागू करने का प्रयास करे ताकि उस रिष्टि को दबाया जा सके।*

टिप्पणी

किसी अधिनियम को पारित करने का कारण लगभग हमेशा मौजूदा विधि को बदलना होता है ताकि उसमें किसी कथित दोष को दूर किया जा सके। वह दोष वह रिष्टि है जिसके लिए अधिनियम निर्देशित किया गया है। यह अध्याय रिष्टि और उसके उपचार से संबंधित है।

...

रिष्टि

धारा 10.2: "रिष्टि" का अर्थ

10.2

(1) संसद जिस रिष्टि को दूर करने का इरादा रखती है, वह या तो एक सामाजिक रिष्टि हो सकती है जो विधिक शरारत के साथ जुड़ी हुई है, या विशुद्ध रूप से विधिक शरारत हो सकती है।

(2) एक सामाजिक रिष्टि एक तथ्यात्मक स्थिति है, जो वर्तमान या जल्द ही अपेक्षित है, जिसे संसद सुधारना चाहती है। यह स्पष्ट रूप से कुछ गलत (जैसे कि एक विशेष प्रकार के असामाजिक व्यवहार का प्रकोप) से लेकर पहले से ही तटस्थ या यहां तक कि लाभकारी स्थिति में सुधार की संभावना तक हो सकता है।

(3) विधिक रिष्टि एक ऐसी स्थिति है जो विधि में एक दोष का गठन करती है, या संसद द्वारा इस तरह के दोष का गठन करने के रूप में माना जाता है। दोष में किसी भी वैधानिक अधिनियम के लिए पूरी तरह से संभव, एक संबंधित सामाजिक रिष्टि के लिए एक उपाय प्रदान करने में विफलता शामिल हो सकती है, या इसमें एक संबंधित सामाजिक रिष्टि के बिना अधिनियम में विशुद्ध रूप से अधिनियमी दोष शामिल हो सकता है।

टिप्पणी

संसद को बिना किसी कारण के कुछ नहीं करने के लिए लिया जाता है। इसलिए प्रत्येक अधिनियम के पारित होने और उसके भीतर प्रत्येक अधिनियम के लिए एक कारण है।

लगभग सभी मामलों में, एक अधिनियम पारित करने का कारण मौजूदा विधि को बदलना है। इसलिए किसी अधिनियम के पारित होने का कारण मौजूदा विधि में कुछ कथित दोष होना चाहिए। यदि मौजूदा विधि को दोषपूर्ण नहीं माना जाता, तो संसद को इसकी आवश्यकता

नहीं होती या वह इसे बदलना नहीं चाहती। वह दोष वह 'रिष्टि' है जिसके लिए अधिनियम निर्देशित किया गया है।"

174. भारतीय संदर्भ में, उक्त नियम को ***बंगाल इम्युनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य*** के मामले के बाद से अपनाया गया है। सुधार की मांग की गई रिष्टि को सरफेसी अधिनियम, 2002 के उद्देश्यों और कारणों के बयान द्वारा पर्याप्त रूप से दर्ज किया गया है। इसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"वाणिज्यिक लेन-देन से संबंधित हमारे मौजूदा विधिक ढांचे ने बदलती वाणिज्यिक प्रथाओं और वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के साथ तालमेल नहीं रखा है। इसके परिणामस्वरूप व्यतिक्रम करने वाले ऋणों की वसूली की गति धीमी हो गई है और बैंकों और वित्तीय संस्थानों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों का स्तर बढ़ रहा है।...
इन समितियों ने अन्य बातों ***के साथ-साथ प्रतिभूतिकरण के लिए एक नई विधि बनाने और बैंकों और वित्तीय संस्थानों को प्रतिभूतियों का कब्जा लेने और न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना उन्हें बेचने के लिए सशक्त बनाने का सुझाव दिया है"।***

[जोर दिया गया]

175. इस प्रकार जिस गड़बड़ी को दूर करने की मांग की गई वह एक वैधानिक तंत्र की कमी थी जिसने बैंकों को न्यायालयों के न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ अपने सुरक्षा हितों का एहसास करने की अनुमति दी। इस प्रकार सरफेसी अधिनियम, 2002 को एक वैधानिक ढांचा प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था जो बैंक के सुरक्षित ऋण की तेजी से और प्राथमिकता से वसूली की अनुमति देता है। इस प्रकार सरफेसी

अधिनियम, 2002 के तहत बैंक द्वारा अपनी प्रतिभूति की प्राप्ति को प्राथमिकता देने का स्पष्ट इरादा है।

176. इस विधायी इरादे को ध्यान में रखते हुए, धारा 37 और धारा 35 के प्रावधानों का अर्थ लगाने की आवश्यकता है।

177. सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 37 का पाठ, जब सतही रूप से पढ़ा जाता है, तो विभिन्न अभिव्यक्तियों को दिए गए महत्व के आधार पर निर्माण की अनुमति दे सकता है। स्पष्टता के लिए, धारा 37 को फिर से निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:

> *"37. **अन्य विधियों का प्रयोग वर्जित नहीं है।**— इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध कंपनी अधिनियम, 1956 (1/1956), प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (42/1956), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (15/1992), बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (51/1993) या तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विधि।"*
>
> *[जोर दिया गया]*

178. इस प्रकार प्रावधान के दो पहलू हैं। पहला यह है कि अधिनियम "इसके अतिरिक्त होगा" दूसरा यह है कि यह "अल्पीकरण में" नहीं होना चाहिए। वास्तव में वे "और" संयोजन से जुड़े हुए हैं, और इन्हें एक साथ समझा जाना चाहिए। लेकिन सतही तौर पर पढ़ने से दोनों निर्माणों को उचित माना जा सकता है-जो "गैर-अल्पीकरण" जनादेश का समर्थन करते हैं या जो "समर्थन के अतिरिक्त" का समर्थन करते हैं।

179. यह इस स्तर पर है कि प्रावधान का शीर्षक इस न्यायालय की सहायता के लिए आता है। इसमें यह दिया गया है कि "अन्य विधियों का अनुप्रयोग वर्जित नहीं है"। इस प्रकार एक सकारात्मक जनादेश इस शीर्षक में निहित है। इसके विपरीत, एक नकारात्मक जनादेश की अनुपस्थिति में है। इस प्रकार, प्रावधान सरफेसी अधिनियम, 2002 को अपने वैधानिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए परिगणित विधियों की सहायता लेने की अनुमति देता है। यह प्रावधान किसी भी तरह से सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रभाव को कम नहीं करता है।

180. इस संदर्भ में, वैधानिक व्याख्या पर बेनियन, 7 वां संस्करण, पृष्ठ 444 निम्नानुसार है:

> ***धारा 16.7: शीर्षक***
>
> ***16.7 <u>शीर्षक एक अधिनियम का हिस्सा है। अधिनियम के किसी भी प्रावधान का अर्थ लगाने में इस पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि इस तथ्य को ध्यान में रखा जाए कि इसका कार्य केवल उस सामग्री के लिए एक संक्षिप्त मार्गदर्शक के रूप में काम करना है जिसे यह नियंत्रित करता है और यह पूरी तरह से सटीक नहीं हो सकता है।</u>***
>
> ***टिप्पणी***
>
> ***<u>शीर्षक किसी भी अन्य घटक की तरह ही किसी अधिनियम का हिस्सा होते हैं और कुछ पुराने मामलों में इसके विपरीत निर्देश के बावजूद, इसके किसी भी प्रावधान का अर्थ लगाने में विचार किया जा सकता है।</u>***
> *(निम्नानुसार चर्चा की गई)*
>
> *जैसा कि अध्याय 2 में चर्चा की गई है, अधिनियमों में विभिन्न प्रकार के शीर्षकों का उपयोग किया गया है। प्रत्येक खंड, अनुसूची, अध्याय और*

*भाग का अपना शीर्षक होता है और इटैलिक शीर्षकों को अक्सर अनुभागों के एक समूह या अनुसूची के एक या अधिक अनुच्छेदों के उपरोक्त रखा जाता है। 2001 से पहले, धाराओं में उपरोक्त रखे गए शीर्षक के बजाय किनारे में साइडनोट या सीमांत नोट रखे गए थे, लेकिन 'शीर्षक' शब्द का उपयोग उन्हें शामिल करने के लिए भी किया जाता है।**

व्याख्या में शीर्षकों के उपयोग के लिए सही दृष्टिकोण का सारांश आर द्वारा हाउस ऑफ लॉर्ड्स बनाम मोंटीला में दिया गया था:

> *"तब सवाल यह है कि क्या शीर्षकों और पार्श्व टिप्पणियों को, हालांकि अपरिवर्तनीय है, संसद के एक अधिनियम में एक प्रावधान का अर्थ लगाने में विचार किया जा सकता है। बेशक, इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इन घटकों को विधेयक में बहस के लिए नहीं बल्कि संदर्भ में आसानी के लिए शामिल किया गया था। यह इंगित करता है कि अधिनियम के उन हिस्सों की तुलना में उन्हें कम महत्व दिया जा सकता है जो संसद में विचार और बहस के लिए खुले हैं। लेकिन विधि के शासन द्वारा उनकी पूरी तरह से अवहेलना करना एक और बात है। **कोई इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता है कि विधायिका के माध्यम से पारित होने के दौरान विधेयक के शीर्ष पर शीर्षक और साइडनोट शामिल हैं। वे मार्गदर्शन के लिए हैं।** वे विधेयक के उन हिस्सों की पुन: जांच के लिए संदर्भ प्रदान करते हैं जो बहस के लिए खुले हैं। बेशक, इस तथ्य के अधीन कि वे अपरिवर्तनीय हैं, उन्हें विधि की किताब तक पहुंचने पर अधिनियमन के हिस्से के रूप में विचार करने के लिए खुला होना चाहिए।"*

जहां एक शीर्षक उस सामग्री से भिन्न होता है जिसका वह वर्णन करता है, यह न्यायालय को जांच में डालता है, लेकिन यह सही होने की संभावना नहीं है कि शीर्षक के कारण विशुद्ध रूप से थेरेस के सादे अर्थ को अभिभावी किया जाए।

[जोर दिया गया]

181. इसी तरह, जी.पी. सिंह के प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, 15 वें संस्करण, पृष्ठ 129-130 में निम्नानुसार दिया गया है:

> *"अब यह विचार तय हो गया है कि विधायिका के अधिनियम के निर्माण में अनुभागों या वर्गों के समूह के उपसर्ग वाले शीर्षकों को संदर्भित किया जा सकता है। **लेकिन इस सवाल पर परस्पर विरोधी राय व्यक्त की गई है कि शीर्षकों के साथ क्या वजन जोड़ा जाना चाहिए। एक दृष्टिकोण के अनुसार, एक शीर्षक को "इसके तहत आने वाले धाराओं की व्याख्या की कुंजी के रूप में माना जाना चाहिए, जब तक कि शब्दांकन ऐसी व्याख्या के साथ असंगत न हो" और इसलिए शीर्षकों को "उनके बाद के प्रावधानों की प्रस्तावना" के रूप में माना जा सकता है। लेकिन दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार**, "शीर्षक " का सहारा केवल तभी लिया जा सकता है जब अधिनियमित शब्द अस्पष्ट हों। तो लॉर्ड गोडार्ड मु.न्या. ने खुद को इस प्रकार व्यक्त किया:*
>
> > *हालांकि, न्यायालय को संसद के एक अधिनियम में शीर्षकों को देखने का अधिकार है ताकि उनके पास अस्पष्ट शब्दों के रूप में किसी भी संदेह को हल किया जा सके, विधि स्पष्ट है कि उन शीर्षकों का उपयोग धारा में स्पष्ट शब्दों को एक अलग प्रभाव देने के लिए नहीं किया जा सकता है जहां शब्दों के सामान्य अर्थ के रूप में कोई संदेह नहीं हो सकता है।*
>
> *इसी तरह, न्या. पतंजलि शास्त्री ने कहा था:*
>
> > *न ही किसी अध्याय के शीर्षक का उपयोग किसी अधिनियम की साधारण शर्तों को प्रतिबंधित करने के लिए वैध रूप से किया जा सकता है।*
>
> *उच्चतम न्यायालय ने स्वयं को इस प्रकार व्यक्त किया है:*

*"यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अनुभागों या प्रविष्टियों (शुल्क अनुसूची की) से पहले जोड़े गए शीर्षक प्रावधान के सादे शब्दों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं; उन्हें प्रावधान का अर्थ लगाने के उद्देश्य से भी संदर्भित नहीं किया जा सकता है जब प्रावधान में उपयोग किए गए शब्द स्पष्ट और असंदिग्धार्थ हों; और न ही उनका उपयोग प्रावधान में शब्दों के स्पष्ट अर्थ को कम करने के लिए किया जा सकता है। **केवल अस्पष्टता या संदेह के मामले में शीर्षक या उप-शीर्षक को प्रावधान को समझने में सहायता के रूप में संदर्भित किया जा सकता है, लेकिन ऐसे मामले में भी इसका उपयोग प्रावधान में उपयोग किए गए स्पष्ट शब्दों के व्यापक अनुप्रयोग को कम करने के लिए नहीं किया जा सकता है।"***

अनुभागों या शीर्षकों के समूह से पहले शीर्षकों के उपयोग से संबंधित परस्पर विरोधी राय का उल्लेख करने के बाद, न्यायमूर्ति लाहोटी ने खुद को इस प्रकार व्यक्त किया:

किसी धारा का शीर्षक या अनुभाग निर्दिष्ट करने की अनुमति है, जो विधियों के निर्माण में एक सीमित भूमिका निभाती है। इन्हें विषय-वस्तु की प्रकृति के बहुत व्यापक और सामान्य संकेतकों के रूप में लिया जा सकता है। अनुभाग या शीर्षक को एक संक्षिप्त नाम के रूप में भी लिया जा सकता है जो नीचे दिए गए अधिनियम द्वारा निपटाए गए विषय की विशेषताओं को सामूहिक रूप से इंगित करने के लिए सौंपा गया है; हालाँकि नाम हमेशा अपनी सीमाओं के साथ संक्षिप्त होगा। प्रावधान की सरल भाषा और अनुभाग या शीर्षक के अर्थ के बीच संघर्ष के मामले में, शीर्षक या शीर्षक उस अर्थ को नियंत्रित नहीं करेगा जो प्रावधान की भाषा से स्पष्ट है।"

[जोर दिया गया]

182. इस प्रकार शीर्षक की सहायता उस संदेह को स्पष्ट करने के लिए ली जा सकती है जो एक दुभाषिया को किसी विशेष प्रावधान का अर्थ लगाते समय हो सकता है। वर्तमान मामले में, यह न्यायालय केवल स्वतंत्र रूप से निकाले गए निष्कर्ष को और अधिक प्रमाणित करने के लिए शीर्षक का उल्लेख कर रही है। इस प्रकार शीर्षक को न्यायालय द्वारा पहले से ही किए गए निष्कर्ष के समर्थन के रूप में माना जा रहा है।

183. उपरोक्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत कार्यवाही को एक उत्कीर्णन के रूप में माना जाना चाहिए, और इसलिए सेबी अधिनियम, 1992 के तहत आदेशों से अप्रभावित रहता है।

184. यह न्यायालय अब सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 26ङ, आर.डी.बी. अधिनियम, 1993 की धारा 31ख और सेबी अधिनियम, 1992 क (3) की व्याख्या से संबंधित विवाद के पहलू पर विचार करेगा।

185. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 28क (3) पर निर्भरता गलत है। वर्तमान विवाद का संबंध वसूली अधिकारी द्वारा राशि की वसूली से नहीं है। प्रावधान को सतही तौर पर पढ़ने से, वर्तमान विवाद में इसकी अप्रयोज्यता स्पष्ट हो जाएगी। धारा 28क (3) निम्नानुसार है:

> *"(3) तत्काल लागू किसी अन्य विधि में कुछ भी निहित होने के बावजूद, धारा 11बी के तहत बोर्ड द्वारा जारी किसी भी निर्देश का पालन न करने के अनुसार, उप-धारा(1) के तहत एक वसूली अधिकारी द्वारा राशि की वसूली को ऐसे व्यक्ति के खिलाफ किसी अन्य दावे पर प्राथमिकता होगी।"*

186. इसके अलावा, धारा 28क (1) इस प्रकार है:

"28क. धनराशि की वसूली।— (1) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहता है या धन की वापसी के लिए बोर्ड के किसी भी निर्देश का पालन करने में विफल रहता है या धारा 11 ख के तहत जारी किए गए आदेश का पालन करने में विफल रहता है या बोर्ड को देय किसी भी शुल्क का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वसूली अधिकारी अपने हस्ताक्षर के तहत निर्दिष्ट प्रपत्र में एक विवरण तैयार कर सकता है जिसमें व्यक्ति से देय राशि (ऐसा विवरण इस अध्याय में इसके बाद प्रमाण पत्र के रूप में संदर्भित है) निर्दिष्ट की गई है और ऐसे व्यक्ति से निम्नलिखित में से एक या अधिक तरीकों से प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट राशि की वसूली करने के लिए आगे बढ़ेगा, अर्थात्:—

(क) व्यक्ति की चल संपत्ति की कुर्की और बिक्री;

(ख) व्यक्ति के बैंक खातों की कुर्की;

(ग) व्यक्ति की अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री;

(घ) व्यक्ति की गिरफ्तारी और जेल में उसकी नजरबंदी;

(ङ) व्यक्ति की चल और अचल संपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक रिसीवर की नियुक्ति, और इस उद्देश्य के लिए, धारा 220 से लेकर 227,228क, 229,232, आयकर अधिनियम, 1961 (43/1961) की दूसरी और तीसरी अनुसूची और आयकर (प्रमाणपत्र कार्यवाही) नियम, 1962 के प्रावधान, जो समय-समय पर लागू होते हैं, आवश्यक संशोधनों के साथ लागू होते हैं, जैसे कि उक्त प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम इस अधिनियम के प्रावधान थे और आयकर अधिनियम, 1961 के तहत आयकर के बजाय इस अधिनियम के तहत देय राशि को संदर्भित करते हैं।

..."

187. यही कारण है कि ***मैसर्स मिडफाइल्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड*** *(पूर्वोक्त)*, का वर्तमान विवाद में कोई अनुप्रयोग नहीं है। ***मैसर्स मिडफायल्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड*** *(पूर्वोक्त)* मामले में तेलंगाना उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर निर्णय सुनाया कि क्या सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 28क के तहत वसूली की कार्यवाही को सरफेसी अधिनियम 2002 पर प्राथमिकता दी जाएगी। महत्वपूर्ण रूप से, ***मैसर्स मिडफाइल्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड*** *(पूर्वोक्त)* में, संबंधित बैंकों के खिलाफ एक वसूली आदेश पारित किया गया था। वर्तमान मामले में, ऐसा कोई आदेश नहीं है। इसलिए उक्त निर्णय प्रतिष्ठित है।

188. ***बिक्री कर आयुक्त, इंदौर*** (पूर्वोक्त) में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2002 और याचिकाकर्ता बैंक के अपनी परिसंपत्ति की वसूली के अधिकारों के बीच संघर्ष पर निर्णय सुनाया। न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा, जिसके साथ यह न्यायालय सहमत है कि आर.डी.बी. अधिनियम की धारा 31 को प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन और ऋण और विविध प्रावधानों की वसूली अधिनियम और संशोधन अधिनियम, 2016 (इसके पश्चात **'कहा गया संशोधन'**) द्वारा से शामिल किए जाने के आलोक में, एक सुरक्षित ऋण और अन्य सभी ऋणों और राजस्व जैसे सरकारी बकाया के बीच प्रधानता के बारे में संदेह, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरणों को देय करों, उपकरों और दरों का निपटान कर दिया गया है। न्यायालय तब यह निष्कर्ष निकालती है कि सुरक्षित ऋण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

189. इसके अलावा, ***सहायक आयुक्त (सीटी), अन्ना सलाई-III असेसमेंट सर्कल*** (पूर्वोक्त) में मद्रास उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश संजय किशन कौल

(जैसा कि तब उनका लॉर्डशिप था) द्वारा लिखित तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ का निर्णय भी उसी निष्कर्ष पर पहुंचा था जो ***बिक्री कर आयुक्त, इंदौर*** (पूर्वोक्त) के मामले में पहुंचा था।

190. ***कालूपुर कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड*** (पूर्वोक्त) में गुजरात उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा ***द इंडियन ओवरसीज बैंक*** (पूर्वोक्त) और ***बिक्री कर आयुक्त*** (पूर्वोक्त) के विपरीत, विशेष रूप से प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 द्वारा दिए गए मुद्दे से संबंधित है। प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया था कि जहां तक याचिकाकर्ता बैंक ने आर.डी.बी. अधिनियम, 1993 के तहत कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है, उक्त अधिनियम की धारा 31 ख का कोई संचालन नहीं होगा।

191. ***कालुपुर वाणिज्यिक सहकारी बैंक लिमिटेड*** *(पूर्वोक्त)* में, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि तत्कालीन याचिकाकर्ता बैंक द्वारा सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत कार्रवाई किए जाने के बावजूद आर.डी.बी. अधिनियम, 1993 की धारा 31ख अभी भी लागू हो सकती है। उक्त निष्कर्ष पर इस आधार पर पहुँचा गया था-क्योंकि आरडीबी अधिनियम, 1993 की धारा 31 ख एक मूल प्रावधान है और आरडीबी अधिनियम, 1993 के अनुसार "सुरक्षित लेनदार" की परिभाषा धारा 2 (ठक) वही है जो सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत प्रदान की गई है; दूसरा, क्योंकि उक्त संशोधन की शुरूआत का कारण सुरक्षित लेनदारों के अधिकारों को प्रधानता प्रदान करना था जैसा कि सरफेसी अधिनियम, 2002 और आरडीबी अधिनियम, 1993 के उद्देश्यों और कारणों के बयान से देखा जा सकता है; तीसरा, क्योंकि सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 37 के आधार

पर आर.डी.बी. अधिनियम, 1993 और सरफेसी अधिनियम, 2002 को एक दूसरे के अल्पीकरण के अलावा पढ़ा जाना चाहिए।

192. आर.डी.बी. अधिनियम, 1993 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण का महत्वपूर्ण भाग इस प्रकार है:

> *"बैंक और वित्तीय संस्थान को शोध्य ऋण अधिनियम, 1993*
> *उद्देश्यों और कारणों का विवरण*
>
> *वर्तमान में बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ऋणों की वसूली और उनसे ली गई प्रतिभूतियों को लागू करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली के लिए मौजूदा प्रक्रिया ने उनके धनराशि के एक बड़े हिस्से को अनुत्पादक परिसंपत्तियों में अवरुद्ध कर दिया है, जिसका मूल्य समय के साथ बिगड़ता जाता है..."।*

193. आर.डी.बी. अधिनियम, 1993 की धारा 31ख निम्नानुसार है:

> *"31ख. सुरक्षित लेनदारों को प्राथमिकता-कुछ समय से लागू किसी अन्य विधि में कुछ भी निहित होने के बावजूद, सुरक्षित लेनदारों के उन परिसंपत्तियों की बिक्री द्वारा देय और देय सुरक्षित ऋणों को प्राप्त करने के अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन पर प्रतिभूति ब्याज बनाया जाता है और केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण को देय राजस्व, कर, उपकर और दरों सहित अन्य सभी ऋणों और सरकारी बकाया पर प्राथमिकता से भुगतान किया जाएगा।*
>
> *स्पष्टीकरण।- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (31/2016) के प्रारंभ होने पर या उसके बाद, ऐसे मामलों में जहां उधारकर्ता की सुरक्षित परिसंपत्तियों के संबंध में दिवालियापन की कार्यवाही लंबित है,*

ऋण के भुगतान में सुरक्षित लेनदारों को प्राथमिकता उस संहिता के प्रावधानों के अधीन होगी।"

194. सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 26ङ निम्नानुसार है:

"26ङ. सुरक्षित लेनदारों को प्राथमिकता-कुछ समय के लिए किसी अन्य विधि में कुछ भी निहित होने के बावजूद, प्रतिभूति ब्याज के पंजीकरण के बाद, किसी भी सुरक्षित लेनदार को देय ऋणों का भुगतान अन्य सभी ऋणों और सभी राजस्व, करों, उपकरों और केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण को देय अन्य दरों पर प्राथमिकता से किया जाएगा।

स्पष्टीकरण।- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (31/2016) के प्रारंभ होने पर या उसके बाद, ऐसे मामलों में जहां ऋणकर्ता, ऋण के भुगतान में सुरक्षित लेनदारों को प्राथमिकता उस संहिता के प्रावधानों के अधीन होगी।"

195. सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 32 निम्नलिखित है:

"32. अन्य विधियों का प्रयोग वर्जित नहीं है।—इस अधिनियम के प्रावधान उस समय लागू किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे और उनका अल्पीकरण नहीं करेंगे।"

196. यह न्यायालय ***बिक्री कर आयुक्त, इंदौर*** (पूर्वोक्त), और ***द इंडियन ओवरसीज बैंक*** (पूर्वोक्त) के निर्णयों से सहमत है, हालांकि, उनके अनुपात को सही परिप्रेक्ष्य में समझा जाना चाहिए। उक्त दो निर्णय कर परिनियमों के साथ टकराव से संबंधित हैं, जिसका अर्थ है कि इन परिनियमों का उल्लेख सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 37 या आर.डी.बी. अधिनियम, 1993 की धारा 34 (2) में नहीं मिलता है।

197. हालाँकि, वर्तमान मामले में, सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 37 में सेबी अधिनियम, 1992 का स्पष्ट उल्लेख है। सरफेसी अधिनियम, 2002 या आर.डी.बी. अधिनियम, 1993 के बीच संघर्ष की व्याख्या करने का तरीका और गैर-अल्पीकरण प्रावधान में उल्लिखित कराधान विधि का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए, वर्तमान मामले से मौलिक रूप से अलग होगा। हालांकि, ***कालुपुर वाणिज्यिक सहकारी बैंक लिमिटेड*** *(पूर्वोक्त)* में विश्लेषण आर.डी.बी. अधिनियम, 1993 की धारा 31 ख पर सरफेसी अधिनियम के तहत बैंक द्वारा शुरू की जा रही कार्रवाइयों की परवाह किए बिना लागू किया जाना प्रासंगिक है।

198. यह न्यायालय गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सहमत है कि सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत शुरू की जा रही कार्यवाही या कार्रवाई की परवाह किए बिना, सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 37 के आधार पर आर.डी.बी. अधिनियम, 1993 का सहारा लिया जा सकता है।

199. इसके बाद विचार सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 26ङ से संबंधित है। धारा 26ङ प्रदान करता है कि किसी भी सुरक्षित लेनदार के कारण ऋण का भुगतान अन्य सभी ऋणों और केंद्र सरकार या स्थानीय प्राधिकरण को देय सभी राजस्व, करों, उपकरों और अन्य दरों पर प्राथमिकता में किया जाएगा।

200. प्रतिभूति हित प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 2016 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण का महत्वपूर्ण भाग निम्नानुसार है:

*"बैंकों और वित्तीय संस्थानों के ऋणों की शीघ्र वसूली के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 और वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 अधिनियमित किए गए थे। **वर्तमान में, ऋण वसूली न्यायाधिकरणों में लगभग सत्तर हजार मामले लंबित हैं। हालांकि बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम के कारण ऋणों की वसूली में वसूली आवेदनों के निपटारे के लिए 180 दिनों की अवधि का प्रावधान है, लेकिन विभिन्न स्थगनों और लंबी सुनवाई के कारण मामले कई वर्षों से लंबित हैं। वसूली आवेदनों के शीघ्र निपटान की सुविधा के लिए, उक्त अधिनियमों में संशोधन आदेश और भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 में परिणामी संशोधन आदेश का निर्णय लिया गया है।***

2. वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में संशोधन बदलते ऋण परिदृश्य के अनुकूल तथा कारोबार करने में आसानी को बढ़ाने के लिए प्रस्तावित हैं जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, (i) सभी प्रतिभूत ऋणदाताओं द्वारा प्रतिभूति हित के सृजन, संशोधन और संतुष्टि का पंजीकरण और संपत्ति अधिकारों से संबंधित विभिन्न कानूनों के अंतर्गत पंजीकरण प्रणालियों के केन्द्रीय रजिस्ट्री में एकीकरण का प्रावधान ताकि संपत्ति अधिकारों पर प्रतिभूति हित का केन्द्रीय डाटाबेस सृजित किया जा सके; (ii) बदलते व्यावसायिक वातावरण में परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को विनियमित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को शक्तियां प्रदान करना; (iii) परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के पक्ष में बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण सौंपने पर स्टाम्प शुल्क से छूट; (iv) गैर-संस्थागत निवेशकों को प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश करने में सक्षम बनाना।"

[जोर दिया गया]

201. इसके अतिरिक्त, संशोधन अधिनियम द्वारा से सम्मिलित किए गए सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 26ङ से संबंधित धाराओं पर टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:

> *"धारा 17 सुरक्षित लेनदारों और अन्य लेनदारों द्वारा पंजीकरण से संबंधित मूल अधिनियम में एक नया अध्याय IVक सम्मिलित करने का प्रयास करता है, इसमें धारा 26ख, 26ग, 26घ और 26ङ शामिल हैं। धारा 26ख ऐसे लेनदार द्वारा उधारकर्ता को दी गई किसी भी वित्तीय सहायता के उचित पुनर्भुगतान को सुरक्षित करने के उद्देश्य से उधारकर्ता की किसी भी संपत्ति पर किसी भी प्रतिभूति ब्याज के निर्माण, संशोधन या संतुष्टि के लिए सुरक्षित लेनदार के अलावा सभी ऋणदाताओं को पंजीकरण के प्रावधान का विस्तार करने का प्रावधान करती है।*
>
> *इसमें आगे यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण का कोई प्राधिकरण या अधिकारी, जिसे कर या अन्य सरकारी बकाया की वसूली का कार्य सौंपा गया है और कर या सरकारी बकाया का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी किसी भी व्यक्ति की किसी भी संपत्ति की कुर्की के लिए कोई आदेश जारी करने के लिए, निर्धारिती के विवरण और कर या अन्य सरकारी बकाया के विवरण के साथ ऐसा कुर्की आदेश केंद्रीय पंजीकरण में ऐसी तारीख से दाखिल करेगा जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए। धारा 26ग यह प्रावधान करना चाहती है कि प्रतिभूति ब्याज का पंजीकरण केंद्रीय पंजीकरण के साथ लेनदेन के पंजीकरण या कुर्की आदेश दाखिल करने की तिथि और समय से प्रभावी होगा और धारा 26घ यह प्रदान करती है कि सुरक्षित लेनदार केवल तभी प्रतिभूतियों को लागू करने के अधिकार का प्रयोग करने का हकदार होगा जब वह केंद्रीय पंजीकरण के साथ पंजीकृत हो।*
>
> ***<u>धारा 26ङ केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण को देय अन्य सभी ऋणों, राजस्व, करों, उपकर और दरों पर</u>***

<u>सुरक्षित लेनदारों को देय ऋणों की प्राथमिकता प्रदान करने का प्रयास करती है।"'</u>

[जोर दिया गया]

202. संशोधन अधिनियम के उद्देश्यों और उद्देश्यों के विवरण से यह स्पष्ट होता है कि सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधान प्राथमिकता का निर्माण करते हैं। यह है कि सुरक्षित लेनदार के ऋणों को सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के किसी भी बकाया पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

203. इसलिए, धारा 26ङ को शामिल करना एक व्यापक उद्देश्य के लिए था, यह हमारे बैंकों को राज्य तंत्र के बल से बचाने के लिए था, जिसने अब तक बैंकों के बकाया चुकाने के अधिकारों में हस्तक्षेप किया था। जैसा कि माननीय विधि मंत्री ने उद्देश्यों और कारणों के बयान में उल्लेख किया है, 2016 का संशोधन बदलते ऋण परिदृश्य के अनुमुकदमा और व्यवसाय करने में आसानी बढ़ाने के लिए प्रस्तावित किया गया था।

204. सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 26ङ वर्तमान तथ्यात्मक परिदृश्य में पूरी तरह से लागू नहीं हो सकती है, हालांकि यह बैंकों को दिए गए सुरक्षित ऋणों को प्राथमिकता देने के विधायिका के निरंतर इरादे को प्रकट करती है।

205. उपरोक्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 35 और धारा 37 की व्याख्या से पता चलेगा कि सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत कार्यवाही को सेबी अधिनियम, 1992 के तहत पारित आदेशों के लिए एक उत्कीर्णन के रूप में माना जाना चाहिए और इससे अप्रभावित रहना चाहिए।

206. वर्तमान मामले के तथ्यों पर, उक्त आदेश याचिकाकर्ता बैंक को अपनी बंधकित संपत्ति की नीलामी के लिए सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत आगे बढ़ने से नहीं रोकते हैं।

207. न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों का सारांश इस प्रकार है:

क. सेबी के पास बैंकों को निर्देशित करने के लिए आवश्यक विधिक शक्ति निहित पाई गई है।

ख. सेबी के पूर्णकालिक सदस्य द्वारा पारित दिनांक 29.05.2018 और 14.12.2018 के आदेश याचिकाकर्ता बैंक पर लागू होते हैं, हालांकि वे याचिकाकर्ता बैंक को विला सं. (ग) मैसर्स टीपीवी-जी-जीवी-07, द पाम स्प्रिंग्स, वजीराबाद गाँव, सेक्टर 54, गुडगांव 122002 के अंतर्गत सरफेसी अधिनियम, 2002 के उपबंधों के अंतर्गत मैसर्स टीपीवी-जी-जीवी-07 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।

ग. 29.01.2021 और 18.03.2021 दिनांकित आक्षेपित ई-मेल गलत और पूरी तरह से अधिकारिता के बिना पाए जाते हैं।

घ. सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत कार्यवाही को सेबी अधिनियम, 1992 के तहत पारित आदेशों और निर्देशों के लिए एक उत्कीर्णन के रूप में माना जाना चाहिए, और इससे अप्रभावित रहना चाहिए।

208. रिट याचिका का निपटान उपरोक्त शर्तों में किया जाता है।

(न्या. पुरुशेंद्र कुमार कौरव)

21 जुलाई, 2023

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*